



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

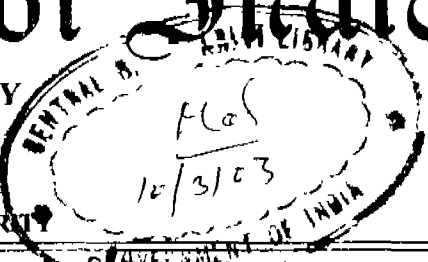
असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 251]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 24, 2002/अश्विन 2, 1924

No. 251]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 24, 2002/ASVINA 2, 1924

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्कों का महानिदेशालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2002

अंतिम जांच परिणाम

विषय : कोरिया गणराज्य और जर्मनी से एक्रायलोनाइट्रिल बुटाडिन रबड़ एन बी आर के आयात पर पाटनरोधी शुल्क के निर्णायक समीक्षा के संबंध में पाटनरोधी जांच।

सं. 50/1/2001-डीजीएडी.— 1995 में यथासंशोधित, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क (5) तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए:

क. प्रक्रिया

जांच के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा जाएगा) ने सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमाशुल्क (टैरिफ पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 की धारा 9 क (5) के नियमों के अनुसार, कोरिया गणराज्य और जर्मनी जिन्हें इसके बाद संबद्ध देश कहा जाएगा से एक्रोलोनाइट्रिल बुटाडिन रबड़ (एनबीआर) (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा जाएगा) के आयात पर लगातार पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता के पुनरावलोकन के उद्देश्य से निर्णायक समीक्षा का प्रारम्भ किया। प्राधिकारी द्वारा दिनांक 30.12.1996 के दिए गए मूल प्रारम्भिक परिणामों में संबद्ध वस्तुओं का निर्धारण किया गया तथा 17.7.1997 के अंतिम जांच परिणाम के द्वारा उनकी पुष्टि की गई। पिछले मध्यावधि समीक्षा के बाद दिनांक 7.09.2001 की अधिसूचना सं० 91/2001 सीमा शुल्क द्वारा पाटनरोधी शुल्क अधिसूचित किए गए थे तथा दिनांक 7.06.2002 की सीमाशुल्क अधिनियम सं० 61/2002 के तहत पाटनरोधी शुल्क आज भी लागू हैं।

(ii) प्राधिकारी ने दिनांक 1.10.2001 को भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित एक सार्वजनिक नोटिस को जारी किया, जिसके अनुसार 1995 में संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 40 की अनुसूची 1 के अंतर्गत वर्गीकृत, कोरिया गणराज्य और जर्मनी मूल के अथवा वहां से निर्यातित, संबद्ध वस्तुओं के आयात संबंधी ऊपर उल्लिखित जांच के बारे में पाटनरोधी जांच प्रारम्भ की गयी।

(iii) प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों और उद्योग प्रयोक्ता संघों को जिनके ब्यौरे पूर्व में की गई जांचों में उपलब्ध हैं अग्रेषित की और नियम 6(2) के अनुसार अपने विचार लिखित रूप में देने के लिए उन्हें अवसर प्रदान किया ।

(iv) प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति, भारत में संबद्ध वस्तुओं के सभी ज्ञात आयातकों को जिनकी ब्यौरे पूर्व में की गयी जांचों में उपलब्ध हैं और उन्हें नियम 6 (2) के अनुसार पत्र जारी किए जाने के 40 दिनों के अंदर अपने विचारों से अवगतकराने की सलाह दी ।

(v) एक्साइज और कस्टम केन्द्रीय बोर्ड (सी बी ई सी) से, जांच की अवधि सहित पिछले तीनवर्षों में भारत में निर्मित संबद्ध वस्तुओं के आयातों की विस्तृत जानकारी देने का आग्रह किया गया ।

(vi) प्राधिकारी ने पूर्वोक्त नियम 6 (3) के अनुसार प्रारम्भिक अधिसूचना की एक प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों और नई दिल्ली में स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को दी ।

(vii) प्राधिकारी ने नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को एक प्रश्नावली भेजी:

- (i) मै0 कोरिया कुम्हों पेट्रोकेमिकल्स कम्पनी लि0 (केकेपीसी), कोरिया गणराज्य
- (ii) मै0 हुंडई पेट्रोकेमिकल्स, कम्पनी लि0 कोरिया गणराज्य
- (iii) मै0 बेयर एजी, जर्मनी

प्रश्नावली के लिए उत्तर/सूचना निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा दी गई थी

- (i) मै0 कोरिया कुम्हों पेट्रोकेमिकल्स कम्पनी लि0 (केकेपीसी), कोरिया गणराज्य
- (ii) मै0 हुंडई पेट्रोकेमिकल्स, कम्पनी लि0 कोरिया गणराज्य
- (iii) मै0 बेयर एजी, जर्मनी

मै. केकेपीसी ने प्रश्नावली का सिलसिलेवार उत्तर दिया, मै0 हुंडई पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने सूचना प्रदान करने में कोई रुचि नहीं दिखाई, और मै0 बेयर एजी ने प्रश्नावली के अनुसार नहीं बल्कि उनके द्वारा किए जाने वाले निर्यातों और सामान्य रूप से उत्पादन में आने वाली उनकी लागत के संबंध में जानकारी दी ।

(viii) नई दिल्ली में स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को नियम 6 (2) के अनुसार जांच प्रारम्भ होने की सूचना दी गई और आग्रह किया गया कि वे उनके देशों के सभी संबद्ध निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समयसीमा के अंदर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें । ज्ञात निर्यातक को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति नियम 6(3) के अनुसार संबद्ध देशों के दूतावासों को भी भेजी गई ।

ix) संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातकों/उपयोक्ता संघों को एक प्रश्नावली भेजी गई जिसकी विस्तृत जानकारी नियम 6(4) के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा जरूरी सूचना के लिए उपलब्ध कराई गई:-

प्रश्नावली के बारे में निम्नलिखित आयातकों द्वारा उत्तर/सूचना दी गई थी ।

- i) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ रबर फुटवेयर इंडस्ट्रीज
- ii) स्मॉल स्केल रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया
- iii) ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया
- x) संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादक मै. अपार इंडस्ट्रीज लि. से क्षति संबंधी सूचना मांगी गई थी ।
- xi) मै. अपार इंडस्ट्रीज लि. के वालिया गुजरात में उनके परिसर की लागत संबंधी जांच भी की गयी ताकि सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जी ए ए पी) के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं को बनाने और उनकी बिक्री लागत और उच्चतम उत्पादन लागत को निकाला जा सके और क्षति संबंधी विभिन्न मापदंडों की जांच की जा सके ।

xii) मै. के के पी सी और मै. अपार इंडस्ट्रीज लि. से अतिरिक्त जानकारी मांगी गई ।

xiii) सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 7.12.2001 को मौखिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने का एक अवसर दिया गया । सभी पक्षकारों से आग्रह किया गया कि वे व्यक्त किए गए अपने विचार लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें । पक्षकारों को विरोधी पार्टियों द्वारा व्यक्त विचारों की प्रतियां एकत्र करने और खंडन यदि कोई हो देने की सलाह दी गई ।

(xiv) प्राधिकारी ने उसके द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपीनय अंश को उपलब्ध कराया और उसे नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण के लिए खुला रखा ।

(xv) पूर्वोक्त नियमों के नियम 16 के अनुसार इन जांच परिणामों के विचार किए गए आवश्यक तथ्य/आधार का दिनांक 13.9.2002 को ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को खुलासा किया गया । जिसके लिए मै. के के पी सी और मै. अपार इंडस्ट्रीज लि. द्वारा उत्तर दिए गए थे ।

(xvi) 23 अगस्त और 24 अगस्त 2002 को निर्यातक मै. के के पी सी सिओल का स्थान स्थापन सत्यापन किया ।

(xvii) \*\*\* यह चिन्ह इस अधिसूचना में एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय रूप से जानकारी उपलब्ध कराई गई है और इसलिए प्राधिकारी द्वारा नियमों के अंतर्गत इसे ऐसा ही माना गया है ।

(xviii) जांच की अवधि (पी ओ आई) 1.4.2000 से 31.3.2001 तक की है ।

#### ख. घरेलू उद्योग निर्यातकों आयातकों उपयोक्ता संघों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार तथा प्राधिकारी द्वारा जांच

विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर प्रकटन विवरण पत्र में विचार किया गया है । वे विचार जिन पर पूर्व में प्रकटन विवरण पत्र में विचार नहीं किया गया है तथा वे विचार जो अब

प्रकटन विवरण पत्र के प्रत्युत्तर में उठाए गए हैं उन पर नीचे दिए गए पैरा में केवल उस सीमा तक विचार किया गया है जितना नियमके अनुसार प्रासंगिक है और जहां तक मामले पर प्रभाव डालता है।

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए संगत तर्कों पर नीचे दिए गए पैरा में समुचित जगहों पर जांच और विचार किया गया है जहां उचित समझा गया कार्यवाही की गई है।

### मे. अपार इंडस्ट्रीज लि. द्वारा व्यक्त किए गए विचार

#### क) विचाराधीन उत्पाद एवं सामान वस्तुएं

i) एक्रायलोनाईट्रिल बुटाडिन रबर (एन बी आर) एक सिंथेटिक रबर है तथा इसका प्रचलित नाम नाइट्रिल रबर या एन बी आर है। एन बी आर की विभिन्न श्रेणियां हो सकती हैं और इसकी विभिन्न रूपों में आपूर्ति की जा सकती है।

ii) एन बी आर का उल्लेख आमतौर पर एक्रिलोनाइट्रिल और मूनी विस्कसिटी के रूप में किया जाता है।

iii) भारतीय उद्योग उन सभी ग्रेडों के समान उत्पादों का उत्पादन करता है जिनका इस समय कोरिया गणराज्य और जर्मनी से आयात किया जा रहा है।

iv) भारतीय उद्योग उन सभी ग्रेडों के समान उत्पादों का उत्पादन करने की स्थिति में है जिनका दक्षिण कोरिया और जर्मनी में उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जा रहा है यद्यपि इनका इस समय भारत को निर्यात नहीं किया जा रहा है।

v) एन बी आर 4002.59 के अंतर्गत छह अंकीय स्तर पर अध्याय 40 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में वर्गीकृत है। यद्यपि एन बी आर समर्पित सीमा शुल्क उपशीर्ष के अंतर्गत श्रेणीबद्ध है किन्तु अन्य सीमा शुल्क शीर्षों के अंतर्गत अत्यधिक सामग्री का आयात किए जाने की अनुमति है क्योंकि आयातक किसी समय एन बी आर का उल्लेख सिंथेटिक रबर के रूप में करते हैं। अतः वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) के सरकारी आंकड़े आयातों की मात्रा और मूल्य के बारे में सही एवं पूर्ण दृश्य प्रकट नहीं करते हैं। जर्मनी और दक्षिण कोरिया से एन बी आर के आयातों के बारे में पूर्ववर्ती जांच में भी इस मुद्दे को निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष लाया गया था। वस्तुतः जर्मनी और दक्षिण कोरिया के निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना में यह पुष्टि हुई थी कि उनके द्वारा किया गया निर्यात डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रदर्शित आयातों से काफी अधिक था।

vi) एन बी आर का इस्तेमाल मुख्य रूप से वहां किया जाता है जहां तेल प्रतिरोध, अपघर्षण प्रतिरोध और उष्मा प्रतिरोध के अनुप्रयोग शामिल होते हैं। इसका व्यापक इस्तेमाल रक्षा ऑटोमोबाइल, फुटवियर, वस्त्र, प्रीटर्स, तेल क्षेत्र के उत्पाद उद्योगों इत्यादि में किया जाता है।

vii) एन बी आर के विशेष ग्रेड का इस्तेमाल उस अंतिम प्रयोग पर निर्भर करता है जिस पर वस्तु का प्रयोग किया जा सकता हो।

viii) भारत में विश्व के अन्य भागों के उपभोक्ता संयंत्र और उपकरण में कोई परिवर्तन किए बिना किसी विनिर्माता द्वारा उत्पादित एन बी आर का इस्तेमाल अदल बदल करके कर सकते हैं। एन बी आर का कोई व्यवहार्य प्रतिस्थापन नहीं है और यह कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित एन बी आर और जर्मनी और दक्षिण कोरिया से निर्यातित एन बी आर में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। इन सभी में एक सी विशेषताएं हैं और तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थानीय हैं और इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए।

ix) अपार द्वारा अंगीकृत प्रौद्योगिकी और जर्मनी और दक्षिण कोरिया में उत्पादकों द्वारा अंगीकृत प्रौद्योगिकी में कोई अंतर नहीं हो सकता है क्योंकि विश्व भर में एन बी आर का उत्पादन प्रयास बहुलकीकरण प्राद्योगिकी द्वारा किया जाता है।

x) वर्तमाने जांच एक समापन समीक्षा है और इसलिए विचाराधीन उत्पाद, समान वस्तु और घरेलू उद्योग के बारे में स्थिति पूर्ववर्ती निष्कर्षों में यथानिर्णित ही रहेगी।

## ख. पाटन

### i) सामान्य मूल्य

1. मैसर्स अपार इंडस्ट्रीज लि. द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं:-

i) दक्षिण कोरिया और जर्मनी में विनिर्माताओं की उत्पादन लागत आई सी आई एस एल ओ आर द्वारा यथा प्रदत्त कच्ची सामग्री की कीमतों और सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार अन्य लागतों के आधार पर परिकलित की गई है। परिकलित सामान्य मूल्य \*\*\* डालर/मी. टन बनता है।

ii) निर्यात संबंधी सूचना का संकलन गौण स्रोतों अर्थात् पोलिमर्स प्लास्टिक रबड़ जर्नल(पी पी आर) से किया गया है। इस सामग्री की निकासी सीमा शुल्क द्वारा की गई है जिसमें सिंथेटिक रबड़ का उल्लेख है। अतः आयातक का नाम माल का वर्गीकरण और कीमत जिस पर आयात किया गया है, पर विचार करते हुए पी पी आर आंकड़ों की प्रति जांच की गयी है।

iii) दक्षिण कोरिया और जर्मनी की कारखाना द्वार पर कीमत क्रमशः 1.08 डालर/किग्रा और 1.80 डालर/किग्रा आती है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन अंतर्देशीय भाड़ा पत्तन प्रहस्तन के लिए समायोजन क्रमशः \*\*\* डालर/मी.टन \*\*\* डालर/मी.टन \*\*\*डालर/मी.टन \*\*\*डालर/मी.टन \*\*\*डालर/मी.ट और \*\*\*डालर/मी.टन सीमा तक होना है।

iv) दक्षिण कोरिया के लिए पाटन मार्जिन लागत के आधार पर 144.94% और पूर्ववर्ती जांच के आधार पर 60.67% आता है। जर्मनी के लिए पाटन मार्जिन लागत के आधार पर 48.29% और पूर्ववर्ती जांच के आधार पर 46.94% आता है।

v) घरेलू उद्योग ने मैसर्स के के पी सी के लिए उत्पादन लागत के बारे में अपने अनुमान दिए हैं और यह अनुरोध किया है कि निर्यातक का एन बी आर का प्रचालन लाभदायक नहीं था।

vi) मैसर्स हुंदई ने वर्ष 2001 के पूर्वार्ध के दौरान घाटा दर्शाया है और चूंकि निर्यातक ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है इसलिए हम प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना का इस्तेमाल करें।

vii) मैसर्स बायर जर्मनी इस समय कम कीमतों पर सौदा कर रहा है जिससे हमें नुकसान हो रहा है और हमें आशंका है कि वे अभी भी पाटन कर रहे हैं।

viii) बायर यह तर्क देता रहा है कि उनके मध्यम ग्रेड एन बी आर की लागत की तुलना हमारे मध्यम ग्रेड के एन बी आर की लागत से की जानी चाहिए और उच्च ग्रेड की उच्च ग्रेड के साथ। हमारा निवेदन है कि परिकलन की यह पद्धति उचित है।

ग) क्षति एवं कारणात्मक संबंध

- i) कोरियाई और जर्मनी निर्यातकों ने वर्ष 1995-96 से 2000-2001 तक भारतीय बाजार में निर्यात मात्रा की बढ़ोतरी की है। आयातक और बाजार हिस्सा निम्नानुसार है:-  
(मी.टन)

	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01
दक्षिण कोरिया और जर्मनी	650	2650	2349	3251	1579	1794
अन्य आयात	2804	1834	2323	2028	1946	2219
कुल आयात	3454	4484	4672	5279	3525	4013
घरेलू बिक्री	*****	*****	*****	*****	*****	*****
कुल	*****	*****	*****	*****	*****	*****

बाजार हिस्सा(%)

	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01
दक्षिण कोरिया और जर्मनी	18.8	59.1	50.3	61.5	44.8	44.7
अन्य आयात	81.2	40.9	49.7	38.50	55.2	55.3

- ii) एन बी आर का घरेलू उत्पादन बहुत कम रहा है और परिणामस्वरूप एन बी आर के संयंत्र का उपयोग अत्यन्त कम रहा है। एन बी आर के निरामापूर्ण प्रचालन के फलस्वरूप कुछेक निर्धारित ऊपरी खर्चों की वसूली करने की दृष्टि से इस संयंत्र का उपयोग गैर एन बी आर उत्पादों के उत्पादन के लिए भी किया गया है। एन बी आर उत्पादन और क्षमता उपयोग निम्नानुसार है:-

	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01
सकल एन बी आर का उत्पादन(घरेलू और निर्यात मात्रा समेत) मी. टन	100	84.68	103.69	112.04	114.56
पोलिमर क्षमता	100	100.00	100.00	100.00	100.00
पोलिमर क्षमता उपयोग(%)	100	84.67	103.66	112.10	114.63

iii) घरेलू उद्योग अपनी उचित बिक्री कीमत से कम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य हुआ है जिसे नीचे दर्शाया गया है:-

	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01
औसत एन बी आर बिक्री कीमत(रू./मी.टन)	100	89.40	88.58	82.82	88.85
उत्पाद शुल्क समेत	100	89.40	88.58	82.82	88.85
बिना उत्पाद शुल्क के	100	90.88	91.17	85.50	91.84

iv) कम प्रोत्साहन स्तर पर कर्मचारियों की लागत अधिक रही क्योंकि कर्मचारियों ने यह महसूस किया है कि वे पाटन के कारण अधिक उत्पादन नहीं कर सकते हैं ।

v) उद्योग की लाभ प्रदता में इसकी स्थापना से ही कमी रही है । उद्योग को वित्तीय सुधार से गुजरना पड़ा जिसमें संवर्धकों की ओर से महत्वपूर्ण त्याग करना शामिल था ।

vi) क्षति मार्जिन अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है और यदि शीघ्र उचित शुल्क नहीं लगाया जाता है आगे और खतरा बना रहेगा ।

vii) कुछ अन्य देशों ने एन बी आर का पाटन किया है और उन पर पाटनरोधी शुल्क पहले ही लगाया जा चुका है । मौजूदा पाटनरोधी शुल्क निम्नानुसार है:-

	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-01	
	कीमत रू./किग्रा	मात्रा मी. टन	कीमत रू./किग्रा	मात्रा मी. टन	कीमत रू./किग्रा	मात्रा मी. टन	कीमत रू./किग्रा	मात्रा मी. टन
संबद्ध देश	55.64	2349	45.64	3251	46.93	1579	52.84	1794
देश जिन पर शुल्क लगाया गया	59.78	1094	58.89	799	58.57	729	69.67	699
अन्य देश	79.93	1228	79.86	1229	86.19	1217	108.09	1519



(viii) एन बी आर की मांग थोड़ी वृद्धि के बाद स्थिर रही है और घरेलू उद्योग को क्षति किसी मंदी अथवा मांग में कमी के कारण नहीं हुई है।

#### घ. अन्य मुद्दे

- i) बेयार से हमें ऐसा कोई दस्तावेज प्राप्त करने में हम सफल नहीं हो सके जिसे यह पता चलता हो कि उन्होंने जर्मनी से एन बी आर की आपूर्ति बंद कर दी है। हम यह समझते हैं कि उन्होंने अपने पूरे एन बी आर का उत्पादन फ्रांस में एकत्र कर दिया है और भारत को एन बी आर की आपूर्ति फ्रांस से कर रहे हैं। चूंकि यह घटना जांच अवधि के बाद का है इसलिए हमारा विश्वास है कि डी जी ए डी इसे ध्यान में रखने में सफल नहीं हुआ है।

प्रकटन विवरण के उत्तर में मै0 अपार इंडस्ट्रीज लि0 द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं-  
आरम्भ में हमने अनुरोध किया था कि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है। समीक्षा जांच के निर्दिष्ट प्राधिकारी को पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की जांच करना अपेक्षित है। इस उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लागू है। इसलिए अनेक क्षति मानदंडों को मौजूदा शुल्कों और क्षति की पुनरावृत्ति के आलोक में देखे जाने की आवश्यकता है। तत्कालिक मामले में भी प्रकटन विवरण से यह पता चलता है कि सम्बद्ध वस्तु से भी पाटन जारी रहा है। इसलिए वर्तमान स्थिति पाटन की पुनरावृत्ति के बजाय पाटन जारी रहने की है। इसलिए शुल्क को और पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखना अनिवार्य है।

हम यह भी उल्लेख करना चाहेंगे कि पाटन रोधी शुल्क के रूप में डीजीएडी द्वारा की गयी कार्रवाई के कारण अभी तक हमारा अस्तित्व बना हुआ है। हमने उत्पादन, संयंत्र उपयोग और बिक्री मात्राओं को अधिकतम करने की अपनी पूरी कोशिश की है। तथापि हमें आयातों से हुई भारी कीमत कटौती के कारण न्यूनतम कीमतों पर बिक्री करने को लगातार बाध्य होना पड़ा।

मौजूदा जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है। विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में स्थिति समान है। उद्योग के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं है। घरेलू उद्योग का दायरा समान रहता है। निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण में इन्हें स्वीकार किया गया है। हम निर्दिष्ट प्राधिकारी से इस संबंध में पहले के जांच परिणामों की पुष्टि करने का अनुरोध करते हैं।

विभिन्न ग्रेडों के समान वस्तु होने के मुद्दे के संबंध में यद्यपि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यह माना गया है कि यह तर्क विरोधी इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रमाणित नहीं है, हम अनुरोध करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा देश में आयातित सामान के समान वस्तु का उत्पादन करना अपेक्षित है। एक वस्तु के विभिन्न ग्रेड स्वयं ही प्रतिस्थापनीय नहीं हो सकते। यद्यपि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ये समान वस्तु नहीं हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गयी विभिन्न जांचों पर भरोसा किया जा सकता है जिनमें डीएमटी/पीटीए, बीओपीपी, एक्रिलिक फाइबर इत्यादि और पोलिएस्टर फिल्म के संबंध में अन्य देशों के साथ-साथ भारत के विरुद्ध यूरोपीय कमीशन द्वारा पाटनरोधी जांच शामिल है।

उपर्युक्त के बावजूद, यह अनुरोध किया गया है कि एनबीआर के विभिन्न ग्रेड समान उत्पाद हैं क्योंकि ये विभिन्न उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रसायनिक विशेषताएं, उत्पाद विनिर्दिष्टताएं, कच्चा

माल, उत्पादन प्रौद्योगिकी और विनिर्माण प्रक्रिया, कार्य और उपयोग, कीमत, टैरिफ वर्गीकरण इत्यादि के रूप में तुलनीय है। यह इंगित करना अनिवार्य होगा कि विभिन्न मापदंडों के मूल्यों में मामूली उतार-चढ़ाव से स्वतः विभिन्न उत्पादों का संकेत नहीं मिलता है। विभिन्न उत्पाद मापदण्डों में मामूली उतार-चढ़ाव इस उत्पाद के लिए विशिष्ट नहीं है। यह लगभग प्रत्येक उत्पाद के लिए है।

यह इंगित करना भी अनिवार्य होगा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह भी माना है कि इस उत्पाद के बारे में पहले की गयी जांच में विभिन्न एनबीआर समान उत्पाद हैं। इस मामले में इस तर्क की कोई महत्ता नहीं है कि विभिन्न प्रकार अलग-अलग उत्पाद है।

### कोरिया द्वारा पाटन

प्रकटन विवरण यह दर्शाता है कि पाटन मार्जिन सिर्फ 10.60 प्रतिशत का है। स्पष्टतया कुम्हों द्वारा किए गए अनुरोध पूर्ववर्ती समीक्षा में निर्यात द्वारा किए गए अनुरोध पूर्ववर्ती समीक्षा में निर्यातकों द्वारा किए गए अनुरोधों के परस्पर विरोधी हैं।

समीक्षा 1 में निर्धारित पाटन मार्जिन 27.94 प्रतिशत अथवा 248.3 डालर/मी0टन था। यदि हम थोड़ा देर के लिए यह मान लें कि उत्पादन लागत में कोई अन्य परिवर्तन नहीं है तो कच्चे माल की लागतों और बिक्री कीमतों में परिवर्तनों के कारण निर्णायक समीक्षा में पाटन मार्जिन 350 अमरीकी डालर/मी0टन अथवा इससे अधिक तक बढ़ गया होता।

हमारा यह तर्क कि निर्णायक समीक्षा में पाटन मार्जिन में वृद्धि हुई है इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कुम्हों की हानि में काफी अधिक वृद्धि हुई है। कुम्हों को कैलेंडर वर्ष 2000 में 24.257 बिलियन बोन की भारी हानि हुई और वर्ष 2001 के पूर्वार्ध में 9249 बिलियन बोन की हानि हुई है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जांच की अवधि 2000-01 में, कुम्हों को कच्चे माल की ऊंची कीमतों और परिष्कृत उत्पाद कीमतों में अनुमानुपाती वृद्धि के कारण अत्यधिक हानि हुई है।

हम निर्दिष्ट प्राधिकारी के ध्यान में यह बात लाना चाहेंगे कि हमारे विचार में 10.60 प्रतिशत का पाटन मार्जिन न केवल घरेलू उद्योग की उम्मीद से कम है बल्कि तथ्यों से भी काफी कम है।

इन दोनों समीक्षाओं के संबंध में निम्नानुसार भी अनिवार्य होगा:-

(क) मौजूदा मामले में जांच की अवधि वर्ष 2000-01 है जो कि निर्यातक के वित्तीय वर्ष से अलग है क्योंकि वह लेखे कैलेंडर वर्ष के आधार पर रखता है। प्रकटन विवरण से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या निर्यातक ने जांच की अवधि के लिए सूचना उपलब्ध कराई है।

(ख) समीक्षा 1 में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा अनेक मिलान विवरण पत्रों का मुद्दा उठाया गया था। पूर्ववर्ती समीक्षा में निर्यातक के उत्तर पर विचार करते हुए यह महत्वपूर्ण है कि क्या अब निर्यातक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी सूचना और विभिन्न मिलान उपलब्ध कराए हैं।

ग. कच्चे माल की खपत के संबंध में हम अनुरोध करते हैं कि समीक्षा 1 में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए खपत के कारक को इस मामले में भी लागू किए जाने की आवश्यकता है जो पूर्ववर्ती मामले में कंपनी के प्रचालनों की जटिल और निर्यातक के व्यवहार को बताते हैं।

घ. कंपनी द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर लागत के कम से कम दो घटकों पर विचार नहीं किया जा सका। ये हैं- समीक्षा 1 में अनुभव पर विचार करते हुए क परिवर्तन लागत और ख अन्य संयंत्र लागत।

ङ. यह प्रतीत होता है कि निर्यातक ने दोबारा उत्पाद की कम लागत दर्शायी है या तो कच्चे माल की लागत कम बताई गयी है अथवा परिवर्तन लागत कम बताई गई है। हम उत्पादन की मौजूदा लागतके साथ उत्पादन की पूर्ववर्ती लागतकी घटकवार तुलना करने का अनुरोध करते हैं। यदि यह पाया जाता है कि लागत के कुछ घटकों का पहले दर्शाई गई लागत से काफी कम दावा किया गया है तो यह अनुरोध किया जाता है कि ऐसे दावों पर पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता है।

समीक्षा 1 के दौरान प्रस्तुत पहले अध्ययन के अनुसार उत्पादन की लागत 890 अमरीकी डालकर/मी०टन की तरह कम नहीं होगी।

यह नोट किया जा सकता है कि कोरिया ने अपनी घरेलू आवश्यकताओं के अनुसार क्षमताओं को बढ़ाया है। इस उत्पाद के लिए कोरियाई क्षमता उनकी अनुपातिक कम घरेलू मांग की तुलना में 40,000 मी०टन की है। इस प्रकार कोरिया में उत्पादकों की हमेशा अधिक क्षमता की समस्या रही है। उनकी समस्या को और बढ़ाने के लिए और उत्पादक हुंदई ने लगभग 4-5 वर्ष पहले सुविधाएं स्थापित कर ली और इस प्रकार इसकी बिक्री और कुम्हों की बिक्रियों पर इनका जबरदस्त दबाव पड़ा। निर्यातक निश्चित रूप से मामूली लागत पर निर्यात कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने स्वयं के घरेलू बाजार में बिक्री भी कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश उन्हें उत्पादन की अपनी पूरी लागत से कम पर बिक्री करनी पड़ रही है और इस प्रक्रिया में उन्हें हानि हो रही है।

यहां पाटन से संबंधित अन्य मुद्दा यह है कि दोनों कोरियाई उत्पादकों के अपने स्वयं के बुटाडिन हैं जिससे वे लाभ कमा रहे होंगे। तथापि, बुटाडिन से कमाए गए लाभों से एनबीआर पर उठाई जा रही हानि को पूरा नहीं किया जा सकता। जैसाकि ज्ञात है पाटनरोधी जांच उत्पाद विशिष्ट जांच है। निर्यातकों को यह प्रमाणित करना होगा कि उनके एनबीआर प्रचालन लाभप्रद थे- जो कि असंभव है क्योंकि वास्तविक स्थिति कुछ और दर्शाती है। इसलिए कंपनी द्वारा उत्पादित कच्चे माल को ऐसे माल की बाजार कीमत के अनुसार माना जाना चाहिए।

यह भी अनुरोध किया गया कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन के संबंधमें निम्नलिखित मुद्दे अनिवार्य हैं-

(क) पैकिंग लागत:- यद्यपि यह माना गया है कि पैकेजिंग के रूप घरेलू बाजार के मामले में अलग हैं, फिर भी केकेपीसी के सीगेट और निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष जोरदार तर्क दिया और जहां तक हमें बाजार की जानकारी का संबंध है केकेपीसी ऐसी पैकेजिंग सामग्री का उपयोग कर रहा है जिसे उपभोज्य के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। कंपनी द्वारा इसी माल का पुनःनिर्माण किया जाता

हे। इसलिए पैकेजिंग माल पर उत्पन्न लागत को पैकेजिंग लागत के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है। ऐसा मामला होने के कारण ज्यादा से ज्यादा ऐसे पैकेजिंग सामग्री पर ह्रास और पुनर्निर्माण की लागत को पैकेजिंग लागत माना जा सकता है। यह भी अनुरोध किया गया कि यह हरसंभव संभावना है कि निर्यातक ने स्वदेशी भाड़े के कारण समायोजन के तहत पैकेजिंग माल की वापसी के साथ संबद्ध परिवहन प्रभारों को पहले ही शामिल कर लिया है। इसलिए निर्यातक द्वारा इस कारण कोई कीमत समायोजन नहीं किया गया। इस संबंध में यह इंगित करना भी अनिवार्य होगा कि ऐसे माल की आयु कम से कम दस वर्ष होगी। इसके अलावा यह अनुरोध किया गया कि मूल्यह्रास की पूरी लागत को एक ही खेप से वसूल नहीं किया जा सकता। निर्यातक द्वारा उसी पैकेजिंग सामग्री का उपयोग अनेक खेपों में किया गया होगा। इस प्रकार पैकेजिंग की लागत पर विचार करते समय उन चक्रों की संख्या, जिनके लिए पैकेजिंग माल का उपयोग किया गया है, पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है।

निवेदन यह है कि निर्यात का दावा एकाउंटिंग सूचना की बाजार पैकिंग लागत के नमूना परिगणन के आधार पर किया गया प्रतीत होता है। संभवतः पैकिंग सामग्री की लागत की बजाय पूरे वर्ष के दौरान निर्यातक द्वारा पैकिंग सामग्री पर किए गए कुल खर्च पर ध्यान देना आवश्यक होगा।

ख) अमेरिकी डालरों के रूप में घरेलू बाजार में बिक्री निर्यात की घरेलू बाजार की बिक्री अमेरिकी डालरों में है। किन्तु ये निर्यातक की कल्पित निर्यात बिक्री मालूम होती हैं। यहां यह कहना संगत होगा कि सहकर्मी के रूप में निर्यातक का व्यापार में एक हिस्सा हो। संभव है कि निर्यात की कुछ बिक्री व्यापारिक शाखा की मारफ़त हुई हो। किन्तु यदि माल वास्तव में कोरिया से बाहर चला गया है तो इस बिक्री को घरेलू बिक्री नहीं माना जा सकता और इसे अलग कर देना आवश्यक है।

ग) व्यापार का स्तर:- व्यापारिक स्तर का तर्क पाटन मार्जिन परिगणन से संबंधित नहीं है। भारत को निर्यात और घरेलू बिक्री के व्यापार का स्तर समान ही है। क्षति मार्जिन के बारे में, (क) निर्यातक और घरेलू उद्योग व्यापार के समान स्तर पर ही बिक्री कर रहे हैं (ख) क्षति मार्जिन, पाटन मार्जिन की अपेक्षा बहुत अधिक है।

घ) परिशोधन खर्च- अभूर्त संपत्तियों का परिशोधन सामान्य सुविधाओं के मूल्य ह्रास के बराबर दी है क्योंकि सामान्य सुविधाओं के मूल्य ह्रास उत्पादन में जोड़ दिया जाता है इसलिए पूरी उत्पादन लागत में से अभूर्त संपत्ति को निकाला नहीं जा सकता है, विशेष रूप से तब जबकि उत्पादन लागत का निर्धारण एस जी ए पर विचार करने के बाद किया जाना हो।

ड.) ड्यूटी ड्रा बैंक:- निर्यातक ने पहले कमी इस आधार पर भत्ते का दावा नहीं किया है। इसके अलावा निर्यातक ने शुल्क मुक्त सामग्री का आयात करना शुरू कर दिया है। अतः यह मालूम नहीं हुआ कि अब समायोजन के रूप में निर्यातक ड्यूटी ड्रा बैंक का दावा कैसे कर सकता है।

(च) बुटाडीन मूल्य:- जैसाकि पहले दिया जा चुका है, निर्यातक ने जिस मूल्य पर बुटाडीन खरीदी है उसी कीमत पर बुटाडीन पर विचार किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति के बुटाडीन की उत्पादन लागत, एस जी ए सहित बुटाडीन की पूर्ण उत्पादन लागत होनी चाहिए।

### हुंडई द्वारा पाटन

हुंडई द्वारा किए गए पाटन का संबंध है कि उनके घाटे आश्चर्यजनक रूप से बढ़ रहे हैं। कैलेण्डर वर्ष 2000 में 378.35 बिलियन वोन का घाटा हुआ था जबकि 2001 के पूर्वार्ध में 144.482 बिलियन वोन का घाटा दिखाया गया है।

अतः हुंडई का पाटन मार्जिन स्वच्छतः कुम्हो से अधिक है, इस बात पर भी ध्यान दें कि यह एक नया संयंत्र है और तदनुसार इसकी ब्याज और मूल्य ह्रास लागत अपेक्षाकृत अधिक होगी। संभवतया इसी कारण से इस कंपनी ने प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया है। चूंकि निर्यातक ने उत्तर न देने का विकल्प अपनाया है अतः अनुरोध है कि इस कंपनी के संबंध में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना वाला विकल्प अपनाया जाए।

### बायर द्वारा पाटन

समीक्षा 1 से स्पष्ट पता चलता है कि पाटन जारी है और हमें आंशका है पाटन अब भी जारी है। इसके अलावा, कई बार वे कम कीमत पर व्यापार कर रहे हैं जिससे हमें क्षति हो रही है। बायर ने यह मुद्दा भी उठाया है कि यह कंपनी भारत को हाइ एक्रिलोनाइटिल स्तर एन बी आर (संक्षेप में हाइ एन बी आर) और मीडियम एक्रिलोनाइट्रिल स्तर बी एन आर (संक्षेप में मीडियम एन बी आर) का निर्यात भी भारत को कर रही है। हम भी यह किस्म बना रहे हैं। बायर अपने मीडिया के साथ हमारे हाइ एन बी आर की लागत की तुलना का भी तर्क दे रही है। हमारा निवेदन है कि हमें इस प्रकार की तुलना पर कोई आपत्ति नहीं है।

### क्षति और कारणात्मक संबंध

क्षति के मामले में हमें भारी पाटित आयातों के कारण, विशेष रूप से दक्षिण कोरिया से, अपने अक्षतिकर कीमतों से बहुत कम कीमत पर बेचने को मजबूर होना पड़ा है। हालांकि उत्पादन की दृष्टि से हमारा काम अच्छा रहा है किन्तु बिक्री, क्षमता उपयोग और हमारे मार्जिन की दृष्टि से हम काफी दबाव में रहे हैं और एन बी आर के व्यापार में हमें घाटा होता रहा है।

निवेदन है कि वर्तमान जांच विद्यमान पाटनरोधी शुल्क की समर्पण समीक्षा है। उत्पादन, बिक्री की मात्रा, विक्रय मूल्य, लाभ/हानि आदि जैसे आर्थिक मानदंडों की जांच उत्पाद पर लागू पाटनरोधी शुल्क के संदर्भ में की जानी चाहिए। इस मामले में क्षति की पुनरावृत्ति भी समान रूप से महत्वपूर्ण है जबकि मामले के तथ्य यह तो साफ दर्शाते हैं कि पाटन जारी है। हमारा यह भी निवेदन है कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने से कुछ मापदंडों में जो सुधार हुआ है वह पाटनरोधी शुल्क की विद्यमानता के कारण ही हैं, जिससे केवल यही सिद्ध होता है कि इस प्रकार का शुल्क जारी रखना न्यायोचित है। इस प्रकार की समीक्षा में केवल घरेलू उद्योग का उचित बिक्री मूल्य और आयातित सामान की पहुंच कीमत ही संगत मापदंड होते हैं ताकि विद्यमान क्षति मार्जिन का अनुमान लगाया जा सके। जैसकि हमारे द्वारा उपलब्ध करायी गयी लागत संबंधी सूचना से देखा

जा सकता है, इस मामले में क्षति मार्जिन काफी अधिक बढ़ गया है, जिससे अपेक्षाकृत अधिक शुल्क लगाना अनिवार्य हो गया है।

मूल्य में कटौती: पाटित आयातों से भारतीय बाजार में मूल्य में कटौती हो रही है। कोरिया से आयात का पहुंच मूल्य घरेलू बाजार में विक्रय मूल्य और कोरिया से आयात पर पाटनरोधी शुल्क के बावजूद अक्षतिकर मूल्य से काफी कम रहा है। जर्मनी से आयात के पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के अक्षतिकर मूल्यों की तुलना में कम हैं।

निम्नलिखित कुछ तथ्यों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति के सबूत मिलते हैं-

क) संबद्ध देशों के घरेलू बाजार में उनकी क्षमता से उत्पादित सारा माल न खपने और पहली जांच अवधि के बाद उनकी क्षमताओं में और वृद्धि हो जाने से निर्यातकों के पास बड़ी उत्पादन क्षमता है।

ख) भारत में इतनी कम कीमतों पर आयात हो रहा है जिससे घरेलू कीमतों पर भारी दमनकारी प्रभाव पड़ रहा है। हमारी उत्पादन लागत तो बढ़ गयी है किन्तु हम आने विक्रय मूल्य बढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं।

ग) आयातों के कारण मूल्य में अत्याधिक कटौती करनी पड़ रही है और परिणामतः घरेलू उद्योग अपना सामान अपने उचित विक्रय मूल्यों पर बड़ी बेच पर रहा है।

घ) पाटनरोधी शुल्क लग जाने के बाद भी घरेलू उद्योग अपने परिचालन मार्जिन में सुधार नहीं कर सका है।

(ङ.) घरेलू उद्योग के पास स्टाफ में वृद्धि हो गई हैं। इस कारण उद्योग को अपना एन बी आर उत्पादन घटाने को बाध्य होना पड़ा था।

च) उद्योग का क्षमता उपयोग इष्टतम से कम रहा है। परिणामतः उद्योग को अपने संयंत्र का उपयोग बढ़ाने के लिए अन्य वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ा था।

छ) बाजार में घरेलू उद्योग का हिस्सा कम रहा है और यदि कोरिया से आयात पर पाटनरोधी शुल्क उचित रूप से नहीं बढ़ाया गया तो इसमें और गिरावट होने की संभावना है।

ज) बाजार में इस वस्तु के निरंतर पाटन से घरेलू उद्योग के कर्मचारियों के मनोबल में गिरावट आयी है।

झ) घरेलू उद्योग को लाभ कम होने से इसके विकास में अड़चने आ रही हैं। प्रतिस्पर्धा शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रवर्तकों ने धन लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। किन्तु पाटन जारी होने से निवेश अलाभकारी हो जाएंगे। इसके अलावा नए निवेश भी उसके बाद संभव नहीं होंगे क्योंकि निवेशकर्ताओं को अपने निवेश पर लाभ का भरोसा नहीं रहेगा।

### परिवर्तनीय आधार पर शुल्क

अनुरोध है कि संशोधित शुल्क परिवर्तनीय आधार पर अमेरिकी डालर में लागू करने की सिफारिश की जाए। निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए यह उचित होगा:-

1. जांच अवधि के बाद निर्यातक के संदर्भ में निर्यात कीमत काफी गिर गई है। यह तब हुआ है जब कि संबंधित कच्चे माल की कीमतों में कोई खास गिरावट नहीं आयी है। इसलिए जांचोंपरांत अवधि में पाटन बढ़ गया है। परिवर्तनीय शुल्क का पूरा उद्देश्य अत्यधिक पाटन को रोकना होने के कारण परिवर्तनीय शुल्क सर्वाधिक उचित आधार होगा।
2. जांच अवधि के बाद इस उत्पाद पर सीमा शुल्क भी कम हुआ है। यह शुल्क और कम हो सकता है। चूंकि परिवर्तनीय शुल्क लगाने का एक उद्देश्य सीमाशुल्क घटने से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को रोकना है इसलिए परिवर्तनीय शुल्क लगाना उचित रहेगा।
3. समापन समीक्षा जांच में नामित प्राधिकारी ने जापान से इस वस्तु के आयात पर परिवर्तनीय शुल्क पहले ही लागू कर दिया है।
4. नामित प्राधिकारी ने गत समय में एक्रिलोनाइड्रिल की भारी खपत वाले एक्रिलिक फाइबर पर परिवर्तनीय शुल्क की सिफारिश की थी जो कि इस मामले में मुख्य कच्चा माल है।
5. कच्चे माल की संबद्ध कीमतों में परिवर्तन के अनुरूप निर्यातक के निर्यात मूल्य में आनपातिक परिवर्तन नहीं हुआ है। संलग्न तालिका से पता चलता है कि निर्यातक ने काफी हद तक कच्चे माल के कारण परिवर्तन को उत्पादन लागत में समाहित कर दिया है।
6. जैसाकि सी ई जी टी ने भी कई मामलों में माना है, नामित प्राधिकारी भी इससे सहमत हैं कि संघनित पाटन के मामलों से निपटने के लिए परिवर्तनीय शुल्क ही उचित बेंच मार्क है।

उपर्युक्त को देखते हुए प्रार्थना है कि अंतिम शुल्क कृपया परिवर्तनीय आधार पर अमेरिकी डालरों में ही लगाया जाए।

### अहानिकारक मूल्य

निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित \*\*\*\* रूपए के अक्षतिकार मूल्य के लिए हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

### 2. आयातकों के विचार

क) विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध वस्तु

1. अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं-

- i) अपार उन सभी ग्रेडों के एन बी आर का उत्पादन नहीं करता जो मै. के के पी सी और मै. बायर द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। अपार के एन बी आर ग्रेड के के पी सी तथा बायर द्वारा उत्पादित एन बी आर ग्रेड समान वस्तु नहीं है अतः आयातों पर निर्भर होने की आवश्यकता होगी।
- ii) अपार इन्डस्ट्रीज द्वारा उत्पादन किए जाने वाले एन बी आर के उन ग्रेडों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना न्यायसंगत नहीं है।

2. अखिल भारतीय रबर फुटवियर उद्योग परिसंघ द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं:-

- i) अपार एन बी आर के सभी ग्रेडों का उत्पादन नहीं करता जो उत्पादन के के पी सी और बायर द्वारा किए जाते हैं।

3. भारत के लघु रबर उद्योग संघ द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए गए:-

- i) प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एन बी आर की विनिर्दिष्टियों और विभिन्न प्रकार के रासायनिक बनावट की जांच भी अवश्य करनी चाहिए।

ख) क्षति

1. अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं:-

- i) मै. अपार ने यह दावा किया है कि डी जी सी आई एंड एस आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं और पी बी आर आंकड़ों पर निर्भर करने पर बल दिया है। संघ ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को विश्लेषण के लिए डी पी सी आई एंड एस के सरकारी आंकड़ों पर विश्वास करने का अनुरोध किया है।
- ii) घरेलू उद्योग के मार्किट 1994-95 में 28% से बढ़कर 2000-01 में 52% तक पहुंच गए हैं और उनका उत्पादन 1994-95 में 2452 रूप टी में 2000-01 में 5280 एमटी तक पहुंच गया है जो यह सिद्ध करता है कि के के पी सी और बायर द्वारा निर्यात से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
- iii) अपार एन बी आर उत्पादन की उच्च लागत का संबंध इनके बड़े उत्पाद संयंत्र से है और संयंत्र के अयोग्य परिचालन उत्पादों की सीमित रेंज के कारण कच्चे माल की उर्ची कीमतों अस्थिर व्यापार स्थिति पर नियंत्रण के सुझाव तथा संयंत्र की अलाभकारी क्षमता के कारण ऐसा हो रहा है।
- iv) निर्दिष्ट प्राधिकारी को एक मद से दूसरे मद तक क्षमता और उत्पादन के बदलने के कारण विभिन्न ग्रेडों के सिंथेटिक रबर पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए घरेलू उद्योग के सभी आवेदनों पर विचार करना चाहिए।



- v) अपार के मूल्य 80% से अधिक तक बढ़े हैं और उन्हें कोई क्षति नहीं हुई ।
- vi) अपार के अक्षतातिकर मूल्य अब कम होंगे क्योंकि उन्होंने अपनी प्लोट की क्षमता बहौर है और उपयोगिता के लिए उनके दावों में सुधार हुआ है एवं के के पी सी और आयर के आयातों से आने वाले समय में कोई क्षति नहीं होगी ।

## 2. अखिल भारतीय रबर फुटवियर उद्योग परिसंघ द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं-

- i) अपार ने अपनी क्षमता बढ़ाई है, परन्तु वह क्षमता एन बी आर की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है ।
- ii) हम निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे विश्लेषण के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर निर्भर करे, पी पी आर आंकड़ों पर नहीं जैसकि अपार ने दावा किया है ।
- iii) अपार ने अक्षतिकर मूल्य से अधिक मूल्य पर सामग्री बेची है और अच्छे लाभ प्राप्त किए हैं ।
- iv) जर्मन एन बी आर के पहुंच मूल्य पाटनरोधी मूल्य को ध्यान में न रखते हुए कारखानागत विक्रय मूल्य से अधिकतर है और जर्मनी से एन बी आर का आयात कम हो गया है और उनके मूल्य बढ़ गए हैं ।

## 3. भारत के लघु रबर उद्योग संघ द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए गए:-

- i) जांच की समीक्षा अवधि 30.9.2001 तक बढ़ा देनी चाहिए ताकि वर्तमान स्थिति भी प्रतिबिम्बित हो सके । घरेलू उद्योग की निजी मूल्य अत्यधिक कम है और मैसर्स अपार इन्डस्ट्रीज लि. का बहुत अधिक फायदा हुआ है ।
- ii) मैसर्स अपार का निष्पादन सदैव उत्तम रहा है और संबद्ध देशों से आयातों के कारण हुई किसी क्षति के लिए कोई कारणात्मक संबंध नहीं है ।
- iii) मैसर्स अपार की क्षमता कम रहती है और यह मूल्य के लिए प्रभावकारी एवं लाभ योग्य नहीं है ।
- iv) अपार एन बी आर और कुछ अन्य मदों का उत्पादन करता है जिसमें व्यापार उत्पाद विविधता का लाभ उसे नहीं मिल पाता और परिणामतः उन्हें कच्चे माल की अस्थिर कीमतों पर निर्भर होना पड़ता है तथा निविष्टियों/विक्रय मूल्यों पर नियंत्रण न होने के कारण वह कीमतों के मार्च पर अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माताओं के सामने हार जाते हैं ।
- v) अपार का प्लांट ऐसे स्थान पर स्थित हो जहां पर कच्चा माल ले जाने के लिए वास्तविक परिवहन लागत और अन्य खर्च होते हैं ।
- vi) अपार इंडस्ट्री को उत्पादन की रूप रेखा बिक्री उत्पादन लागत आदि का विस्तृत विवरण देना चाहिए ।
- vii) अपार एन बी आर, एस बी आर और एच एस आर जैसे विभिन्न प्रकार के रबरों के उत्पादन के दर्शाने वाली विस्तृत सूचना अवश्य है ।
- viii) इस विषय में गहराई से जांच करने के लिए और पाटनरोधी प्राधिकारी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कास्ट अकाउंटेंट चाहिए अकाउंटेंट इंजिनियरों और प्रोसेस एन लिस्ट की एक टीम तैयार की जानी चाहिए ।

**अन्य विषय**

1. **अखिल भारतीय रबड़ इंडस्ट्रीज संस्था द्वारा निम्नलिखित निवेदन दिए गए हैं ।**
  - i) पाटनरोधी प्राधिकारी ने 7.12.2001 को सार्वजनिक सुनवाई के लिए उचित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया ।
  - ii) मै. ऋषिरूप पालिमर्स प्रा.लि.को ऐसी आशंका है कि उन्हें प्राधिकारी से स्पष्ट एवं निष्पक्ष निर्णय नहीं मिल सकता है और उन्होंने प्राधिकारी से अनुरोध किया है वे जांच से अलग हो जाए और सरकार से किसी अन्य प्राधिकारी को नामित करेंगे के लिए वहां है जो नए हिस्से सुनवाई करेगा हम घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों के और साथ ही उपयोक्ता उद्योग दोनों को स्पष्ट एवं शीघ्र अवसर उपलब्ध करवाने के लिए मै. ऋषिरूप पॉलिमर्स प्रा. लि. के आधार को समर्थन करते हैं ।
2. **अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संस्था द्वारा निम्नलिखित निवेदन दिए गए हैं-**
  - i) देश की एन बी आर कुल योग को घरेलू उद्योग के उत्पादन से पूरा नहीं किया जा सकेगा क्योंकि उनके द्वारा एन बी आर की मांग का 6.67% वार्षिक उत्पादन होता है ।
3. **भारत की लघु स्तर रबड़ उद्योग संस्था द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए गए**
  - i) रबड़ उद्योग के मूल निवेशों पर लगतार पाटन रोधी शुल्क लगाने से परिष्कृत रबड़ उत्पादों के मामलों की बाढ़ जाएगी और भारतीय रबड़ विनिर्माताओं द्वारा घरेलू बाजार में पाव जमानों बहुत मुश्किल होता है ।
  - ii) उपयोक्ता उद्योग घरेलू उद्योग और निर्यात उद्योग के बीच स्पष्ट कापार की सराहना करेंगे और यह स्पष्ट प्रतिस्पर्धा समाप्त नहीं होनी चाहिए मामले की गहराई से जांच करने और पाटन रोधी प्राधिकारी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कास्ट अकाउन्टेन्ट चार्टिड अकाउन्टेन्ट इंजिनयरों और प्रोसेस एनेलिस्ट की एक टीम तैयार की जानी चाहिए ।
3. **निर्यातकों के विचार**
  1. **मै.कोरिया कुमहो पैट्रकैमिकल कं. लि. (के के पी सी) कोरिया आर पी**
    - i) मै. अपार सभी प्रकार के एन बी आर का उत्पादन नहीं करता है जो मै. के के पी सी और मै. बायर द्वारा बनाए जाए है और अपार के ग्रेड के के पी सी द्वारा उत्पादित ग्रेड के समान नहीं है अतः यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन हैं ।
    - ii) भिन्न 2 प्रकार के एन बी आर है जैसे कि माक्सीलेटिड एन बी आर जो अपार इंडस्ट्रीज द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता इसलिए इन ग्रेडों पर किसी प्रकार का पाटन रोधी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए ।

**ख. पाटन**

- i) मै. के के पी सी ने निर्यातक प्रश्नावली प्रस्तुत की है और जांच अवधि (पी ओ आई) के दौरान एन बी आर के विभिन्न ग्रेडों की उत्पादन लागत, बिक्री की गई ग्रेडों की घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री कीमतों तथा भारत तथा अन्य देशों में निर्यात कीमतों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध कराए हैं ।
- ii) मै. के के पी सी ने पैकिंग और अन्तर्देशीय भाड़े के कारण क्रमशः \*\*\*\* डालर/मी.टन तथा \*\*\*\* डालर/मी.टन की सीमा तक घरेलू बिक्री कीमतों पर समायोजनों का दावा किया है ।
- iii) मै. के के पी सी ने ऋषिरूप पोतीमर्स प्रा. लि. के लिए अंतर्देशीय भाड़े समुद्री भाड़े समुद्री बीमा ड्यूटी ड्रबिक एवं पैकिंग तथा कमीशन के कारण क्रमशः \*\*\*\* डालर/मी.टन \*\*\*\*डालर/मी.टन \*\*\*\*डालर/मी.टन \*\*\*\*डालर/मी.टन \*\*\*\*डालर/मी.टन तथा \*\*\*\* डालर/मी.टन की सीमा तक निर्यात कीमत पर समायोजनों का दावा किया है । मै. के के पी सी ने यह भी इंगित किया है कि भारत में उनके निर्यात थोक विक्रेताओं को किए गए हैं जबकि मै. अपार इंडस्ट्रीज लि. द्वारा विक्रियां अंतिम उपभोक्ताओं को की गई हैं तथा व्यापार के इस स्तर के कारण समायोजन \*\*\*\* डालर/मी.टन माना जाना चाहिए ।
- iv) निर्यातक ने एस जी ए व्ययों आर एंड डी व्ययों तथा ब्याज प्रभारों के संबंध में 23-24 अगस्त, 2002 को सिओल में के के पी सी के प्रांगण में की गई जांच के दौरान मांगी गई सूचना भी उपलब्ध कराई है । मै. के के पी सी ने प्राधिकारी के दिनांक 10.6.2002 के पत्र के उत्तर में दिनांक 27 अगस्त 2002 को पत्र दिया है और कुछेक मामलों में अपनी घरेलू बिक्रियों के यू एस डालर में होने, निर्यात कीमत के साइट बेसिस पैकिंग के प्रकार, भारत को निर्यातों पर हैंडलिंग प्रभार एस जी ए व्ययों पर स्पष्टीकरण एवं खपत मानकों और उत्पादन लागत में वित्तीय व्ययों पर आधारित होने संबंधी अपने स्पष्टीकरण की ओर ध्यान दिलाया है ।
- v) मै. के के पी सी ने घरेलू उद्योग में बंची गई कम मात्रा तथा बिना किसी तकनीकी समर्थन के भारत में भेजी गई भारी मात्रा के संबंध में भी समायोजनों की मांग की है । व्यापार के इस स्तर में अंतर के लिए 7.5% के समायोजनों की मांग की गई है ।
- vi) यह इंगित किया गया है कि मै. अपार के के पी सी के लिए परिकलित लागत के बारे में प्राधिकारी को भ्रम में डाल रहा है । अपार द्वारा मै. के के पी सी के संबंध में प्रस्तुत पाटन मार्जिन बढ़ाया गया तथा भ्रामक है ।
- vii) मै. के के पी सी ने यह भी संकेत किया है कि पी ओ आई की निर्णायक समीक्षा के दौरान कोई पाटन नहीं किया गया है तथा बिक्री के आवंटन के तरीके पर ध्यान दिलाया है और मै. के के पी सी के लिए उत्पादन लागत के मूल्यांकन के लिए प्रशासनिक व्ययों को ध्यान में रखने के लिए कहा है ।

#### ग. क्षति

- i) मै. के के पी सी ने प्राधिकारी के दिनांक 10.6.2002 के पत्र के उत्तर में घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में विचार प्रस्तुत किए हैं जिसमें यह इंगित है कि निर्णायक समीक्षा अवधि के दौरान भारत को एन बी आर के निर्यातों में पर्याप्त कमी आई है और के के पी सी द्वारा भारत को निर्यातों में महत्वपूर्ण वृद्धि की कोई संभावना नहीं थी । मै. के के पी सी द्वारा यह भी इंगित किया

गया है कि उनके पास निकट भविष्य में क्षमता विस्तार के लिए कोई निर्बाध रूप से निपटान क्षमता या योजना नहीं है। यह भी इंगित किया गया है कि पी ओ आई निर्णायक समीक्षा के दौरान मै. के के पी सी से भारत को निर्यात कीमत में वृद्धि हुई है तथा पी ओ आई के दौरान भारतीय मुद्रा के अवमूल्य के साथ जुड़ी हुई है। यह भी संकेत किया गया है कि मै. के के पी सी के पास निपटान या भारत को निर्यात के लिए एन बी आर की कोई फालते वस्तु सूची नहीं है।

- ii) यह अनुरोध किया गया है कि एन बी आर संयंत्र के अपार की संबंध में आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करते समय, प्राधिकारी को उनके वालिया प्लांट जहां वे प्रचलनों की कुल लागत से अपने एन बी आर का निर्माण करते हैं, में उनके द्वारा उत्पादित एच एस आर की मात्रा के लिए क्षमता प्रचालन लागत निवेश पर आय आदि के संबंध में स्थापित क्षमता को समायोजित करना चाहिए। ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि वालिया संयंत्र में उनके एन बी आर तथा एच एस आर प्रचालन के लिए प्राधिकारी द्वारा विभिन्न लागतों और क्षमताओं का किस प्रकार से विभाजन किया गया है। मै. अपार कैमिकल को उनकी क्षति रहित कीमत के लिए एन बी आर को बनाने और बेचने हेतु ब्याज लागत की पुनर्गणना की जानी चाहिए क्योंकि यह मात्र 3.85% ही बनती है। प्राधिकारी को अपार के द्वारा निर्मित एन बी आर के लिए एन आई पी का निर्धारण सिद्धांत को समान रूप से लागू करते हुए उनकी उत्पादन लागत में 5% लाभ को जोड़कर करना चाहिए।
- iii) पी ओ आई समीक्षा में अपार द्वारा लाई गई ए एन बी 35 एल के नवीन ग्रेड के कीमत आकड़ों को अपार की बिक्री कीमत के विश्लेषण से बाहर रखना चाहिए।
- iv) अपार ने अनुचित ढंग से यह अनुरोध किया है कि उन्हें अपने एन बी आर संबंधी प्रचालनों से कोई लाभ नहीं हो रहा है और उन्होंने तथ्यों को छुपाया है तथा उनके पास क्षति को कोई साक्ष्य नहीं है।
- v) मै. के के पी सी ने मै. अपार इंडस्ट्री के लिए एन आई पी के निर्धारण हेतु प्रणाली का भी सुझाव दिया है।
- vi) मै. अपार ने डी जी सी आई एंड एस तथा पी पी आर से आयात आकड़ों के संबंध में विभिन्न शासकीय आकड़े दिए हैं हम प्राधिकारी से अंतिम जांच के प्रकाशन के समय विषय वस्तु पर स्पष्ट जांच परिणाम देने का आग्रह करते हैं ताकि विश्लेषण का आधार विचलित न हो तथा एक सुसंगत प्रक्रिया का पालन किया जाए यद्यपि चाहे यह पूरा भी न हो।

#### घ. अन्य मुद्दे

- i) आयातक ने उल्लेख किया है कि सार्वजनिक सुनवाई करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है क्योंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी सुनवाई के दौरान उपलब्ध नहीं थे और बैठक में देरी की गई थी। प्राधिकारी ने किसी पक्ष के हलावा कहा है। कि कोई भी जो प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट न हो सीगेट या उच्च न्यायालय जा सकता है। मै. ऋषिरूप पोलीमर्स प्रा. लि. जो मै. के के पी सी का प्रतिनिधित्व कर रही थी इस मामले से संबंधित डब्ल्यू टी ओ के अनुच्छेद 6.0 का हवाला दिया है।
- ii) यह जांच परिणाम जनवरी 2002 के अंत तक पूरे कर दिए जाने चाहिए।

- iii) 2006 तक सभी ग्रेडों के लिए एन बी आर मांग लगभग 17336 मी.टन प्रतिवर्ष हो जाएगी तथा भारत में एन बी आर के लिए मांग आपूर्ति अंतर उत्पन्न होने वाला है ।
- iv) भारतीय कानून में किसी भी निर्णायक प्राधिकारी के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जिसके तहत भारतीय रुपए के अलावा किसी अन्य मुद्रा में पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए और इसलिए पाटनरोधी शुल्क की लेवी को डालर के रूप में इंगित नहीं किया जाना चाहिए ।

### प्रकटन विवरण के उत्तर में, मै. के के पी सी द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं

#### प्रारंभिक आपत्तियां

- प्रकटन विवरण निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है और इस प्रकार यह वैध नहीं है पाटनरोधी नियमों के नियम 16 तथा डब्ल्यू टी ओ के अनुच्छेद 6.9 तथा मामले से संबद्ध कानूनों का उल्लेख किया गया है ।
- विभाग द्वारा जारी व्यापार सूचना 1/99 के उल्लंघन संबंधी निर्णायक समीक्षा शुरुआत कानून अमान्य है क्योंकि वर्तमान मामले में पहले ही एक समीक्षा दिनांक 20.7. 2001 को समाप्त हो जिसके तहत दिनांक 7.9.2001 को एक राजस्व अधिसूचना जारी की गई थी तथा निर्णायक समीक्षा की शुरुआत 1.10.2001 को अर्थात् एक वर्ष की समयावधि के भीतर की गई है । निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस आवश्यकता की जानकारी होनी चाहिए तथा उन्हें शीर्ष न्यायालय द्वारा उल्लेख किए गए अनेक कानूनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए ।
- सार्वजनिक सुनवाई में निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचार पक्षपातपूर्ण तथा सार्वजनिक सुनवाई की कार्यवाही अनुचित थी क्योंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी का पूर्व निर्णित इरादा था तथा उन्होंने निर्यातकों से 2 को कीमत आश्वासन देने के लिए कहा । यह भी डब्ल्यू टी ओ के अनुच्छेद 8.2 का उल्लंघन था ।
- के के पी सी ने कहा है कि यह विचार की मौखिक अनुरोध के पश्चात लिखित अनुरोध देने होंगे यह संकेत देता है कि मौखिक साक्ष्य प्रतिस्थानीय है जोकि उचित नहीं है ।

— इस संबंध में अनुच्छेद 6.2 और नियम (6) के उप नियम (6) का उल्लंघन किया गया है ।

#### विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु

- विचाराधीन उत्पाद के संदर्भ में, इस विषय वस्तु पर निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन है तथा हमारी अपील न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई है और यह मामला सुनवाई के लिए लंबित है । यह घरेलू उद्योग के बारे में बतायी गई स्थिति है कि वे कार्बोक्सीलेटेड एन बी आर का उत्पादन नहीं करते हैं और निर्दिष्ट प्राधिकारी अभी भी उस पर पाटन रोधी शुल्क की लेवी जारी कर रखना चाहते हैं । इसके लिए कोई औचित्य प्रतिपादन नहीं दिया गया है । प्राधिकारी के पास उत्पादों की एक विशिष्ट श्रेणी पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के समस्त अधिकार है क्योंकि मौलिक जांच दी गई अतिरिक्त सूचना के पर आधारित थी । चूंकि अपार कार्बोक्सी लेटेड एन बी आर का उत्पादन नहीं करते हैं हम प्राधिकारी से आग्रह करते हैं कि वे शुल्क की लेवी के लिए एन बी आर के उत्पादों की श्रेणी के परिसीमान के द्वारा उन्हें भविष्य में किसी भी पाटनरोधी शुल्क की लेवी के बाहर रखे । यह एस बी

आर पाटनरोधी जांच मामले में प्राधिकारी के स्वयं के निर्णय के समनुरूप होगा जिसमें पी ओ आई के दौरान एस बी आर की ग्रेडों जिनका भारत में उत्पादन नहीं किया जाता के लिए प्राधिकारी ने यह निर्णय दिया था कि पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाएगा । कार्बोक्सीलेटेड एन बी आर के वर्तमान मामले में भी इसी का पालन किया जाना चाहिए ।

### सामान्य मूल्य

#### के के पी सी के एन बी आर की उत्पादन लागत

- प्राधिकारी ने अनुपयुक्त रूप से बिक्री लागतों तथा विनिर्मित वस्तुओं को लागतों के आबंटन तथा विभाजन के आधार के रूप में चुना है । के के पी सी प्रकटन से अभिज्ञात करते हैं कि प्राधिकारी ने उत्पादन लागत तथा ब्याज हेतु व्ययों का आबंटन और बिक्री लागतों के अनुपात पर आधारित एस जी ए का निर्धारण करने का निर्णय लिया है के के पी सी को यह स्वीकार नहीं है के के पी सी को यह स्वीकार लागत आबंटन तथा संविभाजन का आधार कोरयाई जी ए ए पी कानून के अनुसार है, तथा इसके अलावा, के के पी सी द्वारा लागत आबंटन का इस आधार का पालन के के पी सी द्वारा सुसंगत रूप से किया जा रहा है और एन बी आर के लिए पूर्ववर्ती जांच (1997- में आरंभ ) तथा एस बी आर पाटन रोधी जांच में प्राधिकारी ने इसे पहले स्वीकार किया है । डब्ल्यू टी ओ का अनुच्छेद 2.2.1 तथा नियम 1 का उल्लेख किया गया है ।

• प्राधिकारी को केकेपीसी की लागत आबंटन संबंधी प्रणाली को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि यह उनके द्वारा रखे गए रिकार्ड पर आधारित है और जिसे वे कई वर्षों से लगातार अपना रहे हैं तथा यह कोरिया में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार है । ये रिकार्ड भी जांचाधीन वस्तुओंका उत्पादन और बिक्री के साथ लागत के जुड़े होने की युक्तिसंगतता को प्रदर्शित करते हैं । विभाग के अधिकारी जिन्होंने सत्यापन के लिए केकेपीसी के कार्यालय के दौरे किए थे ने बताया है कि व्यापारिक तथा माँग पर बिक्रियों के लिए एसजीए को घटाने के बाद कमपनी द्वारा बनाए गए सभी उत्पादों की कुल मात्रा का उत्पादित एनबीआर की मात्रा के अनुपात पर आधारित लागत आबंटन के लिए केकेपीसी की प्रणाली एक मद नामतः स्टीम के लिए समुचित नहीं है, इसकी बिक्री कीमत के लिए एसजीए लागत आनुपातिक नहीं हैं । मामला ऐसा प्रतीत होता है लेकिन यह केकेपीसी द्वारा अपनाई गई एक नीति है और केकेपीसी लम्बे समय से लागत आबंटन प्रणाली को अनवरत अपना रहा है । यह केकेपीसी के लागत आबंटन की प्रणाली को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं हो सकता क्योंकि यह कारियाई मानकों में स्वीकृत है ।

- प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई लागत आबंटन प्रणाली के प्रति हमारी आपत्ति के होते हुए भी हम केवल तर्क के लिए और पूर्वाग्रह के बिना निम्नलिखित अनुरोध करते हैं :-

(क) प्राधिकारी ने व्यापारिक बिक्रियों और माग पर बिक्रियों के लिए किसी एसजीए लागत का आबंटन नहीं किया है।

(ख) केकेपीसी ने प्राधिकारी से एनबीआर उत्पादन की किसी लागत का संविभाजन करने से पहले \*\*\* बोन पर व्यापारिक बिक्रियों के लिए एसजीए खर्चों और \*\*\* बोन पर माँग पर बिक्रियों के खर्चों के लिए संविभाजन की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

(ग) केकेपीसी विज्ञापन खर्चों, कमीशन तथा आर एण्ड डी लागत की अनुमति न दिए जाने पर सहमत नहीं है। इसे यह प्रदर्शित करते हुए सविस्तार बताया गया है, कि कमीशन खर्चों के लिए वस्तुतः प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया है। इसका कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। इस समायोजन का वैधानिक ढंग से दावा किया गया है क्योंकि यदि इसे एसजीए खर्चों में से नहीं घटाया गया तो इससे लेखाकरण का कार्य दो गुणा हो जाएगा क्योंकि भारत को एनबीआर की बिक्री की सीआईएफ कीमत से इसका निर्धारण करते समय इसे कारखाना के बाद स्तर पर अलग से विचार किया जाता है।

(घ) केकेपीसी ने प्राधिकारी को भेजे अपने पहले के पत्र में यह अनुरोध किया है कि उसने जांच अवधि के दौरान अपने किसी उत्पाद के लिए भारत में विज्ञापन के लिए कोई खर्च नहीं किए हैं जांच अवधि के दौरान केकेपीसी द्वारा किए गए विज्ञापन संबंधी खर्च जो एसजीए सूची में दिए गए हैं वे घरेलू बाजार में बिक्री संबंधन के लिए ही हैं और भारत को एनबीआर के निर्यात बिक्रियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। केकेपीसी द्वारा उत्पादित एनबीआर का भारत को निर्यात के लिए घरेलू बिक्रियों हेतु लागत के बीच कारखानागत स्तर पर कीमत की तुलना वास्तविक और मदवार आधार पर करने के उद्देश्य से विज्ञापन खर्चों संबंधी इस समायोजन की प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए।

(ङ.) आर एण्ड डी खर्चों के संबंध में केकेपीसी ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी को केएनईएसएल केन्द्र जहां केवल जीव विज्ञान पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है और जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वहां केकेपीसी के सिंथेटिक रबड़ के किसी व्यापार का कोई सह-संबंध नहीं है, के लिए कम से कम 50% के आर एण्ड डी खर्च की अनुमति देने पर विचार करना चाहिए।

(च) कैप्टिव रूप से उत्पादित और खपत की गई बीडी के लिए कीमत अन्तरण का मूल्यांकन सही नहीं है। केकेपीसी ने अपने कैप्टिव रूप से खपत वाले सभी उत्पाद के मूल्यांकन की पद्धति को कारखानागत उत्पादन लागत पर अनवरत अपनाया है न कि बिक्री लागत पर। यह पद्धति कोरियाई जीएएपी कानूनों के अनुसार है और यह स्वयं भारत सरकार द्वारा अपनाए गए भारतीय लागत नियमों के अनुसार भी है। कम्पनी अधिनियम की धारा 209 का उल्लेख किया गया है।

(छ) प्रचालन के लिए ब्याज लागत के आबंटन हेतु प्राधिकारी द्वारा लगाई गई संपत्ति के 55.65% का अनुपात लिया जाना सही नहीं है। केकेपीसी ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि उत्पादन कार्यकलापों के लिए 46.5% का केकेपीसी के आबंटन के बजाए उत्पादन कार्यकलापों के लिए लगाई गई निधि के 55.65 % के आबंटन के अपने निर्णय पर विचार किया जाए।

(ज) केकेपीसी द्वारा उत्पादित एनबीआरके उत्पादन की लागत का मूल्यांकन गलत है। केकेपीसी ने 977.53 अमरीकी डालर प्र. मी० टन पर उत्पादन की कारखानागत लागत प्रदर्शित करने वाले आंकड़े प्रस्तुत किए थे। इसकी तुलना में प्राधिकारी ने कच्ची सामग्री की लागत (बीडी हस्तांतरण कीमत) ब्याज लागत और एसजीए लागतों से उत्पन्न प्रमुख अन्तर के आधार पर उत्पादन की लागत 1079.39 अमरीकी डालर प्र. मी० टन निकाली है। इस प्रकार प्राधिकारी ने 101.86 अमरीकी डालर प्र. मी. टन तक उत्पादन की लागत को बढ़ा दिया है। प्राधिकारी ने अपनी प्रणाली को इनकी कुछ घरेलू बिक्रियों को छोड़ने के लिए नियत नहीं किया है। इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ऐसे मामलों में प्राधिकारी को कीमत में उत्पादन की निर्धारित औसत लागत से कम के कुछ अन्तर की अनुमति देते समय एक निश्चित कीमत पर विचार करना अपेक्षित है। इस बारे में हम प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का विरोध करते हैं और इस पर पुनः विचार करने का अनुरोध करते हैं।

(झ) केकेपीसी का एनबीआर की बिक्रियों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण सही नहीं है। उक्त आंकड़ों की निकट बढ़ती कीमत भिन्नता संबंधी सीमा की व्यवस्था किए बिना प्राधिकारी ने घरेलू बिक्रियों में कतिपय, बिक्री सौदों को छोड़ने के लिए उस स्थिति में अनुचित निर्धारित स्तर अपनाया है।

#### सामान्य मूल्य के निर्धारण को शासित करने वाले सिद्धांत

- सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए तदनुसूचीक डब्ल्यूटीओ नियम अनुच्छेद सं. 2.2.1 का भी उल्लेख किया जाता है।
- गोपनीय प्रकटन में प्राधिकारी कमीशन के समायोजन के बारे में मूक है लेकिन व्याख्या करने पर हम अनुमान लगा रहे हैं कि प्राधिकारी समायोजनों में इसे शामिल करना भूल गए। कृपया



इसकी भी पुष्टि की जाए। प्राधिकारी ने भारत को बिक्रियों के लिए व्यापार के स्तर में किसी समायोजनों की अनुमति नहीं दी है। क्योंकि वह इसे सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए संगत नहीं समझते हैं परन्तु क्षति निर्धारण के लिए उचित है।

- केकेपीसी ने अनुरोध किया है कि 1.7 अमरीकी डालर/मी० टन के झा बैक शुल्क का समायोजन उत्पादन की लागत और घरेलू कारखानागत बिक्री कीमत पर की जानी चाहिए न कि कारखानागत निर्यात कीमत पर क्योंकि मदवार तुलना उपलब्ध करने के लिए घरेलू बिक्रियों के लिए खपत की गई कच्ची सामग्री की लागत है जिसे 1.7 अमरीकी डालर/मी० टन कम किया जाना अपेक्षित है और न कि उत्पादन पश्चात लागत को जैसा कि प्राधिकारी द्वारा समायोजन किया गया है।

### अपार के लिए क्षति निर्धारण

- प्राधिकारी ने नियमों के तहत यथा अपेक्षित आकलित आर्थिक मापदण्डों के अपने निर्धारण को सूची रूप में उदघाटित नहीं किया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों से सूची के उद्धरण को अथवा अन्यथा पिछले वर्षों की तुलना में जांच अवधि के लिए घरेलू उद्योग के लिए सभी आर्थिक कारकों पर अपने विचारों को सामान्य रूप से प्रकाशित किया है। केकेपीसी से आयातों के इतर कारक जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं या जिसके कारण क्षति हो सकती है के निर्धारण के लिए प्राधिकारी द्वारा अलग से आकलन करना अपेक्षित है।

### क्षति के निर्धारण के लिए सिद्धांत (अनुबंध-II)

- नियम (v) और अनुच्छेद 3.5 का उल्लेख किया जाता है
- यह दोहराया जाता है कि केकेपीसी से एनबीआर के आयातों के अलावा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के कुछ मुख्य कारक यदि कोई हों, निम्नानुसार हैं :-
  1. अन्य देशों से आयातों के साथ-साथ जापान, ताइवान इत्यादि जैसे देशों से हो रहे आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जा रहा है।
  2. जिन देशों पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया गया है, उन देशों से केकेपीसी के समान कीमत स्तर पर आयात।
  3. मूल जांच अवधि से सनसेट समीक्षा जांच अवधि तक सीमाशुल्क में महत्वपूर्ण कमी जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं की पहुँच मूल्य में महत्वपूर्ण कमी आना।
  4. सभी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों की तुलना में घरेलू उद्योग की कम प्रचलनात्मक क्षमता।
  5. बीडी की लागत बढ़ाकर संयंत्र स्थल का उपयुक्त स्थान पर न होना।

हम प्राधिकारी से केकेपीसी से आयातों के अलावा अन्य कारकों जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं अथवा क्षति पहुँचा सकते हैं के आधार पर उपरोक्त शासित करने वाले नियमों के अनुसार अलग और सुस्पष्ट परिमाणिक जांच परिणाम निकालने का अनुरोध करते हैं।

- कारणा एवं अनधिरूपण - डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 3.5 का अनुपालन अपेक्षित है, डब्ल्यूटीओ निर्णीत मामलों का उल्लेख किया जाता है।
- अपने इस अनुरोध के समर्थन में कि केकेपीसी से हुए आयातों और घरेलू उद्योग को कथित क्षति, यदि कोई हो के बीच किसी कारणात्मक संबंध का अभाव है, समुचित विचार करने के लिए केकेपीसी के निर्यातों और निर्दिष्ट प्राधिकारी के कारकों के अनुसार हुई क्षति को दर्शाने वाली गणना की गई है।
- क्षति के निर्धारण हेतु मूल जांच अवधि के लिए सीमाशुल्क में अन्तर के लिए समायोजन के बिना सीमा शुल्क सहित पहुँच मूल्य की अवधारणा को लागू करना कानून अवैध है। सीमा शुल्क में गिरावट के कारण क्षति संबंधी प्रभाव का अनुरोध किया गया है।

### वास्तविक क्षति का निर्धारण

- पाटनरोधी जांच को शासित करने वाले भारतीय नियमों में प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वह क्षति संबंधी जांच परिणाम पर पहुँचने की स्थिति में ही किसी पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करे। संगत धारा 9ख, 11(2) तथा नियमों को उल्लेख किया गया है।
- अपने विभिन्न अनुरोधों के दौरान हमने प्राधिकारी को स्पष्टतः यह दिखलाया है कि जांच अवधि के लिए क्षति निर्धारण के लिए मूल्यांकन हेतु आवश्यक सभी आर्थिक मापदंड जांच अवधि में एपीएआर के लिए सकारात्मक हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी के पास सर्फ एक मुद्दा लाभप्रदता के पहलू का है। हम प्राधिकारी को यह याद दिलाना चाहेंगे कि उसे सिर्फ "व्यापार विकृति" पर ही उसी हद तक कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है तथा वह किसी घरेलू उद्योग को "व्यापार सुरक्षा" या "लाभ के आश्वासनों" हेतु फोरम नहीं है।

### व्यापार स्तर/बिक्री/करों की शर्तों में अन्तर हेतु समायोजन

- हमने प्राधिकारी से आयातित वस्तुओं की अंतिम उपयोक्ता के लिए कीमत का घरेलू उद्योग की कीमत से उचित तुलना करने के लिए भारतीय ग्राहकों के लिए केकेपीसी की बिक्री तथा अपार की अपने ग्राहकों को बिक्री के बीच व्यापार स्तर में अन्तर हेतु उचित समायोजन करने का अनुरोध किया था। हमने प्राधिकारी से उक्त समायोजन का अनुरोध क्षति मार्जिन का आकलन करने तथा तथा कथित कीमत ह्रास के प्रभाव का आकलन करने के लिए किया है।
- उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, हम प्राधिकारी से इस समायोजन को मंजूरी प्रदान करने तथा ग्राहकों के लिए आपूर्ति के माध्यम में मध्यवर्ती स्तर द्वारा ऐसी बिक्रियों के निवल प्रभाव को ध्यान में रखने का अनुरोध करते हैं। हम यह दोहराते हैं कि यह मदवार तुलना करने के लिए उचित होगा क्योंकि अपार अपना उत्पाद सीधे अंतिम प्रयोक्ता को बेचता है और यह अपने ग्राहकों से कोई

बिक्री कर नहीं लेता है क्योंकि उन्हें गुजरात सरकार से प्रोत्साहन मिलने के कारण वे वाणिज्यिक क्रियाकलाप के शुरू होने से 15 वर्ष के अवधि तक के लिए बिक्री कर से छूट मिली हुई है।

#### 4 % विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) हेतु समायोजन

- हम अनुरोध करते हैं कि हमने प्राधिकारी के पास केकेपीसी से एनबीआर के आयातकों द्वारा प्रदत्त 4% विशेष अतिरिक्त शुल्क का समायोजन करने का दावा किया है जिससे सामान्यतः घरेलू उत्पादकों और निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा के समान अवसर उपलब्ध होने का अनुमान है। तथापि, वर्तमान मामले में चूंकि ऊपर के पास अपनी बिक्रियों पर कोई बिक्री कर न देने का विशेष प्रोत्साहन है। इस लिए यह एसएडी कर एनबीआर की अपार की बिक्रियों की तुलना में एनबीआर के आयातकों को नुकसान की स्थिति में लाता है। डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.4 में "बिक्री की स्तरों में अंतर" हेतु समायोजन करने के लिए निम्नानुसार नियम है।"

उपभोक्तों और समुदाय के हित पर व्यापक रूप से विचार किया जाए।

- सांख्यिकी आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जाच अवधि के अंतिम भाग में एनबीआर की लगभग 13,000 से 14,000 मी० टन की अनुमानित घरेलू मांग की तुलना में अपार ने केवल लगभग 5100 मी० टन की बिक्री की है। जो बाजार का लगभग 40% अथवा इसके आस-पास है। अतः लगभग 60% अंतिम प्रयोक्ताओं को एक अथवा दूसरे स्रोत से अपने आयातों के लिए पाटनरोधी शुल्क अदा करने के लिए बाध्य किया गया। अपार अपनी उत्पादन क्षमता के लगभग 115% का प्रचालन कर रहा है। इसलिए प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्क की लेवी का कोई सकारात्मक निर्धारण करते समय समुदाय के व्यापक हित को ध्यान में रखना चाहिए। अमरीकी डालर के संबंध में किसी पाटनरोधी शुल्क की लेवी अवैध है।
- हमारा अनुरोध है कि किसी विदेशी मुद्रा जैसे कि अमरीकी डालर के आधार पर किसी पाटनरोधी शुल्क की लेवी कानूनन नहीं है। इस मामले को हमारे द्वारा एक अपील में उठाया जा चुका है जो माननीय उच्चतम न्यायालय के पास लंबित है और हम यहां उसका उल्लेख नहीं करते हैं।

#### 2. हुंडई पेट्रोकेमिकल्स के लिए

क पाटन

- (i) हम अपने पिछले अनुभव के आधार पर निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत न करने का निर्णय लेते हैं।

(ii). कोरिया में एनबीआर के केवल दो निर्यातक अर्थात् केकेपीसी और हुंडई पेट्रोकेमिकल्स लि० हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा 17 जुलाई 1997 को अपने अंतिम जांच परिणाम प्रकाशित किए

जाने से पूर्व हमने प्राधिकारी से यह अनुरोध किया था कि हमने एनबीआर उत्पादन संयंत्र अक्टूबर, 1996 में शुरू किया है और हमने जांच की प्रथम आरंभिक अवधि के दौरान न तो कोई उत्पादन किया है और न ही भारत में एनबीआर की किसी मात्रा का निर्यात किया है।

(iii) प्राधिकारी को 30.12.1996 के प्रारंभिक जांच परिणामों और 17.7.1997 के अंतिम जांच परिणामों में भी इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए था कि जांच अवधि के दौरान कोरिया गणराज्य का केवल एक विनिर्माता अर्थात् केकेपीसी था। हमारे मौखिक और लिखित अनुरोधों के बावजूद प्राधिकारी 8975 रु० प्रति मी० टन की दर से पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। केकेपीसी द्वारा उत्पादित एनबीआर पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना चाहिए जबकि हुंडई पेट्रोकेमिकल को इस सधारण और स्पष्ट कारण से पाटनरोधी शुल्क के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए कि जांच अवधि के दौरान इसने किसी मात्रा का निर्यात नहीं किया है।

(iv) माननीय सीगेट ने 2.2.2000 के अपने आदेश के तहत शुल्क को संशोधित कर डालर के रूप में रखा है और प्राधिकारी को केवल केकेपीसी के लिए डालर के रूप में पाटनरोधी शुल्क संशोधित करना चाहिए। तथापि, हुंडई पेट्रोकेमिकल ने निर्दिष्ट प्राधिकारी की उपर्युक्त अधिसूचना और जांच परिणामों का विरोध नहीं किया।

(v) 20.7.2001 की अधिसूचना संख्या 27/1/2000-डीजीएडी के तहत की गई मध्यावधि समीक्षा के दौरान प्राधिकारी ने केकेपीसी के लिए पाटनरोधी शुल्क 264 डालर में प्रति मी० टन से घटाकर 248.35 डालर प्रति मी० टन कर दिया जबकि हमारे लिए पाटनरोधी शुल्क 26 डालर प्रति मी० टन से सर्वाधिक बढ़ाकर 679 डालर प्रति मी० टन की सिफारिश की। यह वृद्धि इस तथ्य के बावजूद की गई है कि हमने केकेपीसी से उच्चतर कीमत पर निर्यात किया है।

(vi) भारत को हमारे निर्यात कीमत नगण्य 600 मी० टन थी जो भारत में एनबीआर की कुल खपत के 10% से भी कम है।

(vii) मी० अपार हमलोगों के समतुल्य एनबीआर ग्रेडों का विनिर्माण नहीं करता है क्योंकि भारत में एनबीआर का प्रमुख उपयोग राइस रोल्स के उत्पादन के लिए होता है जिसकी मात्रा एनबीआर के उत्पादन के 50% से ज्यादा बनती है। हमारे एनबीआर का उपयोग राइस रोल्स में बिल्कुल नहीं होता है।

(viii) सनसेट समीक्षा के दौरान हमने एनबीआर के विभिन्न ग्रेडों की कुल 600 मी० टन की बिक्री की है। तथापि, हमने 679 डालर प्रति मी० टन/ मी० टन की उच्चतम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद कोई एनबीआर नहीं बेचा है।

(ix) अतः अनेक तथ्य तथा परिस्थितियां हम लोगों को यह विश्वास करने के लिए बाध्य करते हैं कि निर्धारित प्रपत्र में सूचना देने का कोई उपयोग नहीं है।

### 3. बेयर एजी, जर्मनी क क्षति

(i). बेयर से एनबीआर का आयात की मात्रा 1997 में 2034 से पर्याप्ततः घटकर जांच अवधि में 467 मी०टन हो गया है ।

(ii). जांच की प्रारम्भिक अवधि जसके लिए पाटन रोधी शुल्क लगाया गया था की तुलना में जांच की वर्तमान अवधि के दौरान हमारी और सीआईएफ की कीमत भी बढ़ी है ।

(iii). जांच की वर्तमान अवधि के दौरान, बेयर से एनबीआर की कीमत पाटनरोधी शुल्क पर विचार किए बिना घरेलू उद्योग की कारखानागत बिक्री कीमत से ज्यादा थी । बेयर एजी की निर्यात कीमत पर पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा के लिए प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य नहीं है बल्कि वर्तमान में लागू 110.64 डालर प्रति मी०टन के सम्पूर्ण शुल्क को हटाने की आवश्यकता है ।

(iv). घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग में अप्रैल 1994-95 में 34 प्रतिशत से पर्याप्ततः बढ़कर जांच अवधि में 84 प्रतिशत हो गया है । घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट से यह देखा जा सकता है कि 1994-95 और इसके आगे इसने लाभ अर्जित किया है जबकि वर्ष 2000-2001 में निवल घाटा हुआ है जो कड़ी स्पर्धा तथा कच्ची सामग्री की लागत तथा ब्याजों में असामान्य वृद्धि के कारण मार्जिन कम होने के कारण अस्थायी प्रतीत होता है । इसके अलावा, जांच अवधि में भी प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह सकारात्मक रहा था ।

(v) इन सभी तथ्यों पर विचार करते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि किस मात्रा तक एनबीआर के व्यापार ने उनके निष्पादन में योगदान कर सका है ।

### ग प्राधिकारी द्वारा जांच

विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए उपरोक्त अनुरोधों जिस सीमा तक में नियमों के अनुसार है तथा मामले पर प्रभाव डालते हैं, पर उस सीमा तक इन जांच परिणामों में उचित विचार किया गया है और इन में उचित स्थानों पर कार्रवाई की गयी है ।

### 1. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु एवं घरेलू उद्योग

प्राधिकारी विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1995 की धारा 9 क 5 के अनुसार की गई वर्तमान सनसेट समीक्षा वर्तमान में लागू पाटनरोधी शुल्क के संदर्भ में है जिसकी पहले दिनांक 30.12.96 के प्रारम्भिक जांच परिणामों द्वारा सिफारिश की गई थी तत्पश्चात् दिनांक 17.7.97 के अंतिम जांच परिणामों द्वारा पुष्टि की गई थी। पाटनरोधी शुल्क को मध्यावधि समीक्षा में दिनांक 7 सितम्बर, 2001 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं० 91/2001 द्वारा भी जारी रखा गया था तथा इस समय दिनांक 7.6.2002 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 61/2002 द्वारा लगाया गया था । प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की पुष्टि करने का प्रस्ताव किया था जैसाकि पूर्ववर्ती मुख्य जांच में नियत किया गया था ।

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि समान वस्तु के संबंध में कुछ हितबद्ध पार्टियों द्वारा तर्क दिये गये हैं जहां तक समान वस्तु तथा विचाराधीन उत्पाद में अदला बदली के क्षेत्र के साक्ष्य नहीं दिए गए हैं का सवाल है विचाराधीन उत्पाद एनबीआर के सभी ग्रेडों को कवर करने के लिए मुख्य जांच में पहले ही शामिल की जा चुका है। तथापि, मै. के.के.पी.सी. द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि कुछ वस्तुएं जैसे कार्बोअक्सीलेटेड ग्रेड का विनिर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है तथा वे छोड़े जा सकते हैं तथा यह मुद्दा न्यायालय के निर्णयाधीन भी है। तथापि, यह नोट किया गया है कि मै0 के.के.पी.सी. ने कार्बोग्लाइलेटेड ग्रेड का निर्यात नहीं किया है बल्कि सिर्फ के.एनबी 35 एल ग्रेड का निर्यात किया है जबकि कार्बोग्लाइलेटेड-ग्रेड के अपवर्जन का मांग किया है। प्राधिकारी ने इन संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं हेतु हाल के अपने सभी जांचों में जांच क्षेत्र के भीतर एनबीआर के सभी ग्रेडों पर विचार किया है और यह एक निर्णायक समीक्षा होने के कारण विचाराधीन उत्पाद को "एक्रिलोनिटाइराइल बूटाडीन रबड़ के रूप में जिसे नाइट्राइल रबड़ और एनबीआर के रूप में भी जाना जाता है जैसाकि दिनांक 30.12.1996 के ऑरिजनल फाइंडिंग में इंगित किया गया है, दुहराते हैं तथा पुनः पुष्टि करते हैं। एनबीआर मुख्य रूप से विभिन्न रबड़ की वस्तुओं, जैसे ऑयल सील्स, होजेज, आटोमोटिव प्रोडक्ट्स, गास्क्ट्स, राइस देहुस्किंग रोल्ल्स, प्रिंटर फैब्रिक्स, आयल फिल्ट्र प्रोडक्ट्स के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति विभिन्न प्रयोगकर्ताओं को राइस रोल्ल्स, मोल्डेड एंड एक्सट्रूडेड ऑटो एण्ड इंडस्ट्रीज पार्ट्स, सील्स, होंजे, आटोमोटिव कम्पोनेन्ट्स, आयल सीड्स, ओरिंग्स, आटोमोबाइल्स होजेज, बेलोज, फ्यूल ट्यूट्स, फ्यूल होजेज और रेलवे तथा रक्षा उत्पादों के उत्पादन हेतु करता है। प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद का स्मरण तथा उसकी पुष्टि करते हैं जैसाकि दिनांक 17.7.1997 के अंतिम जांच निष्कर्ष में पैरा एफ (4) और एफ (5) तथा प्रारंभिक जांच निष्कर्षों में पैरा ई(1) और ई(5) के तहत भी इंगित किया गया है।

जहां तक घरेलू उद्योग के विचार का संबंध है मै0 एपार इंडस्ट्रीज लि0 मुख्य उत्पादक है और पाटनरोधी नियमों के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। प्राधिकारी, इसलिए, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और समान वस्तु की पुनः पुष्टि करते हैं जैसाकि हाल ही मुख्य

जांच में इंगित है और पाते हैं कि दक्षिण कोरिया और जर्मनी से निर्यातित वस्तुएं नियम 2(घ) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तुओं के समान वस्तु हैं।

## 2. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पाटन मार्जिन, सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत

क. मै0 कोरिया कुम्हों पेट्रोकेमिकल्स कं. लि. (के.के.पी.सी.)

### सामान्य मूल्य

प्राधिकारी प्रकटन विवरण में अपने प्रेक्षकों का स्मरण करते हैं और दोहराते हैं कि जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में बेचे गए विभिन्न ग्रेड के एनबीआर के उनके उत्पादन लागत के परिकलन के विभिन्न पहलुओं पर मै. के.के.पी.सी. द्वारा दिए गए तर्क/निवेदन पर उचित तरीके से

विचार किया गया है। दिनांक 23-24 अगस्त, 2002 को मौके पर की गई जांच के दौरान प्रस्तुत निवेदन/आंकड़ों और प्रश्नावली के उनके मुख्य/पूरक उत्तर में उनके द्वारा किए गए अनुरोध तथा जांच के अनुवर्ती में उनके द्वारा निदेशालय को प्रस्तावित स्पष्टीकरणों पर उचित रूप से विचार किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन आधार पर विभाजन के संबंध में एसजीए का दावा तथा निर्यातक का हित तर्कसंगत तथा तार्किक प्रतीत नहीं होता है। यदि कम्पनी प्रति यूनिट लागत तथा बिक्री प्राप्ति में विस्तृत रूपान्तर के साथ विजातीय उत्पादों का उत्पादन कर रहा हो तो ऐसे विभाजन से संबंधित लागत सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए। इस प्रकार प्राधिकारी प्रकटन विवरण में बिक्रियों के लागत के आधार पर इन लागतों के विभाजन का प्रस्ताव किया।

आर एंड डी खर्चों के संबंध में प्राधिकारी मौके पर जांच के दौरान उपलब्ध कराई गई कम्पनी के साहित्य/विवरणिका से नोट करते हैं कि आर एंड डी कार्य कलाप एनबीआर समेत सभी उत्पादकों के लिए संगत हैं। इसके अतिरिक्त एनबीआर के ग्रेड-वाइज उत्पादन लागत के विवरण से यह मालूम होता है कि कम्पनी ने एनबीआर पर आर एंड डी खर्चों की बड़ी राशि का भी वहन किया है। इस प्रकार इन पर एसजीए खर्चों के हिस्से के रूप में विचार किया गया है। अशोध्य ऋणों के अपवर्जन संबंध में प्राधिकारी द्वारा विचार किए जाने हेतु दावे का प्रस्ताव किया गया था क्योंकि यह एनबीआर से संबंधित नहीं है। इसी प्रकार, अमूर्त परिसम्पत्तियों के परिशोधन के संबंध में प्राधिकारी द्वारा विचार किए जाने हेतु दावे का भी प्रस्ताव किया गया था जैसा कि ऊपर अशोध्य ऋणों के लिए किया गया था।

विज्ञापन खर्चों के संबंध में, प्रकट विवरण में यह वर्णित किया गया था कि, निर्यातक विज्ञापन से संबंधित खर्चों के अपवर्जन हेतु अपने दावे को प्रामाणित करने में समर्थ नहीं हुए हैं। अतः प्राधिकारी द्वारा विचार करने हेतु उसका प्रस्ताव नहीं किया गया था।

ब्याज खर्चों के संबंध में, निर्यात के निवेश कार्यकलापों से संबंधित निधियों को वर्जित करते हुए उत्पादन क्रिया-कलाप हेतु उपलब्ध निधियों की प्रतिशतता परिकलित की है। उत्पादन कार्य-कलापों के लिए लागू-निधियों का निर्यातक के \*\*\* % दावों के विरुद्ध, प्राधिकारी ने गैर-उत्पादन कार्य-कलापों में किए गए निवेशों पर विचार करने के पश्चात् इसे \*\*\* % निर्धारित किया है। उत्पादन कार्य-कलापों के लिए ब्याज के आबंटन हेतु, ब्याज आय का निष्कर्ष निकालने के पश्चात् निर्यातक ने निवल व ब्याज लागत पर विचार किया है। इस दावे को विचार करने हेतु प्रस्तावित किया जाना इंगित किया गया था क्योंकि ब्याज आय कम्पनी के निवेश कार्य-कलापों से संबंधित है कि उत्पादन कार्य कलाप से। एसजीए हेतु परिकलित कुल राशि तथा ब्याज का बिक्रियों की लागत के आधार पर भिन्न-भिन्न उत्पादों के लिए आबंटन किया गया है। यह पाया गया है कि आबद्ध रूप से उत्पादित और आबद्ध रूप से प्रयुक्त बूटाडीन की अंतरण कीमत में एसजीए एकल ब्याज के प्रभाव को हिसाब में नहीं लिया जाता है यद्यपि एसजीए एवं ब्याज के आबंटन के लिए उत्पादन संबंधी विभिन्न कार्यकलापों पर लागू होने वाले हिस्से की गणना करने के लिए बूटाडीन से संबंधित बिक्री की लागत के प्रभाव पर मूल्य वर्ग में विचार किया गया है। तदनुसार एनबीआर के उत्पादन में आबद्ध रूप से उत्पादित तथा प्रयुक्त बूटाडीन के खपत कारक के आधार पर, एसजीए तथा ब्याज का प्रभाव पर भली-भांति विचार करने हेतु प्रस्ताव किया गया था। प्राधिकारी ने नोट किया था कि

सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु निर्यातक ने सभी ग्रेडों के अधिमानित औसत घरेलू बिक्री कीमत उपलब्ध कराया है। उत्पादन लागत भी निर्यातक द्वारा सभी ग्रेडों हेतु अधिप्रमाणित औसत कारखाना-द्वार के आधार पर उपलब्ध कराया गया है। जांच दल द्वारा निर्यातक की मौके पर जांच के दौरान यह देखा गया था कि विभिन्न ग्रेडों हेतु उत्पादन लागत में विभेद का संकीर्ण बैंड है और यह ध्यान में रखते हुए कि यह एक निर्णायक समीक्षा है, भारत औसत से भारत औसत ग्रेड तुलना पद्धति जैसाकि हाल में किया गया था, की पद्धति का सामान्य मूल्य, उत्पादन लागत भारत को निर्यात कीमत के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ ग्रहण किए जाने हेतु दर्शाया गया था।

घरेलू बिक्रियों हेतु सामान्य मूल्य का मूल्यांकन करने के क्रम में, प्राधिकारी ने जैसाकि उपर पैरा में दर्शाया गया है अधिमानित औसत उत्पादन लागत का मूल्यांकन करने के पश्चात वैसे सभी लेन-देन जो कि व्यापार की सामान्य अवस्था में नहीं किए गए हैं को वर्जित रखा था। ऐसे लेन-देन को वर्जित करने के पश्चात पीओआई के दौरान अधिमानित औसत मूल्य \*\*\*\* डालर/एमटी दर्शाया गया था।

प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का संदर्भ \*\*\*\* डालर/एमटी के रूप में प्रस्तावित किया था। गोपनीय प्रकटन विवरण निर्यातक को उपलब्ध कराया गया था।

### निर्यात कीमत

कारखाना-द्वार निर्यात कीमत के मूल्यांकन के संबंध में, प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय भाड़े, पैकिंग, एजेंट को कमीशन अर्थात् मै0, ऋषिरूप पोलिमर प्रा0 लि0 तथा ड्यूटी ड्रॉबैक पर किए गए समायोजनों पर विचार करने का प्रस्ताव किया। तथापि प्राधिकारी ने नोट किया कि भारत को निर्यातों पर दावा किए गए अंतर्देशीय भाड़े के मामले में, कुछ निर्यात दूसरे बंदरगाह अर्थात् बुसन बंदरगाह से भी किए गए थे जैसाकि निर्यातक द्वारा मौके पर जांच के दौरान जांच दल को दर्शाया गया था। तदनुसार, अंतर्देशीय भाड़े को \*\*\*\* डालर/एमटी के रूप में विचार करने का प्रस्ताव किया गया है।

निर्यातक ने घरेलू बाजार में अपने व्यापार के स्तर तथा भारत को किए गए निर्यातों हेतु समायोजनों का दावा किया था। तथापि, मौके पर जांच के दौरान निर्यातक ने अपने दावे का फैंसला किया है जहां तक घरेलू बाजार में व्यापार का स्तर और भारत को किए गए निर्यातों का संबंध है क्योंकि घरेलू बाजार बिक्रियां वास्तविक प्रयोक्ता तथा वितरकों/विक्रेताओं को भी की गई थीं। तथापि, उन्होंने अब प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा भारत के थोक बिक्रेताओं को किए गए निर्यातों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग द्वारा की गई बिक्रिया जो कि अंतिम प्रयोक्ता स्तर की है, समान नहीं है, उन्होंने व्यापार के इस स्तर के लिए समायोजन की मात्रा नियम की है। प्राधिकारी ने इंगित किया था कि चूंकि घरेलू बाजार तथा निर्यात बाजार में व्यापार समायोजनों के स्तर का दावा नहीं किया गया है और साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है इसलिए सामान्य मूल्य के उद्देश्य हेतु इस समायोजन पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता है। भारत को निर्यातों के लिए व्यापार के स्तर पर उनके दावे के संबंध में यह इंगित किया गया था कि इसकी जांच सिर्फ



पाटनरोध् नियमों के अनुसार क्षति निर्धारण तथा प्राधिकारी द्वारा औद्योगिकीय उत्पादों के क्षति मूल्यांकन हेतु अनुसरण किए गए नियमित अभ्यास के प्रयोजनार्थ की जा सकती है।

पैकिंग पर समायोजनों के संबंध में, प्राधिकारी ने इंगित किया कि भारत को निर्यातों के लिए दावा किए गए पैकिंग लागत तथा घरेलू बिक्रियां और अन्य देशों को निर्यात हेतु दावा किए गए पैकिंग लागत की राशि में भिन्नता है। भारत को घरेलू तथा निर्यात बिक्री हेतु दो भिन्न प्रकार अर्थात् बक्सा तथा थैला पैसी पैकिंग का प्रयोग किया गया है। प्राधिकारी ने मोकें पर जांच के दौरान निर्यातक द्वारा जुटाये गए साक्ष्य के आधार पर भारत को निर्यातों के पैकिंग खर्च पर विचार किया है जैसाकि प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर दावा किया गया। तथापि पैकिंग खर्च का लाभ एवं हानि लेखे के साथ शामिल करने के पश्चात् समायोजनों पर \*\*\*\* डालर/मी०टन की सीमा तक विचार किया गया है, जहां तक घरेलू बिक्रियों की पैकेजिंग का संबंध है इसे निर्यातको को गोपनीय प्रकटन विवरण में इंगित किया गया था।

उपरोक्त के आधार पर, कारखानागत द्वार पर निर्यात कीमत को \*\*\*\*डालर/मी०टन के रूप में तथा पाटन मार्जिन को 10.6% (\*\*\*\* डालर/मी०टन) के रूप में इंगित किया गया था।

मै० केकेपीसी के प्रतिनिधि द्वारा प्रकटन के अनुवर्ती में प्रस्तावित टिप्पणियों के संबंध में प्राधिकारी ने सावधानीपूर्वक उसकी जांच निम्नानुसार की है:-

1. निर्यातक का यह तर्क कि वे ऐतिहासिक रूप से एसजीए के आबंटन हेतु आधार का प्रयोग कर रहे हैं तथा मात्रा आधार पर ब्याज को मूल अभिलेखों से जांच प्रक्रिया के दौरान केकेपीसी द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सका क्योंकि वे सिर्फ बिक्री की लागत तक उत्पाद-वार लागत का हिसाब करते हैं तथा उसके बाद का हिसाब नहीं रखते हैं।

सत्यापन की कार्यवाई के दौरान के के पी सी को यह विधिवत स्पष्ट कर दिया गया था कि उत्पादित एनबीआर की मात्रा और सभ् उत्पादकों की कुल मात्रा के अनुपात के आधार पर लागत आबंटन की पद्धति अनुचित है कि एक मद अर्थात् स्टीम की एस जी ए लागत और बिक्री कीमत या लागत में असामनता है। निर्यातक ने प्रकटन विवरण के अपने उत्तर में इस तर्क पर सहमति व्यक्त की है। मात्रा के संबंध में स्टीम का हिस्सा कुल उत्पादन के 70 % से अधिक बनता है जबकि बिक्री के संबंध में यह लगभग 7 % ही है। एसजीए तथा ब्याज के आबंटन हेतु मात्रा के अनुसार स्टीम और अन्य उत्पादों की बराबरी करना उचित नहीं है। तदनुसार बिक्री लागत के आधार पर एस जी ए एवं ब्याज के लागत अनुपात को उचित समझा गया था और उसे ही प्राधिकारी ने अपनाया है।

2. निर्यातक ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उन विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के लिए मांग पत्र पर बिक्री और व्यापारगत बिक्री, जिनसे उसने मांग-पत्र प्राप्त किया है अथवा बिक्री कमीशन का प्रस्ताव किया है, को केकेपीसी की लेखा बहियों में प्रदर्शित नहीं किया गया है। तदनुसार, बिक्री मूल्य के आधार पर बिक्री मूल्य से एसजीए का आकलन नहीं होता है। इसके अलावा, बिक्री मूल्य से खासकर एनबीआर के मामले में, जिसके बारे में निर्यातक द्वारा पाटन किए जाने का दावा किया गया है, सही और उचित मूल्य का पता नहीं चलता है। अतः वर्तमान परिस्थितियों में प्राधिकारी ने बिक्री लागत को एसजीए एवं ब्याज के अनुपात/आबंटन का सर्वाधिक उचित आधार माना है। इस तर्क की जांच की गई है कि प्राधिकारी ने निबल एसजीए व्यय का निर्धारण करने के लिए विज्ञापन व्यय, कमीशन तथा आर एण्ड डी व्यय के कारण कुछेक समायोजनों की अनुमति नहीं दी है। यह पाया गया है कि प्राधिकारी ने कमीशन के बारे में केकेपीसी के दावे पर विचार किया है और निबल एसजीए लागत का निर्धारण करते समय उस पर विचार नहीं किया है। जहां तक विज्ञापन व्यय का संबंध है, प्रकटन विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे एसजीए का भाग क्यों माना गया है। जहां तक अनुसंधान एवं विकास संबंधी व्यय का संबंध है, निर्यातक अपने दावे की पुष्टि नहीं कर सका और उसने अब यह बताया है कि लागत विवरण में आर एण्ड डी व्यय का अंग्रेजी में गलत अनुवाद हो गया है। के के पी सी ने अब अनुमान के आधार पर यह इच्छा व्यक्त की है कि कम से कम 50 % आर एण्ड डी व्यय पर विचार कर लिया जाए चूंकि इस अनुमान का कोई आधार नहीं दिया गया है, इसलिए इस संबंध में निर्यातक के तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है।

4. एसजीए के हिस्से पर विचार करके कौटिब रुप से उत्पादित और खपत की गई बुटाडीन की अन्तरण कीमत के गलत मूल्यांकन के बारे में केकेपीसी का तर्क सही नहीं है क्योंकि एनबीआर के लिए प्रयोज्य एसजीए एवं ब्याज के हिस्से का निर्धारण करने के

लिए कैप्टिव रूप से उत्पादित तथा खपत की गई कच्ची सामग्रियों एवं उपयोगिताओं को जोड़कर सभी उत्पादों की ब्याज का आबंटन कुल बिक्री लागत पर किया गया है इसलिए बुटाडीन (कैप्टिव रूप से उत्पादित अथवा खपत की गई) के लिए प्रयोज्य हिस्से को कच्ची सामग्री का वास्तविक अन्तरण मूल्य निकालने के लिए जोड़ा जाना चाहिए ।

5 उत्पादन कार्यकलाप के लिए लगाई गई परिसंपत्तियों के अनुपात पर मार्च 2001 की स्थिति के अनुसार लगाई गई कुल निधियों में से अप्रचालनात्मक निधियों में से अप्रचालनात्मक निधियों को निकालकर समुचित ढंग से विचार किया गया है । 50.50 के आधार पर नकद एवं बैंक शेष तथा दीर्घावधि ऋणों सहित परिसंपत्तियों के त्वरित अनुमान के आधार की पुष्टि नहीं की गई थी और उसे स्वीकार नहीं किया जा सका ।

6 निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्तानुसार उत्पादन लागत का उचित निर्धारण किया गया है ।

7. प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 में यथा निर्धारित व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के परीक्षण को लागू करके किया गया है ।

प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मै0 केकेपीसी के प्रतिनिधि ने निर्यात कीमत पर कमीशन के समायोजन के बारे में स्पष्टीकरण माँगा है और उसने सामान्य मूल्य पर शुल्क वापसी संबंधी समायोजन पर विचार करने की मंशा जाहिर की है । प्राधिकारी यह स्पष्ट करते हैं कि निर्यातक द्वारा दवा किए गए कमीशन पर कारखाना निर्यात कीमत के मूल्यांकन हेतु विचार किया गया है और शुल्क वापसी संबंधी समायोजन को अब दावा की गई निर्यात कीमत की बजाय सामान्य मूल्य में उचित ढंग से समायोजित किया गया है क्योंकि यह समायोजन या तो सामान्य मूल्य पर या निर्यात कीमत पर किया जा सकता है । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण के उत्तर में घरेलू उद्योग ने केकेपीसी के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण से संबंधित मुद्दा भी उठाया है प्राधिकारी ने अनुरोधों पर विचार किया है और संगत मुद्दों पर निम्नानुसार उचित कार्रवाई की है:-

1. जहाँ तक इस अभिमत का संबंध है कि निर्यातक लेखों का रख-रखाव कैलेंडर वर्ष के आधार पर करता है और जाँच अवधि 2000-01 वर्ष है, अनुरोध है कि निर्यातक ने लाभ एवं हानि लेखे, तुलन-पत्र एवं जाँच अवधि के दौरान एनबीआर सहित विनिर्मित विभिन्न उत्पादों की उत्पादन लागत के बारे में पूर्ण सूचना उपलब्ध की है जिस पर उचित विचार किया गया है ।
2. जहाँ तक कच्ची सामग्री की खपत का संबंध है, कॉफी कच्ची सामग्री की खपत का लेखा बहियों के साथ पूर्ण पुनर्मिलान प्रस्तुत किया है ।
3. पैकिंग लागत पर टिपपणियों के बारे में अनुरोध है कि इसका लेखा बहियों के साथ विधिवत पुनर्मिलन किया गया है । जहाँ तक खर्चों के शोधन का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि यह कम्पनी खनन संबंधी कार्यकलाप से संबंधित है न कि एनबीआर से ।

4. कैटिवरूप से उत्पादित और खपत की गई बुटाडीन की कीमत को विधिवत समयोजित किया गया है ताकि उसमें लागू होने वाले एसजीए की लागत एवं इंटरैस्ट को शामिल किया जा सके ।

निर्यातक के प्रतिनिधि को यह भी स्पष्ट कर दिया गया था और उसके द्वारा स्वीकार भी किया गया था कि प्रकटन विवरण में निवल ब्याज लागत तैयार करने में प्राधिकारी की वास्तविक मशा यह सूचित करने की थी कि ब्याज आय कम्पनी के निवेश कार्यकलापों से संबंधित है न कि उत्पादन कार्यकलाप से और इसलिए सकल ब्याज लागत पर विचार किया गया है । इस संबंध में निर्यातक के तर्क की उचित जाँच की गई है और प्राधिकारी यह दोहराते हैं कि ब्याज आय केवल निवेश कार्यकलापों से संबंधित है और इसलिए इसे शामिल नहीं किया जाता है । प्राधिकारी आगे निर्यातक के इन अनुरोधों को भी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण में इस असंगति के कारण वह अवैध है । प्राधिकारी मानते हैं कि प्रकटन विवरण का उद्देश्य आवश्यक तथ्यों को उजागर करना होता है इसके तहत प्रकटन विवरण पर उत्तर से उत्पन्न मुद्दों का समाधान करना भी होता है । इस चरण पर पद्धति, तथ्यगत असंगतता इत्यादि का उचित समाधान करना होता है क्योंकि यह इससे ही अन्तिम निर्धारण किया जाता है । यह तथ्य कि प्राधिकारी ने इसे निर्यातक के समक्ष स्पष्ट कर दिया और निर्यातक ने स्वीकार कर लिया है, प्राधिकारी ने आवश्यक तथ्य उपलब्ध कराए हैं और उन पर टिप्पणियाँ मांगी हैं तथा उन पर समुचित ढंग से विचार भी किया गया है ।

इस प्रकार, प्रकटन विवरण में यथा निर्दिष्ट सामान्य मूल्य के निर्धारण की पद्धति के साथ-साथ स्पष्ट किए गए मुद्दों की पुष्टि की जाती है ।

तदनुसार सामान्य मूल्य \*\*\* डालर/मी० टन बनता है तथा कारखाना निर्यात कीमत \*\*\* डालर/मी० टन और पाटन मार्जिन \*\*\* डालर/मी० टन (10.27%) बनता है ।

#### ख. हुण्डई पेट्रोकेमिकल कं० लि० सामान्य मूल्य

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यातकों ने विभिन्न अनुरोधों के संबंध में निर्धारित प्रश्नावली में कोई उत्तर उपलब्ध नहीं किया है जैसाकि पूर्व के पैरा में उल्लेख किया गया है । ऐकसी परिस्थितियों में प्राधिकारी के पास सपाटनरोधी नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है । अतः प्राधिकारी ने मै० हुण्डई पेट्रोकेमिकल कं. लि. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सहयोगी निर्यातकों में से एक निर्यातक अर्थात् मै. केकेपीसी द्वारा यथा उल्लेखित उच्चतमक घरेलू बिक्री कीमत का संदर्भ लेने का प्रस्ताव किया ।

चूँकि प्रकटन पत्र का कोई उत्तर दायर नहीं किया गया है इसलिए प्राधिकारी \*\*\* डालर प्रति मी० टन के सामान्य मूल्य की पुष्टि करते हैं ।

#### निर्यात कीमत

निर्यात कीमत के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग नें गौण स्रोतों के आधार पर मै० हुण्डई द्वारा जाच अवधि के दौरान भारत को किये गए निर्यातों से संबंधित सौदे

उपलब्ध कराये हैं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा यथा उपलब्ध भारित औसत सीआईएफ निर्यात कीमत का संदर्भ लेने का प्रस्ताव किया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तथा सहयोगी निर्यातक द्वारा दिये गये साक्ष्य/मिलान किये गये आंकड़ों के अनुसार भी समुद्री, समुद्री बीमा, कमीशन, अन्तर्देशीय भाड़े, पैकिंग और पत्तन खर्चों के लिए समायोजनों पर विचार करने का भी प्रस्ताव किया।

चूँकि प्रकाटन पत्र का कोई उत्तर दायर नहीं किया गया है इसलिए प्राधिकारी \*\*\* डालर प्रति मी० टन के सामान्य मूल्य की पुष्टि करते हैं।

उपरोक्त के आधार पर पाटन मार्जिन 47.08% (\*\*\*) डालर/मी० टन) बनता है।

### (ग) कारिया गणराज्य के अन्य असहयोगी निर्यातक/उत्पादक

प्रकाटन विवरण का कोई उत्तर न मिलने के मद्देनजर, प्राधिकारी सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की निम्नानुसार पुष्टि करते हैं।

#### सामान्य मूल्य

प्राधिकारी असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए मै० केकेपीसी द्वारा उपलब्ध किये गये आंकड़ों के साक्ष्य के अनुसार उच्चतम घरेलू कीमत का संदर्भ लेने का प्रस्ताव करते हैं।

अतः सामान्य मूल्य का संदर्भ डालर/मी० टन पर लिया गया है।

#### निर्यात कीमत

जहाँ तक निर्यात कीमत का संबंध है, प्राधिकारी न्यूनतम निर्यात कीमत का संदर्भ लेते हैं जैसाकि सहयोगी निर्यातक और घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध किये गये आंकड़ों से साक्ष्य मिलता है। प्राधिकारी कारखाना निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु मै० हुंडई पेट्रोकेमिकल कं० लि० के मामले में यथाविचारित समायोजनों पर विचार करते हैं।<sup>1</sup>

कारखाना निर्यात कीमत \*\*\* डालर/मी० टन बनती है।

उपरोक्त के आधार पर, पाटन मार्जिन 49.06% (\*\*\*) डालर/मी० टन) बनता है।

### 3. जर्मनी

#### (क) वेयर एजी, जर्मनी

##### सामान्य मूल्य

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मै० वेयर ने निर्धारित प्रश्नावली के अनुसार आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये हैं किन्तु उन्होंने यह उल्लेख किया है कि उनकी उत्पादन लागत में एक मात्र लागत संबंधी परिवर्तन मोनोकर की लागत के कारण आया है जिसके संबंध में उन्होंने कीमत उपलब्ध कराई है। जहाँ तक अन्य उत्पादन लागत का संबंध है, यह उल्लेख किया गया है कि लागत में कुल मिलाकर कोई परिवर्तन नहीं गया है। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मध्यावधि समीक्षा की सिफारिश 17.72001 की अधिसूचना के तहत की गई थी। प्राधिकारी यह भी नोट

करते हैं कि मै0 बेयर द्वारा उसे चुनौती नहीं दी गई है। अतः प्राधिकारी ने वही पद्धति अपनाई जो सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु पूर्ववर्ती समीक्षा में अपनाई गई थी।

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मै0 बेयर द्वारा भारत को निर्यातित एनबीआर की निर्यात कीमत में सनसेट समीक्षा हेतु वर्तमान जांच अवधि में वृद्धि हुई है। यद्यपि मोनोमार की कीमत में वृद्धि हुई है और परिणामतः मै0 बेयर के सामान्य मूल्य में भी उर्ध्वगामी संशोधन अपेक्षित है तथापि प्राधिकारी पिछली जांच अवधि के दौरान यथानिर्धारित पूर्ववर्ती सामान्य मूल्य का सदर्थ लेने का प्रस्ताव करते हैं जो वर्तमान परिस्थितियों में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना होगी।

इस आधार पर सामान्य मूल्य \*\*\* डालर/मी0 टन बनता है। चूंकि निर्यातक द्वारा प्रकटन विवरण को कोई उत्तर नहीं दिया गया है इसलिए प्राधिकारी \*\*\* डालर/मी0 टन के सामान्य मूल्य की पुष्टि करते हैं।

### निर्यात कीमत

प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने भारत को निर्यातित मात्राओं के साथ-साथ जांच अवधि के दौरान भारत औसत सीआईएफ कीमत उपलब्ध कराई है। अतः प्राधिकारी ने निर्यात कीमत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसी का सदर्थ लिया है। प्राधिकारी ने इस सीआईएफ कीमत के आधार पर पूर्ववर्ती मध्यावधि समीक्षा के दौरान उपलब्ध किये गये आकड़ों के अनुसार समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा और कमीशन के संबंध में समायोजनों पर विचार किया है।

कारखाना निर्यात कीमत \*\*\* डालर/मी0 टन बनती है।

चूंकि निर्यातक द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है इसलिए प्राधिकारी \*\*\* डालर/मी0 टन की निर्यात कीमत की पुष्टि करते हैं।

उपरोक्त के आधार पर, पाटन मार्जिन 24.87% (\*\*\* डालर/मी0 टन) बनता है।

### (ख) जर्मनी के अन्य असहयोगी निर्यातक/उत्पादक

चूंकि प्रकटन विवरण का कोई उत्तर नहीं दिया गया है इसलिए प्राधिकारी ने निम्नानुसार सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

### सामान्य मूल्य

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जर्मनी के किसी निर्यातक/उत्पादक ने सहयोग नहीं किया है। अतः प्राधिकारी ने इन परिस्थितियों में केवल मै0 बेयर एजी के लिए यथानिर्धारित सामान्य मूल्य का सदर्थ लिया है।

अतः सामान्य मूल्य का \*\*\* डालर/मी0 टन पर सदर्थ लिया गया है।

### निर्यात कीमत

जहां तक कारखाना निर्यात कीमत का संबंध है प्राधिकारी ने असहयोगी निर्यातको/उत्पादको के लिए मै0 बेयर एजी की न्यूनतम निर्यात कीमत का संदर्भ लिया है। मै0 बेयर एजी को निर्यात कीमत पर प्रदान किये गये समायोजनों पर इन असहयोगी निर्यातको के लिए भी विचार किया गया है।

कारखाना निर्यात कीमत \*\*\* डालर/मी0 टन बनता है।

उपरोक्त के आधार पर, पाटन मार्जिन 44.11% (\*\*\* डालर/मी0 टन बनता है)

### **4. पाटन - सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत की तुलना**

तुलना से संबंधित नियमों में निम्नानुसार व्यवस्था है -

"पाटन मार्जिन निकालते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना करेंगे। यह तुलना व्यापारिक उसी स्तर पर सामान्यतः कारखाना स्तर पर और यथासंभव उसी समय की गई बिक्रियों के संबंध में की जाएगी। प्रत्येक मामले में बिक्री, कराधान की शर्तों, व्यापार स्तरों, मात्राओं, भौतिक विशेषताओं में अन्तर और ऐसे अन्तर, जिन्हें कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है, सहित कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने वाले अन्तरों के लिए गुण-दोष के आधार पर अनुमति दी जाएगी।"

पाटन मार्जिन का मूल्यांकन करने के लिए प्राधिकारी ने भारत औसत सामान्य मूल्य की तुलना भारत औसत कारखाना निर्यात कीमत के साथ की है। सामान्य मूल्य का आकलन करते समय प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबद्ध। के नियम 2 के अनुसार व्यापार की सामान्य प्रक्रिया को परीक्षण लागू किया है।

ऊपर यथा निर्धारित सामान्य मूल्य एवं कारखाना निर्यात कीमत के आधार पर प्राधिकारी ने संबंधित देशों के मूल्य के अथवा वहाँ से भारत को निर्यातित संबंधित वस्तु के लिए पाटन मार्जिन का आकलन किया है।

निर्यातक/उत्पादक	सामान्य मूल्य डा0/एमटी	निर्यात कीमत डा0/एम.टी	पाटन मार्जिन (%)
<b>कोरिया आर0पी0</b>	****	****	10.27
1. कोरिया कुम्हों पेट्रोकेमिकल कं0			
2. हुंदई पेट्रोकेमिकल्स कं0 लि0	****	****	47.08
3. अन्य सभी निर्यातक/उत्पादक	****	****	49.06
<b>जर्मनी</b>	****	****	24.87
1. बायर ए.जी.			
2. सभी अन्य निर्यातक/उत्पादक	****	****	44.11

उक्त पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक हैं ।

#### 5. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ, 1975 की धारा 9क(5) के अनुसार इस धारा के अन्तर्गत लगाया गया पाटनरोधी शुल्क यदि पहले रद्द न किया जाए तो वह उसके लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा ।

इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी समीक्षा में केन्द्र सरकार का यह मत हो कि ऐसे शुल्क को समाप्त करने से पाटन जारी रहेगा और इसकी पुनरावृत्ति होगी तथा क्षति पहुँचेगी तो वह इस शुल्क को लागू होने की अवधि को समय-समय पर अगले पांच वर्ष के लिए बढ़ा सकती है और ऐसी और अवधि इसके बढ़ाने के आदेश की तारीख से शुरू होगी । इसमें यह भी प्रावधान है कि जहाँ उक्त पांच वर्ष की अवधि के समाप्त होने से पूर्व शुरू की गई समीक्षा का ऐसे रागापन से पूर्ण कोई परिणाम न निकले तो पाटनरोधी शुल्क ऐसी समीक्षा के परिणाम आने तक अगली इतनी अवधि के लिए लागू रहेगी जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"

उक्त नियम-11, अनुबंध-11 के अधीन भी जब किसी क्षति का जांच परिणाम तय किया जाता है तो ऐसे जांच परिणाम में घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण भी शामिल होगा जिसमें "..... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में मूल्यों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा ..... ।" कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने में यह जांच करना आवश्यक समझा गया है कि भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमतों में पर्याप्त कटौती हो रही है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतें



काफी सीमा तक अन्यथा अवरूद्ध होती है अथवा कीमतों की वृद्धि जो अन्यथा काफी मात्रा में हो गई होती; में रूकावट उत्पन्न करती हैं।

भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सूचकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री की प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर उक्त नियमों के अनुबंध-॥ (iv) के अनुसार विचार किया गया है।

चूंकि वर्तमान जांच के अन्तर्गत यह मूल्यांकन किया जाना है कि क्या पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त करने से पाटन और क्षति जारी रहेगी अथवा वह पुनः होगी, प्राधिकारी ने इस पहलू का आकलन करने के लिए उक्त नियमों के अनुबंध-॥ (iv) में यथा उल्लिखित क्षति के उचित मानदंडों पर विचार किया है।

प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग अर्थात् मै0 अपार इंडस्ट्रीज लि0 के संबद्ध वस्तु से संबंधित विभिन्न अर्थिक मानदंडों का अनुपालन किया है और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात इस प्रकार है:-

आर्थिक मानदंड	1997-98	1998-99	1999-2000	पीओआई (2000-01)
क्षमता (एमटी)	6250	6250	6250	6250
एनबीआर का सकल उत्पादन (एमटी)	3785	4609	4990	5154
प्रभावी उत्पादन (एमटी)	4300	5366	5742	5360
प्रभावी उत्पादन पर आधारित क्षमता उपयोग (%)	69%	86%	92%	86%
एनबीआर की घरेलू बिक्री (एमटी)	3149	3750	4073	4637
ग्रास ब्लाक (लाख रू.)	4483	4534	5266	5865
अंतिम भंडार (एमटी)	183	279	380	172
प्रतिकर्मचारी औसत मजदूरी (आरएस)	63095	66667	69645	81695
अधिकतम स्थापित मांग (एमटी)	10142	9934	12372	10481
कुल अधिकतम आयात (एमटी)	6693	6184	8299	5844
सकल आयात में कोरिया के आयातों का हिस्सा	33.59	48.42	53.45	48.58

(%)				
सकल आयात में जर्मनी का हिस्सा (%)	18	9.7	7.23	7.99
सकल आयात में संबद्ध देश के आयात का (%)	51.59	58.12	69.68	56.57
साउथ कोरिया से आयात का सकल मांग में (%)	23.16	30.14	35.86	27.09
जर्मनी से आयात का सकल मांग में (%)	12.41	6.04	4.85	4.46
संबद्ध देशों से आयात का सकल भाग में %	35.57	36.18	40.70	31.54
घरेलू उद्योग का सकल मांग में % हिस्सा	31.05	37.75	32.92	44.24
निवल बिक्री प्राप्ति (रु. एमटी)	****	****	****	****
उत्पादन की लागत (रु./एमटी)	****	****	****	****
लाभकारिता (रु./एमटी)	****	****	****	****

प्राधिकारी विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए आयातों के लिए डीजीएडी के आंकड़ों का संदर्भ लेने के बारे में किए गए निवेदनों को भी नोट करते हैं। प्राधिकारी प्रकटन निवरण में की गई अपनी टिप्पणियों को स्मरण करते हैं और सहयोगी निर्यातकों, डीजीएडी और गौण स्रोत अर्थात् पीपीओ से उत्तरों से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अधिकतम मांग और अधिकतम आयातों का मूल्यांकन किया गया है।

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मैं केकेपीसी ने यह निवेदन किया है कि विभिन्न क्षति मानदंडों और मै0 अपार इंडस्ट्रीज लि0 के उत्पादन लागत की विस्तृत जांच की जानी चाहिए और क्षति और कारणात्मक संबंध पर उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने भी घरेलू उद्योग को हुई क्षति से संबंधित मुद्दों को उठाया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मै0 अपार इंडस्ट्रीज लि0 गुजरात में अपने वालिया संयंत्र में प्रारंभिक रूप से एनबीआर का उत्पादन करता है। जांच अवधि के दौरान कम्पनी ने जांच अवधि में प्रयुक्त सकल क्षमता को लगभग 95% एनबीआर का उत्पादन किया है। कम्पनी वालिया संयंत्र के लिए अलग विधिवत संपरीक्षित लेखा बहियां रखता है। अतः एनआईपी के निर्धारण का आधार अधिप्रमाणित है और केवल एनबीआर से संबंधित लागतों और खर्चों पर उत्पादन लागत के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है तथा इसके द्वारा गैर-क्षति कारक कीमत पर विचार किया गया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने परम्परा के अनुरूप भील लागतों के विभिन्न घटकों का आकलन किया है ताकि घरेलू उद्योग को कोई

अनुचित लाभ या संरक्षण प्राप्त न हो सके जो उन्हें उनकी अकुशलता के कारण प्राप्त हो सकता था। अतः प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की कार्य स्थल की जांच के दौरान लाभकारिता और बहु-उत्पाद कम्पनी होने के कारण कम्पनी द्वारा विभिन्न संबंधित उत्पादों पर परस्पर खर्चों को लगाने के बारे में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को उचित रूप से ध्यान में रखा है।

तालिका में उक्त आर्थिक मानदंडों से यह मालूम होता है कि संबद्ध वस्तु की मांग लगभग 10,000 एमटी से 12000 एमटी तक रही है और यह क्षति का कोई कारण नहीं है। घरेलू उद्योग के लिए उत्पादन और क्षमता उपयोग से संबंधित सूचको से वृद्धि का संकेत मिलता है। यद्यपि सकल मांग में घरेलू उद्योग के हिस्से में वृद्धि हुई है परन्तु संबद्ध देशों विशेषतः कोरिया आर.पी. से आयात पाटनरोधी शुल्क के बावजूद मांग के पर्याप्त % के रूप में बने रहने के कारण देशों से आयात पर्याप्त मात्रा में हो रहे हैं। इसके साथ-साथ मूल्य में कटौती के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और यह क्षति दोबारा भी होगी।

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति गैर-क्षतिकारक कीमत से कम है। संबद्ध देशों से पाटित आयात मूल्य में कटौती करने के सबूत हैं क्योंकि ऐसे पाटित आयातों का पहुँच मूल्य गैर क्षतिकारक कीमत से कम है और वर्तमान पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद भी मै0 केकेपीसी के मामले में जब पाटनरोधी शुल्क सहित पहुँच मूल्य की गैर क्षतिकारक कीमत के साथ तुलना की जाती तो भी मूल्य में कटौती हुई है। मै0 केकेपीसी के इस तक कि सीमाशुल्क और एसएडीडी के प्रभाव पर भी उचित रूप से विचार किया जाए, अतः इन पर भी प्राधिकारी द्वारा विधिवतः विचार किया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एनबीआर एक औद्योगिक उत्पाद है और संबंधित प्रथा के अनुसार कारखाना द्वार के गैर क्षतिकारक मूल्य की ही पहुँच मूल्य के साथ तुलना की जाती है जैसे निम्नलिखित निर्धारण में इसे परिभाषित किया गया है। यदि संबद्ध वस्तु के लिए जांच की वर्तमान अवधि में सीमाशुल्क लगाया गया है तो घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भी कम शुल्क लगे होंगे इसलिए गैर-क्षतिकारक मूल्य पर भी सीमा शुल्कों में कमी के कारण प्रभाव पड़ा है। अतः जांच अवधि में पहुँच मूल्य की तुलना जांच अवधि के दौरान गैर क्षतिकारक मूल्य के साथ करने की प्रथा उचित और अनुकूल है। मै0 केकेपीसी का यह तर्क कि व्यापार के स्तर पर समायोजन प्रदान किए गए हैं क्योंकि मै0 केकेपीसी के निर्यात थोक विक्रेताओं को किए गए हैं न कि अंतिम प्रयोक्ताओं को, भी उचित नहीं है क्योंकि यदि थोक विक्रेताओं को, वितरण श्रृंखला पाटित आयातों से लाभ होता है तो आपूर्तियाँ अन्ततः खुदरा स्तर के वास्तविक प्रयोक्ताओं को ही की जाती हैं। इसलिए घरेलू उद्योग की बिक्री पर इसका प्रतिकूल प्रभाव हुआ है और इस प्रकार कारखाना द्वार पर की गई उपर्युक्त तुलना उचित है। उपर्युक्तानुसार कारखाना द्वार के स्तर पर मूल्यांकन की तुलना उचित है जिसे प्राधिकारी अनुकूल रूप से कर रहे हैं। इसलिए प्राधिकारी ने यही नीति अपनाई है। मै. केकेपीसी द्वारा पाटित वस्तु का पहुँच मूल्य वर्तमान पाटनरोधी शुल्क जोड़ने के बाद भी एनआईपी सके कम है। प्राधिकारी बूटाडीन की अधिक लागत के बारे में किए गए निवेदनों के संबंध में यह नोट करते हैं कि माननीय सिगेट ने जापान से एनबीआर के मामले में अपने दिनांक 4.2.1997 के निर्णय में इष्टतम स्तर पर एनआईपी के निर्धारण की पद्धति को बरकरार रखा है और घरेलू उद्योग की स्थितियों को ध्यान में रखा है। विभिन्न आर्थिक घटकों अर्थात् पाटित आयातों से मूल्य में कटौती,

एनआईपी से कम निवल बिक्री वसूली और लाभकारिता में ह्रास का अर्थ है कि यदि सबद्ध देशों से सबद्ध वस्तु पर लगे पाटनरोधी शुल्क हटा लिए जाएं तो पाटन और क्षति जारी रहेंगे और दोबारा होंगे और घरेलू उद्योग को अत्यधिक वास्तविक क्षति पहुँचाएंगे।

#### 6. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सबद्ध वस्तु की मांग और पूर्ति में असमानता और निर्यात प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव के बारे में भी निवेदन किए गए हैं। इस सबद्ध में प्राधिकारी का यह मानना है कि सामान्यतः पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो देश के सामान्य हित में है।

प्राधिकार यह भी मानते हैं कि यद्यपि पाटनरोधी शुल्क लगाने से सबद्ध वस्तु का प्रयोग करके बनाए गए उत्पादों के मूल्य के स्तर को प्रभावित कर सकता है और इसके फलस्वरूप इन उत्पादों की सापेक्ष प्रतिस्पर्धा पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है, परन्तु भारतीय बाजार में इन पाटनरोधी उपायों के कारण उचित प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत पाटनरोधी उपायों को लागू करने से पाटन प्रथाओं द्वारा प्राप्त होने वाले अनुचित लाभ समाप्त हो जाएंगे और घरेलू उद्योग का पतन रुक जाएगा तथा उपभोक्ताओं के लिए सबद्ध वस्तु के अधिक विकल्प उपलब्ध रहने में सहायता प्राप्त होगी। पाटनरोधी उपायों को लागू करने से सबद्ध देशों से किसी भी प्रकार का आयात प्रतिबधित नहीं होगा इसलिए उपभोक्ताओं/प्रयोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी।

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मै0 केकेपीसी द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस मामले में विभिन्न मामला विषयक कानूनों का उल्लेख करते हुए अपने हस्ताक्षर से प्रकटन विवरण भेजना चाहिए था। निर्यातकों ने भी यह निवेदन किया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई सुनवाई नियमानुसार उचित रूप से नहीं की गई और उसके लिए डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेदों का और मामलों से संबंधित कानूनों का उल्लेख किया। इस सबद्ध में प्राधिकारी उस नियम को नोट करते हैं जो जाच के दौरान की जाने वाली मौखिक प्रस्तुतियों और नियम 16 के अन्तर्गत प्रकटन विवरण जारी करने के बारे में है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सुनवाई के दौरान प्रस्तुत मौखिक निवेदनों पर केवल तभी विचार किया जाता है जब उन्हें बाद में लिखित में प्रस्तुत किया गया हो। इसलिए एक अनिवार्य आवश्यकता यह है कि मौखिक निवेदनों के बाद लिखित निवेदन किए जाएं ताकि इस पर जाच के दौरान उचित रूप से विचार किया जा सके। प्राधिकारी न नियम की इस स्थिति का अनुपालन किया है और ऐसी सुनवाई करने में तथा विभिन्न पक्षकारों को अपने निवेदन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करने में अनुकूल प्रथा का अनुरोध किया है। इसका अतिरिक्त प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मै0 केकेपीसी द्वारा किए गए समस्त निवेदनों की जाच दल द्वारा कार्य स्थल पर विधिवत जाच की गई थी और सभी सगत निवेदनों पर विधिवत विचार करके उनका समाधान किया गया था। जहां तक प्रकटन विवरण का सबद्ध है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि प्रकटन विवरण अनिवार्य तथ्यों से संबंधित सूचना के बारे में होता जो किसी निर्णय का आधार बनता है परन्तु वह कोई निर्णय नहीं होता। प्राधिकारी ने निर्दिष्ट प्राधिकारी की ओर से जाच

अधिकारी के हस्ताक्षर के अन्तर्गत किसी ऐसी सूचना को प्रकट करने की अनुकूल प्रथा को अपनाया है, इसलिए वह मानते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम-16 के अन्तर्गत अपनाई गई प्रथा ही इस मामले में अपनाई गई है।

## 7. पहुँच मूल्य

संबद्ध वस्तु के लिए पहुँच मूल्य का निर्धारण अधिमानित औसत सीआईएफ निर्यात कीमत, सीमाशुल्क की लागू दर धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के अधीन लगाए गए शुल्कों को छोड़कर और पहुँच प्रभारों के लिए एक प्रतिशत को जोड़ने के बाद किया गया है।

## (घ) निष्कर्ष

पूर्वोक्त पर विचार करने के बाद यह मालूम होता है कि:-

(क) संबद्ध देशों के मूल से अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु का भारत में इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया है,

(ख) विभिन्न आर्थिक सूचकों और पाटित आयातों द्वारा मूल्य में विशेष रूप से की गई कटौती में क्षति के मानदंडों का यह अर्थ है कि संबद्ध देशों से वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने से निरन्तर और बार-बार पाटन और क्षति होती रहेगी, इसलिए प्राधिकारी निम्न प्रकार से किए गए उल्लेख के अनुसार संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखन की सिफारिश करते हैं। इस संबंध में प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि दिनांक 21.12.2001 की अधिसूचना के तहत सीमाशुल्क विभाग द्वारा कार्यान्वित अन्तिम समीक्षा में जापान से एनबीआर के आयातों पर एक परिवर्तनीय शुल्क लगाया गया है इसलिए प्राधिकारी यह उचित समझते हैं कि इस जांच में भी परिवर्तनीय किस्म का पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए। प्राधिकारी इस बात का भी स्मरण कराते हैं कि माननीय सिगेट ने डालर के रूप में शुल्क लगाने की मान्यता दी है।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय 40 के अधीन आने वाले तथा कोरिया आर पी और जर्मनी से उद्भूत अथवा निर्यातित एक्रिलोनाइट्रिल बूटाडीन रबर (एनबीआर) के सभी ग्रेडों पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 3 में दी गई राशि और डालर/मी.ट. में पहुँच मूल्य के बीच के अंतर के बराबर परिवर्तनीय राशि का पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने के संबंध में विचार किया गया है।

क्र.सं.	निर्यातक/उत्पादक का नाम	शुल्क की राशि डालर/मी.ट.
1.	कोरिया आर.पी. 1. कोरिया कुमहो पेट्रोकेमिकल कं.लि. (केकेपीसी) 2. हुंदई पेट्रोकेमिकल कं.लि. 3. अन्य सभी निर्यातक/उत्पादक	1692.12 1908.28 1908.28
2.	जर्मनी 1. बायर एजी 2. अन्य सभी निर्यातक/उत्पादक	2314.8 2314.8

(घ) इस आदेश के खिलाफ कोई अपील उक्त अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क उत्पाद, स्वर्ण (नियंत्रण) अपील ट्रिब्यूनल के समक्ष की जाएगी।

एल.बी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अपर सचिव

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

#### DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2002

#### FINAL FINDINGS

Sub. : Anti-Dumping investigations concerning Sunset Review of anti-dumping duty on imports of Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) from Korea RP and Germany.

No. 50/1/2001-DGAD.— Having regard to the Section 9A(5) of the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of anti-dumping duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof :

#### A PROCEDURE

The procedure described below has been followed

- (i) The Designated Authority (hereinafter also referred to as Authority), under the above Rules as per Section 9A(5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 initiated Sunset Review to review the need for continued imposition of anti-dumping duty on imports of Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) (hereinafter called subject goods) from Korea RP and Germany (hereinafter called subject countries). Subject goods were defined in the original preliminary findings of the Authority dated 30.12.1996 and thereafter confirmed vide Final Findings dated 17.7.1997. The Anti Dumping Duty after the last mid-term review were notified vide Customs Notification No.91/2001-Cus. Dated 7.9.2001 and the Anti Dumping Duty is present in force vide Custom Notification No.61/2002 dated 7.6.2002.

- (ii) The Authority issued a public notice dated 1 10 2001 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations in respect of the above mentioned investigation concerning imports of the subject goods classified under Chapter 40 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 originating in or exported from Korea RP and Germany
- (iii) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters (whose details were available in the investigations conducted earlier) and the industry/user associations and gave them an opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2)
- (iv) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers ((whose details were available in view of investigations conducted earlier) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(2)
- (v) Request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) to arrange details of imports of subject goods made in India during the past three years, including the period of investigation
- (vi) The Authority provided a copy of the initiation notification to the known exporters and the Embassies of the subject countries, New Delhi in accordance with Rules 6(3) supra
- (vii) The Authority sent a questionnaire to elicit relevant information to the following known exporters/producers, in accordance with the Rule 6(4)
  - (i) M/s Korea Kumho Petrochemical Co Ltd (KKPC), Korea RP
  - (ii) M/s Hyundai Petrochemical Co Ltd Korea RP
  - (iii) M/s Bayer AG, Germany

Response/information to the questionnaire was filed by the following exporters/producers:

- (i) M/s Korea Kumho Petrochemical Co Ltd (KKPC) , Korea RP
- (ii) M/s Hyundai Petrochemical Co. Ltd Korea RP
- (iii) M/s Bayer AG, Germany

Though M/s KKPC filed structured response to the questionnaire, M/s Hyundai Petrochemic Co Ltd indicated no desire to furnish the information, and M/s Bayer AG provided details on exports made by them and their views on their cost of production in general, and not as per structured questionnaire response

- (viii) The Embassies of the subject countries in New Delhi were also informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) with a request to advise all concerned exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter and questionnaire sent to the known exporter was also sent to the Embassies of the subject countries in accordance with Rule 6(3)
- (ix) A questionnaire was sent to the known importers/user associations of the subject goods whose details were made available by the petitioner for necessary information in accordance with Rule 6(4) -

Response/information to the questionnaire was filed by the following importers -

- (i) All India Federation of Rubber Footwear Industries
- (ii) Small Scale Rubber Industries Association of India
- (iii) All India Rubber Industries Association of India
- (x) Information regarding injury was sought from M/s Apar Industries Ltd., the domestic producer of the subject goods
- (xi) Cost investigation of M/s Apar Industries Ltd at their premises at Walia, Gujarat was also conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and to examine various injury parameters
- (xii) Additional information from M/s KKPC and M/s Apar Industries Ltd was also sought
- (xiii) An opportunity was provided to all interested parties to present their views orally on 7 12 2001 All parties presenting views were requested to file written submissions of the views expressed The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rebuttals, if any,
- (xiv) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority by the Authority and kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7)
- (xv) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties on 13 9 2002 Response to which was filed by M/s KKPC and M/s Apar Industries Ltd.
- (xvi) On site verification of the exporter, M/s KKPC, Seoul was conducted on 23<sup>rd</sup> August and 24<sup>th</sup> August of 2002
- (xvii) \*\*\* in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- (xviii) The period of investigation (POI) considered is 1 4 2000 to 31 3 2001

**B. VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY, EXPORTERS, IMPORTERS, USER ASSOCIATIONS AND OTHER INTERESTED PARTIES & EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

The views expressed by various interested parties have been discussed in the disclosure statement The views which have not been discussed earlier in the disclosure statement and those now raised in response to the disclosure statement are discussed in the relevant paras herein below to the extent these are relevant as per rules and have a bearing upon the case The relevant arguments raised by the interested parties have been examined, considered and, wherever appropriate, dealt in the relevant paras herein below

**1. VIEWS EXPRESSED BY M/S APAR INDUSTRIES LTD.**



**a) PRODUCT UNDER CONSIDERATION & LIKE ARTICLE**

- (i) Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) is a synthetic rubber and is popularly known as Nitrile Rubber or NBR. NBR can be of various grades and can be supplied in various forms.
- (ii) NBR is normally described in terms of acrylonitrile and mooney viscosity
- (iii) Indian industry produces equivalent of all those grades which are being imported at present from Korea RP and Germany
- (iv) Indian industry is in a position to produce equivalent of all those grades which are being produced by the producers in South Korea and Germany even though the same are not being exported to India at present
- (v) NBR is classified in the Customs Tariff Act under Chapter 40 at six digit level under 4002 59. Though NBR has been categorised under dedicated Customs sub-head, lot of material is allowed to be imported under other customs heads as importers some time describe NBR as synthetic rubber. The official statistics of Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) does not therefore exhibit true and complete picture with regard to volume and value of imports. The issue was brought out before the Designated Authority in earlier investigation regarding imports of NBR from Germany and South Korea also. In fact the information furnished by the exporter from Germany and South Korea confirmed that the exports of NBR made by them were significantly higher than the imports shown by DGCI&S
- (vi) NBR is primarily used where oil resistance, abrasion resistance and heat resistance applications are involved. It is widely used in defence automobile, footwear, fabrics, printers, oil field products industries etc
- (vii) Use of a particular grade of NBR depends on the end use to which the goods could put to use
- (viii) Customers in India as well as the other parts of the world can use NBR produced by any manufacturer interchangeably without making any changes in the plant and equipment. There is no viable substitute for NBR and that there is no significant difference in the NBR produced by the petitioner and that exported from Germany and South Korea. They all have similar characteristic and are technically and commercially substitutable and should be treated as like article
- (ix) There cannot be any difference in the technology adopted by Apar and the technology adopted by the producers in Germany and South Korea as NBR world over is produced by emulsion polymerization technology
- (x) The present investigation is a Sunset review and therefore the position on product under consideration, like article and Domestic Industry remains the same as decided in the earlier findings

**b) DUMPING****(i) NORMAL VALUE****1 The following submissions have been made by M/s Apar Industries Ltd.:-**

- (i) The cost of production for the manufacturers in South Korea and Germany has been calculated on the basis of the raw material prices as given by ICIS-LOR and on the basis of other costs as per the best available information. The constructed normal value comes to \*\*\*\*\$/MT
- (ii) The information on exports has been compiled from secondary sources viz Polymers Plastic Rubber Journal (PPR). The material has been cleared by Customs bearing description synthetic rubber. The PPR data has therefore been cross-

examined considering the name of importer, description of goods and the price at which it has been imported.

- (iii) The ex-factory export price from South Korea and Germany comes to 1.08 \$/kg and 1.80\$/kg respectively. The adjustments are to be made account of ocean freight, inland freight, marine insurance, commission, inland freight, port handling to an extent of \*\*\*\*\$/MT, \*\*\*\*\$/MT, \*\*\*\*\$/MT, \*\*\*\*\$/MT, \*\*\*\*\$/MT and \*\*\*\*\$/MT respectively.
- (iv) The Dumping Margin for South Korea comes to 144.94% based on cost and 60.67% based on previous investigation. The Dumping Margin for Germany comes to 48.29% based on cost and 46.94% based on previous investigation.
- (v) The domestic industry has given their estimation regarding the cost of production for M/s KKPC and submit that the exporter's NBR operation were not profitable.
- (vi) M/s Hyundai have shown losses during the first half of 2001 and since the exporter has not responded, we request the Authority to use the best available information.
- (vii) M/s Bayer Germany are transacting at time at low prices causing injury to us and we apprehend that they still are dumping.
- (viii) Bayer has been arguing that cost comparison of their medium grade with our medium grade NBR should be done and high grade with high grade. We submit that this method of computation is appropriate.

c) **INJURY & CAUSAL LINK**

- (i) The Korean and German exporters have increased quantities in the Indian market since 1995-96 to 2000-2001. The imports and the market share are as under:

( in MT)

	1995-96	1996-97	1997-98	1998-1999	1999-00	2000-01
South Korea and Germany	650	2650	2349	3251	1579	1794
Other imports	2804	1834	2323	2028	1946	2219
Total imports	3454	4484	4672	5279	3525	4013
Indigenous Sale	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Total	*****	*****	*****	*****	*****	*****

**Market Share (in %)**

	1995-96	1996-97	1997-98	1998-1999	1999-00	2000-01
South Korea and Germany	18.8	59.1	50.3	61.5	44.8	44.7
Other imports	81.2	40.9	49.7	38.50	55.2	55.3

- (ii) The indigenous NBR production has been very low and consequently the utilisation of the plant for NBR has been very poor. As a result of the dismal NBR operations, the plant has been utilised for production of non-NBR products.

also in order to recover some fixed overhead costs. The NBR production and capacity utilisation are as under:-

	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01
Gross NBR production (including domestic and export qty) (MT)	100	84.68	103.69	112.04	114.56
Polymer Capacity	100	100.00	100.00	100.00	100.00
Polymer capacity utilisation (%)	100	84.67	103.66	112.10	114.63

- (iii) Domestic industry has been forced to sell at prices below its fair selling price as indicated below:-

	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01
Average NBR Selling Price (Rs/MT)	100	89.40	88.58	82.82	88.85
With Excise Duty	100	89.40	88.58	82.82	88.85
Without Excise Duty	100	90.88	91.17	85.50	91.84

- (iv) There has been considerable turnover of the employees cost of low motivation level as the employees have felt that they may not be able to grow due to dumping.
- (v) The profitability of the industry has been very poor since its inception. The industry had to undergo the financial rehabilitation which involved significant sacrifices on part of the promoters.
- (vi) The injury margin is quite significant and there has been a severe injury to the Domestic Industry and is further threatened in case appropriate duties are not imposed at the earliest.
- (vii) Some other countries have dumped NBR and the anti dumping duties have already been imposed on them. The existing anti dumping duties are as under:-

	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-01	
	Price Rs/Kg	Qty MT	Price Rs/Kg	Qty MT	Price Rs/Kg	Qty MT	Price Rs/Kg	Qty MT
Subject countries	55.64	2349	45.64	3251	46.93	1579	52.84	1794
Countries attracting duties	59.78	1094	58.89	799	58.57	729	69.67	699

Other countries	79.93	1228	79.86	1229	86.19	1217	108.09	1519
-----------------	-------	------	-------	------	-------	------	--------	------

- (viii) The demand of NBR has been stable with small growth and that injury to the Domestic Industry is not on account of any recession or contraction of any demand.

d) **OTHER ISSUES**

- (i) We have not been able to find any document from Bayer, which mentions that they have stopped supplies of NBR from Germany. Our understanding is that they have consolidated their entire NBR production in France, and are supplying NBR to India from France. Since this development is post-POI, we believe that the DGAD may not be able to take this into consideration.

**In response to the disclosure, the following submissions have been made by M/s Apar Industries Ltd.:-**

- At the outset, we submit that the present investigation is a sunset review investigation. In the review investigation, the Designated Authority is required to examine recurrence of dumping and/or injury. The Anti Dumping Duty has been in force on the product. Various injury parameters are, therefore, required to be seen in the light of existing duties and recurrence of injury.
- In the instant case also, it is evident from the disclosure statement that even the dumping continues from the subject goods. Therefore, the present situation is that of continuation of dumping rather than recurrence of dumping. It is, therefore, vital to continue the duty for a further period of five years.
- We would also like to state that because of the action by DGAD in the form of an anti dumping duty, we have been able to survive thus far. We have tried our level best to optimize on production, plant utilization and sales volumes. However, we have been continuously forced to sell at sub-optimal prices due to the severe undercutting by the imports.
- The present investigation is a sunset review investigation. The position with regard to product under consideration and like article remains the same. There is no change in the structure of the industry. The scope of the domestic industry remains the same. These have been acknowledged by the Designated Authority in the disclosure statement. We request the Designated Authority to confirm the earlier findings in this regard.
- With regard to issue of various grades are being like article, though it is acknowledged by the Designated Authority that the argument is not substantiated by the opposing interested parties, we submit that the domestic industry is required to produce like article to goods imported into country. Different grades of an article may not per se be substitutable. However, it does not mean that they are not like article. Reliance is being placed upon various investigation conducted by the Designated Authority, which includes DMT/PTA, BOPP, Acrylic Fibre etc. and Anti Dumping Investigation by European Commission against, inter alia, India concerning polyester film.
- Notwithstanding above, it is submitted that various grades of NBR are like products, as these are comparable in terms of various product characteristics,

such as physical and chemical characteristics, product specifications, raw material, production technology and manufacturing process, functions & uses, pricing, tariff classification, etc. It is relevant to point out that slight variations in the values of various parameters per se does not imply different product. Slight variations in various product parameters is nothing peculiar to this product. This is so for almost every product.

- It is also relevant to point out that the Designated Authority has also held that various NBR are like product in the investigations earlier conducted on this product. Such being the case, there is no merit in the argument that various types are different products.

### **Dumping by Korea Kumho**

- The disclosure statement shows that the dumping margin is just 10.60%. Apparently, the submissions made by Kumho are inconsistent with the submissions made by the exporter in the previous review.
- The dumping margin assessed in Review 1 was 27.94 % or \$ 248.3/mt. If we assume momentarily that there are no other changes in the production cost, then the dumping margin in the Sunset Review on account of the changes in the raw material costs and the selling prices should have increased to US \$ 350/mt or more.
- Our contention that the dumping margin has increased in the Sunset Review is corroborated by the fact that Kumho's losses have increased very substantially. Kumho has incurred heavy losses of 24.257 Billion Won in the calendar year 2000, and a loss of 9.249 Billion Won in the 1<sup>st</sup> half of 2001. Thus, it is clear that in the Period of Investigation (2000-01), Kumho has incurred very heavy losses on account of the higher raw material costs and disproportional increases in finished product prices.
- We would like to bring to the attention of the Designated Authority that, in our opinion, the dumping margin of 10.60 % is not only less than expectations of the domestic industry but also much less than the facts.

The following would also be relevant with regard to the two reviews: -

- a) The investigation period in the instant case is 2000-01 year, which differs from financial year of the exporter, who maintains accounts on calendar year basis. It is not clear from the disclosure statement that whether the exporter has provided information for the period of investigation
- b) In the review 1, the issue of various reconciliation statement was raised by the Designated Authority. Considering the response of the exporter in the previous review, it is important whether the exporter has now provided such information and various reconciliation to the Designated Authority.
- c) With regard to consumption of raw materials, we submit that the consumption factors earlier adopted by the Designated Authority in the Review 1 need be applied in this case also, given the complexity of the operations of the company and behaviour of the exporter in the previous case.
- d) At least two elements of costs could not have been considered based on the information given by the company. These are (a) Conversion Cost and (b) Other Plant Cost considering experience in Review 1.

- e) It appears that the exporter has again shown lower cost of production. Either the raw material costs are understated or the conversion cost is understated. We request element wise comparison of previous cost of production with the present cost of production. In case it is found that some elements of costs have been claimed much lower than what these were shown earlier, it is submitted that such claims deserves reconsideration.

In line with earlier study submitted during Review 1, the cost of production would not be as low as US \$ 890/mt.

- It may be noted that Korea has increased capacities far in excess of its domestic requirement. The Korean capacity for this product is in region of 40,000 MT, as against their relatively small domestic demand. Thus, the producers in Korea are always having the problem of excess capacity. To compound the problems further for them, one of the producers – Hyundai - had set up facilities about 4-5 years back and thus had tremendous pressure on its sales and on Kumho's sales. The exporters are obviously exporting as well as selling in their own domestic market at marginal cost. Unfortunately, they have to sell even below their full cost of production and are suffering losses in the process.
- Another issue relevant to dumping here is that both the Korean producers are having their own Butadiene, which they might be making profits. However, profits made on Butadiene cannot be offset against losses being suffered on NBR. As is known, anti-dumping investigations are product specific investigations. The exporters must establish that their NBR operations were profitable – which is impossible since the factual position shows otherwise. Therefore, the raw material produced by the company should be considered at market price of such material.

It is also submitted that the following issues are relevant with regard to the dumping margin determined by the Designated Authority: -

- a) Packing costs: - Even if it is assumed that the form of packing is different in case of domestic market, KKPC has vehemently argued in CEGAT and before the Designated Authority and is our market knowledge, KKPC is using such kind of packing material that the same can not be described "consumable". The same material is recycled by the company. Cost incurred on packing material can not be, therefore, considered as the packing cost. Such being the case, at best, depreciation on such packing material and cost of recycling can be considered as the packing cost. It is also submitted that there is every likelihood that the exporter should have already included the transportation charges associated with return of the packing material under the adjustment on inland freight. Therefore, no price adjustment on this account could be claimed by the exporter. It would be relevant to point out in this regard that the life of such material would be at least ten years. Further, it is submitted that the entire cost of depreciation cannot be charged to single shipment. There should have been several shipments made by the exporter using the same packing material. Thus, number of cycles for which the packing material

has been used is required to be considered while considering the cost of packing

It is submitted that the claim of the exporter appears to be based on sample calculations of packing cost involved rather than accounting information. It would be perhaps necessary to consider the total expenses incurred on packing material by the exporter during the whole year rather than cost of packing material

- b) US \$ denominated sales in the domestic market - The exporter has US \$ denominated sales in the domestic market. However, these appear to be deemed export sales of the exporter. It would be relevant here to point out that the exporter has a trading arm as its affiliate. It is possible that some of the sales of the exporter are through the trading arm. In case, however, the material has physically moved out of Korea, these sales can not be described as domestic sales and are required to be excluded.
- c) Level of trade - The argument on level of trade does not concern the dumping margin calculations. The level of trade between exports to India and domestic sales is the same. With regard to injury margin, (a) the exporter as also domestic industry is selling at the same level of trade, (b) the injury margin is substantially higher than the dumping margin.
- d) Amortization expenses - Amortization of intangible assets is similar to depreciation on common facilities. Since depreciation on common facilities is loaded onto the products, amortization of intangible assets cannot be excluded from the full cost of production, particularly when the cost of production is required to be determined after considering SGA.
- e) Duty Drawback - The exporter has never before claimed an allowance on this account. Further, the exporter has resorted to import of duty free material. It is, therefore, not understood how the exporter can now claim duty drawback as an adjustment.
- f) Butadiene price - As argued earlier, Butadiene is required to be considered at the price at which the exporter has purchased Butadiene. In any case, the cost of production of Butadiene should be full cost of production including SGA.

#### **DUMPING BY HYUNDAI**

- With regards to dumping by Hyundai, their losses have been astonishingly increasing. The calendar year 2000 showed a loss of 378.35 Billion Won and 1<sup>st</sup> Half of 2001 showed a loss of 144.482 Billion Won.
- So, the dumping margin for Hyundai is obviously much higher than Kumho, also considering that it is a newer plant and accordingly would have higher interest and depreciation costs. That could be the reason for no questionnaire response by the company. Since the exporter has preferred not to respond, we request the Rule of Best Information Available in respect of this company.

#### **DUMPING BY BAYER**

- The Review 1 clearly shows that dumping continues, and we apprehend that dumping still continues. Further, they have been transacting at times at low

prices causing injury to us. One issue, which Bayer has raised, is that the company has been exporting High Acrylonitrile level NBR (in short - high NBR) and Medium Acrylonitrile level NBR (in short - medium NBR) to India. We are also producing these types. Bayer has been arguing about cost comparison of their medium with our medium NBR and their high with our high NBR. We submit that we do not have any objection to this method of comparison.

### **INJURY AND CAUSAL LINK**

- On the injury front, we have been forced to sell at much below our Non-injurious price due to the heavily dumped imports particularly from South Korea. While our operations have increased in terms of production, sales, capacity utilization; our margins have been under tremendous strain and we have been incurring losses in the NBR business.
- It is submitted that the present investigation is a sunset review of existing anti-dumping duty. Examination of various economic parameters, such as production, sales volumes, selling prices, profit/loss, etc. are to be examined in the context of an anti dumping duty being in force on the product. Recurrence of injury is also equally important in a case of Review, even though the facts of this case clearly show continuance of injury. It is also submitted that with anti dumping duty being in force, improvement in some of the parameters could be a result of anti-dumping duty in force, which merely justifies continued imposition of such duty. The only relevant parameters in such reviews are the fair selling price of the domestic industry and landed price of imports so as to ascertain the existence of injury margin. As may be seen from the costing information provided by us, the injury margin has substantially increased in this case, thereby necessitating imposition of higher duties.
- Price undercutting: The dumped imports are undercutting the prices in the Indian market. The landed price of imports from Korea has been significantly lower than the selling price of the domestic industry and the Non-injurious price even after imposition of anti-dumping duty on imports from Korea. The landed price of imports from Germany is lower than the Non-injurious price for the domestic industry.

The Injury incurred by the domestic industry is evident from some of the following facts:

- a) Substantial capacity available with the exporters in the subject countries given that the domestic market is not big enough to absorb all their production and enhanced capacities which have become available after the previous investigation period.
- b) Imports are entering India at prices, which have a significant depressing effect on domestic prices. In spite of increase in the cost of production, we are not in a position to increase the selling prices.
- c) Imports are resulting in severe price undercutting and consequently the domestic industry is not able to sell at its fair selling price.



- d) The domestic industry has not been able to improve its operating margins in spite of imposition of anti-dumping duty.
- e) Stock with the domestic industry has piled up. The industry as a result was forced to decrease its production of NBR.
- f) Capacity utilisation of the industry has remained sub-optimal. The industry has been forced to make other products to increase the utilisation of the plant.
- g) Domestic industry's market-share has been low and is likely to decline further in case the anti-dumping duty on imports from Korea is not appropriately enhanced.
- h) Employees of the domestic industry are demoralised as a result of continued dumping of the product in the market.
- i) The domestic industry's lack of profits are hampering its growth. The promoters have done their utmost in investing funds for increasing the competitiveness. However, with the continued dumping, the investments being made will be un-remunerative. Also, no fresh investments would be possible thereafter since investors will not be confident of their returns.

#### **DUTY ON VARIABLE BASIS**

It is requested that the revised duty may be recommended on variable basis in terms of US \$. This would be appropriate in view of the following: -

1. There is considerable decline in the export price in respect of the exporter after the investigation period. This is in spite of no significant decline in the associated raw material costs. Thus, the dumping has intensified in the post investigation period. The whole purpose of variable duty being check on intensified dumping, the variable duty would be most appropriate basis.
2. The customs duty on this product has also declined after the investigation period. The duty may decline in future. One of the purpose of variable duty being to check injury to the domestic industry due to decline in the customs duty, it would be appropriate to have variable duty.
3. The Designated Authority has already imposed variable duty on this product in case of imports from Japan in the sunset review investigations. Thus, the last investigations on this product had variable form of duty.
4. The Designated Authority had recommended variable duty in the past on Acrylic Fibre, a product having significant consumption of Acrylonitrile, which is one of the major raw materials in this case.
5. The export price of the exporter have not proportionately changed with the changes in the associated raw material costs. The enclosed table demonstrates that the exporter has absorbed changes in the cost of production on account of raw materials to a very significant extent.
6. The Designated Authority as also CEGAT has held in various cases that variable duty is appropriate benchmark to handle the situation of intensified dumping.

In view of the above, it is prayed that the final duties may kindly be recommended in terms of US \$ on variable basis.

**Non injurious price**

We have no comments on the non injurious price of Rs. \*\*\*\* determined by the Designated Authority.

**2. IMPORTER'S VIEWS****a) PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE****1. The following submissions have been made by All India rubber Industries Association:-**

- (i) Apar do not produce all grades of NBR which are produced by M/s KKPC and as well as by M/s Bayer. Apar's NBR grades are also not like article to the NBR grades produced by KKPC and Bayer as well as there would be a need to depend on imports.
- (ii) There is no justification in imposition of anti dumping duty on such grades of NBR which are not produced by Apar industry

**2. The following submissions have been made by All India Federation of RubberFootwear Industries:-**

- (i) Apar does not produce all grades of NBR as produced by KKPC and Bayer.

**3. The following submissions have been made by Small Scale Rubber Industries Association of India:-**

- (i) The Authority must also examine the specifications and chemical composition of various types of NBR produced by the Domestic Industry

**b) INJURY****1 The following submissions have been made by All India Rubber Industries Association:-**

- (i) M/s Apar has claimed that DGCI&S data is not reliable and have urged to depend on PPR data. Association urges Designated Authority to rely on the official DGCI&S statistics for the analysis.
- (ii) The market share of the Domestic Industry has increased from 28% in 1994-95 to 52% in 2000-2001 and their production has gone upto 2452 MT in 1994-95 to 5280 MT in 2000-2001 which proves that there is no injury to the Domestic Industry by way of exports from KKPC and Bayer.
- (iii) The high cost of production of NBR by Apar are solely related to their multi-product plant and due to inefficient operation of the plant, high raw material cost due to limited range of products and without any control on the volatility of the market and uneconomic plant capacity

- (iv) Designated Authority should consider all the applications of the Domestic Industry for imposition of anti dumping duty on various grades of synthetic rubber because of the transfer of the capacity and production from one item to another.
- (v) Apar have jacked up various prices by more than 80% and there is no injury to them.
- (vi) The non-injurious price for Apar would now be lower has they have increased their plant capacity and improved upon their claims for utilities and there would be no injury in the forthcoming period by the imports from KKPC and Bayer.

**2. The following submissions have been made by All India Federation of Rubber Footwear Industries:-**

- (i) Apar has increased their capacity, but is not sufficient to meet the demand of NBR.
- (ii) We request Designated Authority to depend on DGCI&S data for analysis and not on the PPR data as claimed by Apar.
- (iii) Apar has sold material above the non-injurious price and made made good profits.
- (iv) The landed price of German NBR is higher than the Apar ex-factory selling price even without taking into account the anti dumping duty and that imports of NBR from Germany have declined and their prices have increased.

**3. The following submissions have been made by Small Scale Rubber Industries Association of India:-**

- (i) The review period of investigation should be changed suitably to cover upto 30.9.2001 so as to reflect the present position. The individual cost of the Domestic Industry is far less now and M/s Apar Industries Ltd. had made huge profits.
- (ii) M/s Apar's performance has been excellent and there exists no causal link for the injury caused due to imports from the subject countries.
- (iii) M/s Apar's capacity remains low and is not cost effective and profit worthy.
- (iv) Apar produces NBR and a few other items which do not have the advantage of manufacture of a large diversified range of products with a result that they have to depend on the volatility of the prices of the raw materials and have no control on the prices of the inputs/sales, loosing out on the price front to the international manufacturers.
- (v) Apar's plant is located at a place which involves substantial transportation cost of raw materials and other overheads.
- (vi) Apar industry should submit detailed account of production figures, sales, cost of production etc.
- (vii) Apar must come with detailed information indicating the production of various types of rubbers such as NBR, SBR and HSR.
- (viii) A team of Cost Accountant, Chartered Accountant, Engineers and process analyst must be formed to examine/investigate the matter in depth and submit the Report before the Anti Dumping Authority.

**OTHER ISSUES****1     The following submissions have been made by All India Rubber Industries Association:-**

- (i) The Anti Dumping Authority did not follow the appropriate procedure for holding the public hearing on 7.12.2001.
- (ii) M/s Rishiroop Polymers Pvt. Ltd. have apprehension that they cannot get a fair and impartial decision from the Authority and have requested the Authority to step aside from this investigation and have asked the Government to nominate another Designated Authority who will hearing their case de novo. We support the stand of M/s Rishiroop Polymers Pvt Ltd. for fair and quick opportunity to be provided both to the representatives of the Domestic Industry as well the consumer industry.

**2.     The following submissions have been made by All India Rubber Industries Association:-**

- (i) The production by the Domestic Industry will not be able to meet the total demand of NBR in the country since there is an annual growth of 6.67% of the demand of NBR.

**3.     The following submissions have been made by Small Scale Rubber Industries Association of India:-**

- (i) Continuance of anti dumping duty on the basic inputs of rubber industry will open floodgates of imports of finished rubber products and will be extremely difficult for Indian rubber manufacturers to keep their foothold in the domestic market.
- (ii) The consumer industries would appreciate a fair trade war between the Domestic Industry and the exporting industry and the fair competition must not be closed. A team of Cost Accountant, Chartered Accountant, Engineers and process analyst must be formed to examine/investigate the matter in depth and submit the Report before the Anti Dumping Authority.

**3.     EXPORTER'S VIEWS****1.     M/S KOREA KUMHO PETROCHEMICAL CO. LTD. (KKPC), KOREA RP****a)     PRODUCT UNDER CONSIDERATION & LIKE ARTICLE :-**

- (i) M/s Apar does not produce all grades of NBR which are produced by M/s KKPC and M/s Bayer and that Apar's grades are not like article to the grades produced by KKPC and that the matter is also sub-judiced before the Delhi High Court.
- (ii) There are several grades of NBR such as Carbo Oxylated NBR which are not produced by M/s Apar Industries and that there should not be any anti dumping duty on these grades.

**b) DUMPING.**

- (i) M/s KKPC has filed the exporter questionnaire and have provided data on the cost of production of various grades of NBR, domestic selling prices of grades sold in domestic market and the export prices to India and other countries during the Period of Investigation (POI).
- (ii) M/s KKPC has claimed adjustments on the domestic selling prices on account of packing and inland freight to the extent of \*\*\*\*\$/MT and \*\*\*\*\$/MT respectively.
- (iii) M/s KKPC have also claimed adjustments on the export price to India on account of inland freight, ocean freight, ocean insurance, duty drawback and packing and commission to M/s Rishiroop Polymers Pvt. Ltd. to an extent of \*\*\*\*\$/MT, \*\*\*\*\$/MT, \*\*\*\*\$/MT, \*\*\*\*\$/MT, \*\*\*\*\$/MT and \*\*\*\*\$/MT respectively. M/s KKPC has also indicated that their exports to India are made to the wholesalers whereas the sales made by M/s Apar Industries Ltd to the end users and adjustments on account of this level of trade to an extent of \*\*\*\*\$/MT should be considered.
- (iv) The exporter has also provided information pertaining to SGA expenses, R&D expenses and interest charges as sought for during the verification conducted on 23-24<sup>th</sup> August, 2002 at M/s KKPC's premises at Seoul. M/s KKPC vide their letter dated 27<sup>th</sup> August, 2002 and in response to the Authority's letter dated 10.6.2002 and have indicated their explanation pertaining to their domestic sales in certain cases being in US dollar, exports sales being on sight basis, type of packing, handling charges on exports to India, clarifications on SGA expenses and consumption norms and financial expenses in the cost of production.
- (v) M/s KKPC had also sought adjustments on account of small volumes sold in the domestic market and on large volumes sent to India without any technical support. The adjustments of 7.5% for difference in this level of trade has been sought.
- (vi) It is indicated that M/s Apar continues to mislead the Authority on the constructed cost of production for KKPC. The dumping margins for M/s KKPC presented by Apar are inflated and misleading.
- (vii) M/s KKPC have also indicated that there has been no dumping during the Sunset Review POI and have highlighted the method of allocation of selling and administrative expenses to be considered for evaluating the cost of production for M/s KKPC.

**c) INJURY**

- (i) M/s KKPC has also in response to the Authority's letter dated 10.6.2002 provided views regarding Injury to the Domestic Industry indicating that there has been a significant decline in the exports of NBR to India during the Sunset Review Period and that there was no likelihood for substantial increase of exports into India from KKPC. It has also been indicated by M/s KKPC that they do not have any freely disposable capacity or plan for expansion of capacity in immediate future. It has also been indicated that exports price from M/s KKPC to India has increased during the Sunset Review POI and coupled together with the depreciation of the Indian currency during the POI. It has also been indicated

that M/s KKPC does not have any excess inventories of NBR for disposal or export to India.

- (ii) It is submitted that While evaluating the Apar's economic status for their NBR plant, the Authority should adjust/discount the installed capacity pertaining to capacity operating cost, return on investment etc. for the quantum of HSR produced by them at their Walia plant where they make their NBR from the total cost of operations. Therefore there is a need to examine as to how the various costs and capacities have been apportioned by the Authority for their NBR and HSR operation at Walia. The interest cost for M/s Apar to make and sell NBR calculating for its Non-Injurious Price should be reworked since it works out to only 3.85%. The Authority should uniformly apply the principle for determination of NIP for NBR made by Apar by taking their cost of production and adding a 5% profit. The non-injurious price should be calculated on the expanded capacity of Apar.
- (iii) The price data of new grade of ANB-35L introduced by Apar in review POI should be excluded from the analysis of selling price of Apar.
- (iv) Apar had incorrectly submitted that they are not having profits from their operations of NBR and hide the facts and that there is no evidence of injury to them.
- (v) M/s KKPC have also indicated methodology to determine the NIP for M/s Apar Industry.
- (vi) M/s Apar has given various official statistics on import data from DGCI&S and PPR. We request the Authority to give a clear findings on the subject matter when it publishes its final findings so that very basis of its analysis is not distorted and a consistent practice is followed even though it may not be perfect

d) **OTHER ISSUES**

- (i) Importer has mentioned that the appropriate procedure was not followed for holding the public hearing indicating that the Designated Authority was not available during the hearing and that the meeting was delayed. The Authority also indicated from any side stated that the doors of CEGAT and High Courts are open to anybody who were unhappy with the Authority's decision. M/s Rishiroop Polymers Pvt Ltd., representing M/s KKPC have also quoted Article 6.3 of WTO related to the matter.
- (ii) The findings should be completed within end of January, 2002.
- (iii) The NBR demand for all grades by 2006 would be about 17336 MT per annum and that there is going to be a demand-supply gap for NBR in India.
- (iv) There exists no provision in any Indian law for any adjudicating Authority to levy anti dumping duty in currency other than India rupee and therefore levy of anti dumping duty should not be indicated in dollar terms.

**In response to the disclosure, the following submissions have been made by**

**M/s KKPC:-**

**Preliminary objections:**

- The Disclosure statement is not signed by Designated Authority and is invalid in law. Rules 16 of Anti Dumping Rules and Article 6.9 of WTO and case relevant laws have been mentioned

- The Sunset review initiated in violation of Trade Notice 1/99 issued by the department is invalid in law as in the present case, an earlier review was completed on 20-7-2001 against which the revenue notification was issued on 7-9-2001 and the sunset review initiated on 1-10-2001, i.e., well within one year's time period. The Designated Authority ought to have known about this requirement and should not violate several case laws of the Apex court have been cited.
- The views of the Designated authority at the Public hearing were biased and proceedings at the public hearing were improper as Designated Authority had a prejudged mind set and asked 2 of the exporters to agree to give a price undertaking. This was also in violation of Article 8.2 of the WTO Rules.
- KKPC has also expressed that views that oral submissions are followed by written submission indicating that they can substitute oral submissions is not proper.
- *Article 6.2* and sub rule (6) of Rule (6) has been cited in this regard.

#### **Product under consideration and Like Article**

- As regards product under consideration, the decision on this subject matter is subjudice with the Supreme Court and that our appeal has been admitted by it and matter is pending for hearing. It is also admitted position of the domestic industry that they do not produce Carboxylated NBR and still the authority chooses to continue to levy the anti dumping duty on it. There is no justification for the same.
- The authority has every right to apply the anti dumping duty to a narrower class of products as compared to the original investigation based on additional information with it. Since APAR does not produce Carboxylated NBR, we request the authority to exclude the same from levy of any future anti dumping duty by refining the class of products of NBR for levy of duty. This would be consistent with the Authority's own decision in the matter of SBR anti dumping investigation wherein for the grades of SBR not produced in India during the POI, the authority had held that anti dumping duty was not to be levied. Same should be followed in the present case for Carboxylated NBR.

#### **NORMAL VALUE**

##### **Cost of Production of KKPC's NBR**

- The authority has incorrectly chosen basis of allocation and apportionment of costs on cost of sales of manufactured goods basis. KKPC recognizes from the disclosure statement that the Authority has decided to determine the cost of production and allocation of expenses for interest and SGA based on the ratio of cost of sales. KKPC cannot accept the same. The basis of cost allocation and apportionment followed by KKPC is in accordance with the Korean GAAP law and, furthermore, this basis of cost allocation by KKPC has also been consistently followed by KKPC and it has been previously accepted by the Authority in its previous investigations for NBR (original in 1997) as well as the SBR anti dumping investigation. Article 2.2.1 and Rule 1 of the WTO has been cited.

- The authority should accept KKPC's methodology for cost allocation since these are based on the basis of records kept by it and followed consistently for several years and are in accordance with the generally accepted principles of accounting in Korea. These records also reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the articles under consideration. The officers of the department who had visited KKPC's office for verification had stated that KKPC's methodology for cost allocation based on ratio of quantity of NBR produced to total quantity of all products made by the company after deducting the SGA for trading and indenting sales is inappropriate as for one item, namely, steam the SGA costs are disproportionate to its selling price. That may appear to be the case, but it is a policy adopted by KKPC and KKPC has consistently followed the cost allocation method since long time. This cannot be the reason to reject KKPC's method of cost allocation as it is acceptable in Korean standards.
- Notwithstanding our objection to the methodology for cost allocation adopted by the authority, for argument sake and without prejudice, the following is submitted:
  - a) The Authority has not allocated any SGA cost for trading sales and indent sales.
  - b) KKPC has requested the authority to allow the apportionment of SGA expenses for trading sales at Won \*\*\*\* and for indent sales expenses at Won \*\*\*\* before apportioning any costs to NBR production.
  - c) KKPC does not agree with the disallowance of advertisement expenses, commissions and R&D costs. The same have been elaborated, indicating that  
for the Commission expenses, in fact the authority is silent in the disclosure statement. That is no reference to it at all. This adjustment is legitimately claimed as it would tantamount to double accounting if this is not deducted from the SGA expenses as it is considered separately as post ex factory cost whilst determining the same from the CIF price of the sale of NBR to India.
  - d) KKPC has already submitted in its earlier letter to the authority that it did not incur any expenses for advertisement in India for sale of any of its products during the POI. The advertisement expenses incurred by KKPC during the POI as reflected in the SGA list as solely for the sales promotion in the domestic market and have no bearing on the export sales of NBR to India. In order to arrive at like for like comparison of apples to apples comparison of price at ex Factory level between cost for domestic sales and for export to India of the NBR produced by KKPC this adjustment of advertisement expenses should be allowed by the authority.
  - e) As regards R&D expenses, KKPC submits that at the very least the authority should consider to allow at least 50% of the R& D expenditure allocable to KLESL center where research work is only being carried out on life sciences and which we categorically submit has no correlation to any synthetic rubber business of KKPC.
  - f) Valuation of transfer price for BD captively produced and consumed, is incorrect. KKPC has consistently followed the practice of valuing all its captively consumed



products at the cost of ex Factory production cost and not on sales cost. This practice is in accordance with the Korean GAAP laws and also it is in accordance with the Indian costing rules followed by the Indian Government itself. Section 209 of the Companies Act has been cited

- g) Ratio of 55.65 % of assets deployed taken by authority for allocating the interest cost for operations is incorrect. KKPC request the authority to reconsider its decision to allocate 55.65% of the funds deployed towards production activities as against KKPC's allocation of 46.5% for the production activities
- h) Assessment of Cost of Production of NBR produced by KKPC is incorrect. KKPC had submitted data to the authority showing the ex factory cost of production at USD 977.53 per MT. As against this the authority has worked out the cost of production at USD 1079.39 per MT based on the main differences resulting from the raw material costs ( BD transfer pricing), interest cost and SGA costs. Thus the authority has inflated the cost of production by USD 101.86 per MT. The authority has not stipulated its methodology deployed for excluding some of its domestic sales. No explanation has been offered in this regard. The authority in such cases is required to consider a price band whilst allowing some variation in price below the rated average cost of production. In this regard we object to the procedure adopted by the authority and request you to reconsider the same.
- i) Determination of Normal Value for KKPC's NBR sales is incorrect. The authority has adopted a unfair cut off level to exclude certain sales transaction in domestic sales if they fall below the figure of cost of production so determined by it without providing for a price variation band around that figure. The Indian Antidumping rules governing the determination of normal value are cited:

#### **Principles governing the determination of Normal Value.**

- The corresponding WTO Rule Article 2.2.1 for determination of normal value is also cited.
- In the confidential disclosure the authority is silent with regard to the adjustment to the commission but by interpolation we are presuming that the authority has forgotten to include it in the adjustments. This may kindly be confirmed. The authority has not allowed any adjustments in the level of trade for sales to India as it considers it as not being relevant for determination of normal value but appropriate for emanation of injury determination
- KKPC submits that the adjustment of duty drawback of USD 1.7/MT should be made to the cost of production and to the domestic ex factory selling price and not to the ex-factory export price since to provide for an apple to apple comparison it is the cost of the raw materials consumed for domestic sales which need to be reduced by USD 1.7/MT and not the post production cost as has been adjusted by the authority.

## INJURY DETERMINATION FOR APAR

- The authority has not revealed in index form its determination of the assessed economic parameters as required under the rules. The authority has simply published index extracts from the submissions made by the domestic industry and has not published in index form or otherwise its comments on all the economic factors for the domestic industry for the POI as compared to the previous years. a separate assessment is required to be made by the authority for determination of factors other than imports from KKPC which are causing or may be causing injury to the domestic industry.

### *Principles for determination of injury (ANNEXTURE II)*

- Rule (V) and Article 3.5 have been cited.
- It is reiterated that some of the major factors causing injury, if any, to the domestic industry other than imports of NBR from KKPC are:
  - 1) Imports from other countries simultaneously being subjected to antidumping duty such as Japan, Taiwan, etc.
  - 2) Imports at similar price level as that from KKPC from countries not subject to any antidumping duty.
  - 3) Substantial reduction in custom duty from the original POI to the sunset review POI thereby resulting in a substantial reduction in landed value of the goods.
  - 4) Small operational capacity of the domestic industry vis-à-vis all other international competitors
  - 5) Improper location of plant site by increasing cost of BD.

We request the authority to arrive at separate and distinctive quantifiable findings from factors other than imports from KPPC which are causing or may be causing injury to the domestic industry in accordance with the governing rules cited above.

- **Causation and Non –Attribution – Article 3.5 of WTO is required to be followed, WTO case laws have been cited.**
- In support of their submission that there is absence of any causal link between the imports from KKPC and the alleged injury, if any, to the domestic industry, the calculations indicating injury due to KKPC's exports and as per factors of Designated Authority has been done for appropriate consideration.
- **Utilization of concept of landed value including custom duty without adjustment for variation in customs duty to original POI for determination of injury margin invalid in law. Injury incidence due to fall in custom duty has been submitted.**

- The Indian rules governing the antidumping investigation require the authority to recommend levy of any antidumping duty only in the event of its arriving of injury findings. The relevant Section 9B, 11(2) and Rule has been cited
- Throughout our various submissions we have clearly shown to the authority that all the economic parameters as required to be evaluated for any injury determination are positive for APAR for the POI. It appears that the only issue that is in the mind of the authority is on the aspect of profitability. We would like to remind the authority that it has been empowered to take action solely for “trade distortion” and to that extent only and it is not to the forum for “trade protection” or for “assurance of profitability” to any domestic industry.

#### **Adjustment for level of trade/differences in conditions of sale/taxes**

- We had requested the authority to make due adjustment for the difference in the level of trade between KKPC’s sale to Indian customers and APAR’s sale to its customers in order to make a fair comparison of the price of the imported goods to the end user with that of the price from the domestic industry.. We request the authority to make this adjustment whilst assessing the injury margin and in determination of the so called price undercutting effect as well
- In view of the foregoing, we request the authority to kindly allow this adjustment and to take into account the net impact of such sales through intermediary level in the supply chain to the customer. We reiterate that this would be appropriate for making an apple to apple comparison as APAR sells its product directly to the end user and it does not charge any sales tax to its customers as they are exempted from the same for a period of 15 years from the start of commercial operations due to incentive given by the Government of Gujarat to them.

#### **Adjustment for 4 % Special additional duty (SAD)**

- We submit that we had made a claim with the authority for adjustment for the 4 % Special additional duty paid by the importers of NBR from KKPC which is normally supposed to bring level playing field between the domestic producers and exporters. In the present case, however, since APAR has special incentive of no sales tax on its sales this SAD tax constitutes a disadvantage to the importers of NBR vis-à-vis APAR’s sales of NBR. Article 2.4 of WTO rule as under for making adjustment for “differences in conditions of sale”:

#### **Interest of consumers and community at large to be considered.**

- From the analysis of the statistical data it will be clear that as against an estimated market demand of about 13,000 to 14,000 MT of NBR in sunset POI, APAR has sold only about 5100 MT which is about 40% or so of the market. Approximately 60% if the end users are, therefore, forced to pay anti-dumping duty for their imports from one source or the other. APAR is operating at about 115% of their production capacity so the authority ought to see the larger community interest as well whilst arriving at any affirmative determination of levy of anti dumping duty.

**Levy of any anti dumping duty in terms of US Dollars is illegal**

- It is our submission that the levy of any anti dumping duty based on any foreign currency such as the US Dollar is not lawful. This matter has already been taken up by us under an appeal which is pending with the Honorable Supreme court and we do not elaborate on it here

**2 HYUNDAI PETROCHEMICAL CO. LTD.****a) DUMPING**

- (i) From our past experience, we decide not to furnish the information in the prescribed format.
- (ii) There are only two exporters of NBR in Korea, viz KKPC and Hyundai Petrochemical Co. Ltd. Before the Designated Authority published its final findings on 17<sup>th</sup> July, 1997, we represented to the Authority that we had commissioned NBR production plant in October, 1996 and do not produce nor have exported any quantity to NBR in India during the first initial period of investigation.
- (iii) The Authority should have acknowledged in the preliminary findings dated 30.12.1996 and also in final findings dated 17.7.1997 that during the POI there was only one manufacturer viz. KKPC from Korea RP. Despite our oral and written submissions, the Authority recommended imposition of anti dumping duties at the rate of 8975 Rs/MT. The anti dumping duty if at all should have been applicable to NBR produced by KKPC whereas Hyundai Petrochemical should have been kept out of the imposition of anti dumping duty for the simple and clear reason that during the POI it did not export any quantity to India.
- (iv) The Hon'ble CEGAT vide its order dated 22.2.2000 has modified the duty to dollar form and the Authority should have modified the anti dumping duty in dollar form only for KKPC. Hyundai Petrochemical however did not contest the above notification and findings of the Designated Authority.
- (v) During the mid-term review vide Notification No 27/1/2000-DGAD dated 20.7.2001, the Authority reduced the anti dumping duty from 264 \$/MT to 248.35\$/MT for KKPC whereas recommended imposition of highest ever anti dumping duty of 679 \$/MT from 264 \$/MT for us. This enhancement has been made despite the fact that we exported at prices higher than KKPC.
- (vi) Our exports to India were for negligible quantity of 600 MT which is far less than 10% of the total consumption of NBR in India.
- (vii) M/s Apar do not manufacture NBR grades equivalent to ours as the major application of NBR in India is for production of rice rolls constituting more than 50% of NBR production. Our NBR is not used in the rice rolls application at all.
- (viii) During the Sunset Review we have sold a total quantity of 600 MT on NBR constituting of different grades. We have however not sold any NBR since imposition of highest anti dumping duty of 679 \$/MT.
- (ix) The various facts and circumstances therefore compel us to believe that there is no use to submit information in the prescribed format

a) **INJURY**

- (i) The exports of NBR from Bayer have reduced in quantity substantially from 2034 MT in 1996-97 to 467 MT in POI.
- (ii) Our average CIF prices have also increased during the current period of investigation as compared to the initial period of investigation for which the anti dumping duty was levied.
- (iii) During the current POI, the prices of NBR from Bayer was higher than the domestic industry's ex-factory selling price without considering the anti dumping duties. There is no prima facie evidence for review of anti dumping duty at Bayer AG's exports price but there is a warrant to remove the whole of anti dumping duty of 110 64\$/MT in force at present.
- (iv) Capacity utilisation for Domestic Industry has improved significantly from 34% in April, 1994-95 to 84% in the present POI. From the Domestic Industry's Annual Report, it has been seen that for the years 1994-95 onwards it has made profits whereas in the year 2000-2001 there has been a net loss which has been indicated to be temporary on account of squeeze in margins due to intense competition and the abnormal rise in cost of raw materials and interests. Further even during the period, the cash flow from operating activities was positive.
- (v) Considering all these facts, Designated Authority should examine as to what extent NBR business could be contributed to their performance.

❧

**C. EXAMINATION BY AUTHORITY:**

The foregoing submissions made by the various interested parties, to the extent these are relevant as per Rules and have a bearing upon the case, have been examined, considered and dealt with at appropriate places in these findings.

**1. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE AND DOMESTIC INDUSTRY**

The Authority notes the submissions made by the various interested parties on the product under consideration and the like article. The Authority also notes that the present Sunset Review conducted as per Section 9A(5) of the Customs Tariff Act, 1995 is with reference to the existing Anti Dumping Duties which were first recommended vide the preliminary findings dated 30.12.96 and thereafter confirmed vide final finding dated 17.7.1997. The Anti Dumping Duties were also continued vide Customs Notification No 91/2001 dated 7<sup>th</sup> September, 2001 in a Midterm Review and presently levied vide Custom Notification No 61/2002 dated 7.6.2002. The Authority in the Disclosure Statement had proposed to confirm the scope of the product under consideration as already settled in the earlier main investigation. The Authority notes that though submissions pertaining to like article have been made by some of the interested parties, they are not supported with evidence showing non-interchangeability as far as the like article and scope of the product under consideration is considered, which in the main investigation has already been settled to cover all the grades of NBR. It has however been mentioned by M/s KKPC that certain goods like carboxylated grades are not manufactured by the

Domestic Industry and be excluded and that this issue is also subjudiced in the court of law. However it is noted that M/s KKPC has not exported the carboxylated grade but have exported only KNB 35L grade while have demanded exclusion of the carboxylated grade. The Authority has in all its earlier investigations for subject goods from these subject countries have considered all grades of NBR within the scope of investigation and this being a Sunset review reiterates and reconfirms the product under consideration as “Acrylonitrile Butadiene Rubber, also known as Nitrile Rubber and NBR as indicated in original finding dated 30.12.1996. NBR is mainly used for manufacturing various rubber articles such as Oil Seals, Hoses, Automotive products, Gaskets, Rice Dehusking Rolls, Printers fabrics, Oil field products. The Domestic Industry supplies the subject goods to various users viz rice rolls, moulded and extruded auto and industrial parts, seals, hoses, automotive components, oil seeds, O rings, automobiles hoses, bellows, fuel tubes, fuel hoses and railway and defence products. The Authority recalls and confirms the product under consideration as also indicated in the initial preliminary findings under Para E(1) and E(5) and Paras F(4) and F(5) in final findings dated 17.7.1997.

As regards the standing of the Domestic Industry is concerned M/s Apar Industries Ltd. is the sole producer and represents the Domestic Industry as per Rule 2(b) of the Anti Dumping Rules.

The Authority therefore reconfirms the scope of product under consideration and like article as indicated in the main investigation earlier and holds that the goods exported from South Korea and Germany as like article to the goods manufactured by the Domestic Industry as per Rule 2(d).

## **2 NORMAL VALUE AND EXPORT PRICE**

### **DUMPING MARGIN, NORMAL VALUE AND EXPORT PRICE**

#### **KOREA RP**

#### **A. M/S KOREA KUMHO PETROCHEMICAL CO. LTD(KKPC)**

#### **NORMAL VALUE**

The Authority recalls its observations in the disclosure statement and reiterates that arguments/submissions made by M/s KKPC on various aspects of computation of their cost of production for the various grades of NBR sold by them in the domestic market during the POI have been considered appropriately. The submissions/data furnished during on the spot verification on 23-24<sup>th</sup> August, 2002 and the submissions made by them in their main/supplementary response to the questionnaire and the clarifications offered by them to the Directorate subsequent to the verification have been appropriately considered. The Authority notes the claim of SGA and interest of the exporter regarding apportionment on the production basis does not appear to be justifiable and logical keeping in view the costing principles governing such apportionment in case the company is producing heterogeneous products with wide variations in the per unit cost and the sales realisation. Thus the Authority in disclosure statement proposed to apportion these costs on the basis of cost of sales.

As regards R&D expenses, the Authority notes from the company's literature/brochure provided during the on spot verification that the R&D activities are relevant for all the products including NBR. Further the details on grade-wise cost of production of NBR shows that the company has incurred substantial amount of R&D expenses on NBR also. Thus these have been considered as part of the SGA expenses. The claim regarding exclusion of bad debts was proposed to be considered by the Authority as the same is not related to NBR. Similarly the claim regarding amortization of intangible assets was also proposed to be considered by the Authority as done for bad debts as indicated above.

As regards the advertisement expenses, it was mentioned in disclosure that the exporter has not been able to substantiate its claim for exclusion of the expenses related to the advertisement. Hence the same was not proposed to be considered by the Authority.

As regards the interest expenses, the exporter has worked out the percentage of funds available to the production activity by excluding funds related to investment activities. Against the claim of exporter of \*\*\*\*% of funds applicable to production activities, the Authority has assessed the same as \*\*\*\*% after considering of investments made in non-production activities. For allocation of interest to production activities, the exporter has considered net interest cost after deducting interest income. This claim was indicated to be proposed to be considered since the interest income relates to the investment activities of the company and not the production activity. The total amount worked out for SGA and interest has been allocated to different products on the basis of the cost of sales. It has been observed that the transfer price of captively produced and captively used Butadiene does not take into consideration the incidence of SGA and interest although for allocation of SGA and interest the incidence of cost of sales related to Butadiene has been considered in the denominator to arrive at the share applicable to various production activities. Accordingly based on the consumption factor of captively produced and used Butadiene in the production of NBR, the incidence of SGA and interest was proposed to be duly considered. The Authority had noted that the exporter has provided weighted average domestic selling price of all grades for determination of Normal Value. The cost of production has also been provided by the exporter on the weighted average ex-factory basis for all grades. It was observed by verification team during the on the spot verification of exporter that there is a narrow band of variation in the cost of production for various grades and keeping in view that this is a Sunset Review, the methodology of weighted average to weighted average grade comparison as done earlier was indicated to be adopted for the purpose of evaluation of normal value, cost of production and the export price to India.

In order to evaluate the normal value for the domestic sales, the Authority had excluded all those transactions which have not been made in the ordinary course of trade after evaluating weighted average cost of production as indicated in the para above. After excluding such transactions, the weighted average normal value during POI was indicated as \*\*\*\*\$/MT.

The Authority had proposed to reference the normal value as \*\*\*\*\$/MT. Confidential disclosure was made available to the exporter.

### EXPORT PRICE

As regards the evaluation of the ex-factory export price, the Authority proposed to consider the adjustments claimed by the exporter on ocean freight, ocean insurance, inland freight, packing, commission to agent viz M/s Rishiroop Polymer Pvt. Ltd. and duty drawback. The Authority however noted that in case of inland freight claimed on exports to India, there were certain exports made through another port viz. Busan Port also as was indicated by the exporter to the verification team during on the spot verification. Accordingly, the inland freight is proposed to be considered as \*\*\*\*\$/MT.

The exporter had claimed adjustments on account of their level of trade in the domestic market and also the exports made to India. However during on the spot verification, the exporter has foregone their claim as far as the level of trade in the domestic market vs. the exports to India is concerned. Since the domestic market sales were also made both to actual users and the distributors/wholesellers. However they have now submitted that in view of the exports by them to India made to wholesalers unlike the sales made by the Domestic Industry which are at the end user level, they have quantified an adjustment on account of this level of trade. The Authority had indicated that since level of trade adjustments in domestic market and export market has not been claimed and could not be evidenced, the question of considering this adjustment for the purpose of Normal Value does not arise. As regards their claim on level of trade for exports to India is concerned, it was indicated that it can be examined only for the purpose of injury determination as per the Anti Dumping Rules and the consistent practice followed for injury evaluation for industrial products by the Authority.

As regards the adjustments on packing, the Authority indicated that there is a variation in the amount of packing cost claimed for exports to India and that claimed for domestic sales and exports to other countries. Two different types of packing have been used for the domestic and exports sales to India, viz box type and bag type respectively. The Authority on the basis of the evidence provided by the exporter during on the spot verification have considered the packing expenses on exports to India as claimed on the basis of the evidence produced. However after reconciling of the packing expenses with the Profit & Loss Account, adjustments have been considered to an extent of \*\*\*\*\$/MT as far as the domestic sales packaging are concerned were indicated in the confidential disclosure to the exporter.

On the basis of the above, the ex-factory export price was indicated as \*\*\*\*\$/MT and the dumping margin as 10.6%(\*\*\*\*\$/MT)

As regards the comments offered subsequent to the disclosure by the representative of M/s KKPC, the Authority has carefully examined the same as under -

- 1 The argument of the exporter that they are historically using the basis for allocation of SGA and interest on quantity basis could not be substantiated by KKPC during the course of verification from basic records as they maintain



product-wise cost upto cost of sales only and not afterwards. During the course of verification this was duly explained to KKPC that the methodology for cost allocation based on ratio of quantity of NBR produced to total quantity to all products is inappropriate as for one item namely steam the SGA cost is disproportionate to its cost and selling price. The exporter has agreed to the argument in his response to the Disclosure Statement. On quantity terms the steam constitutes more than 70% of the total production whereas in terms of cost of sales the same constitutes about 7% only. Treating steam and other products at par on quantity basis for allocation of SGA and interest is not appropriate. Accordingly, cost apportionment of SGA and interest on the basis of cost of sales was considered appropriate and the same is adopted by the Authority.

2. The exporter has himself accepted that the trading sales and indent sales for foreign suppliers from whom it received indenting or offer sales commission do not get reflected in KKPC's books of accounts. Accordingly, it is difficult to assess the SGA on the basis of sales value. Further, the sales value does not reflect the true and fair value especially in case of NBR which is claimed to be dumped by the exporter. Therefore, the Authority has considered appropriate to adopt the cost of sales as most appropriate basis of apportionment/allocation of SGA and interest in the present circumstances.
3. The argument that the Authority disallowed certain adjustments on account of advertisement expenses commission and R&D expenses for determination of net SGA expenses has been examined. It is observed that the Authority considered the claim of KKPC with regard to commission and excluded the same while determining the net SGA cost. With regard to advertisement expenses the Disclosure Statement is clear as to why the same has been considered as part of SGA. With regard to research and development expenses the exporter could not substantiate his claim and now he has stated that in cost statement the R&D expenditure is mistranslated in English. M/s. KKPC, now based on some hypothetical assumption, has desired to at least consider 50% of the R&D expenses only. Since no basis has been given for such assumption it is not possible to accept the argument of the exporter in this regard.
4. The argument of KKPC regarding incorrect valuation of transfer price for Butadiene captively produced and consumed by considering share of SGA does not hold as for assessing the share of SGA and interest applicable to NBR the total cost of sales of all products has been considered by also adding the captively produced and consumed raw materials and utilities. Since the SGA and interest has been allocated on total cost of sales, share applicable to Butadiene (captively produced and consumed) should be added to arrive at real transfer value of the raw material.
5. The ratio of assets deployed for production activity has been properly considered by excluding non operational deployment of the funds from the total funds deployed by the Company as at March, 2001. The hypothetical basis of distributing quick assets constituting cash and bank balance and short term loans of 50:50 basis was not substantiated and hence could not be accepted.
6. The cost of production has been properly assessed by the Designated Authority as indicated above.
7. The Authority has determined normal value by applying ordinary course of trade test as prescribed under the Annexure 2 of the Anti Dumping Rules.

The Authority also notes that the representative of M/s KKPC has sought clarification regarding adjustment on commission on export price and have desired to consider the duty drawback adjustments on the Normal Value. The Authority clarifies that the commission as claimed by the exporter has been considered for evaluation of the ex-factory export price and that the duty drawback adjustment has now been appropriately adjusted on the Normal Value rather than the export price as claimed, since this adjustment could either be made on the Normal Value or on the export price. The Authority also notes that in response to the disclosure statement, Domestic Industry has also raised issues pertaining to the evaluation of Normal Value for M/s KKPC. The Authority has considered the submissions and have appropriately dealt the relevant issues as illustrated below:-

1. With regard to the observation that the exporter maintains accounts on calendar year basis and the period of investigation is 2000-01 year, it is submitted that the exporter has provided complete information regarding Profit and Loss Account, Balance sheet and cost of production of different products manufactured including NBR during the period of investigation which has been considered appropriately
2. With regard to consumption of raw materials the company has furnished complete reconciliation of raw material consumption with books of accounts.
3. On comments on the packing cost it is submitted that the same has been duly reconciled with books of accounts. With regard to amortization expenses it is clarified that the same has not been considered since they are related mining activity of the company and not NBR.
4. The price of the captively produced and consumed Butadine have been duly adjusted to include cost of SGA and interest as applicable.

Also it was clarified to the representative of the exporter as also acknowledged by him that under the formulation of net interest cost in the disclosure, the Authority had actually intended to convey that interest income relates to the investments activities of the company and not production activity and hence the gross interest cost has been considered. The argument of the exporter in this regard has been appropriately examined and the Authority reiterates that the interest income relates only to investment activities and is hence excluded. The Authority further notes the submissions of the exporter that by virtue of this discrepancy in the disclosure, the same is invalid. The Authority here submits that purpose of disclosure is to bring out essential facts and also thereby address issues emanating from the response to the disclosure. The issues on methodology, factual inconsistencies etc. are to be appropriately resolved at this stage since it eventually leads to the final determination. The fact that Authority has clarified this to the exporter and it has been acknowledged, the Authority has provided the essential facts and invited the comments thereupon and have also considered these appropriately.

Thus the determination methodology on Normal Value as indicated in the disclosure with the issues raised as clarified now, is confirmed.

Accordingly the Normal Value comes to \*\*\*\*\$/MT and the ex-factory export price comes to \*\*\*\*\$/MT and the dumping margin as \*\*\*\*\$/MT(10.27%).

**B HYUNDAI PETROCHEMICAL CO. LTD.,**

**NORMAL VALUE**

The Authority notes that the exporter has not provided any response in the prescribed questionnaire on account of various submissions as indicated in the foregoing para. The Authority under such circumstances has no option but to construct the normal value on the basis of the best available information as per Anti Dumping Rule 6(8). The Authority therefore proposed to reference the highest domestic selling prices as indicated by one of the cooperating exporter, viz. M/s KKPC for the purpose of evaluating the normal value for M/s Hyundai Petrochemical Co. Ltd..

Since no response has been filed to the disclosure, the Authority, confirms the normal value as \*\*\*\*\$/MT.

**EXPORT PRICE**

As regards the export price, the Authority notes that the domestic industry has provided on the basis of the secondary sources, the transactions pertaining to exports made by M/s Hyundai during the POI to India. The Authority proposed to reference the weighted average CIF export price as provided by the domestic industry. The Authority also proposes to consider adjustments on account of ocean freight, ocean insurance, commission, inland freight, packing and port expenses on the basis of the information as made available by the Domestic Industry and also as evidenced/correlated from the data provided by the cooperating exporter.

As no response has been filed to the disclosure, the Authority confirms the ex-factory export price as \*\*\*\*\$/MT.

On the basis of the above, the dumping margin comes to 47.08%(\*\*\*\*\$/MT).

**C. OTHER NON-COOPERATIVE EXPORTERS/PRODUCERS FROM KOREA RP**

In view of no response to the disclosure, the Authority confirms the Normal Value and export price as under:-

**NORMAL VALUE**

The Authority proposes to reference the highest domestic selling price as evidenced from the data provided by M/s KKPC for the non-cooperative exporters/producers.

The normal value is therefore referenced as \*\*\*\*\$/MT.

### **EXPORT PRICE**

As regards the export price, the Authority references the least export price as evidenced from the data provided by the cooperating exporter and the Domestic Industry. The Authority considers adjustments as considered in case of M/s Hyundai Petrochemical Co. Ltd for determination of the ex-factory export price

The ex-factory export prices comes to \*\*\*\*\$/MT.

On the basis of the above, the dumping margin comes to 49.06%(\*\*\*\*\$/MT)

### **3. GERMANY**

#### **A. BAYER AG, GERMANY**

##### **NORMAL VALUE**

The Authority notes that M/s Bayer has not provided data as per the structured questionnaire but have indicated that the only cost change in their cost of production has happened on account of the cost of Monomers for which they have provided the price. As regards the other production costs, it has been indicated that the costs has not been changed by and large. The Authority in this regard notes that the midterm review recommendation was given vide Notification dated 17.7.2001. The Authority also notes that the same has not been challenged by M/s Bayer. The Authority has therefore adopted the same methodology as was done in the earlier review for determination of the Normal Value.

The Authority notes that the export price to India of NBR exported by M/s Bayer has increased in the present POI for the Sunset Review, even though the monomer prices have increased and consequently the normal value of M/s Bayer would also warrant an upward revision, the Authority proposes to reference the earlier Normal Value as determined during the past POI, which would be the best available information in the present circumstances.

The Normal Value on the basis of this comes to \*\*\*\*\$/MT. Since there is no response by the exporter to the disclosure, the Authority confirms the Normal Value as \*\*\*\*\$/MT.

##### **EXPORT PRICE**

The Authority notes that the exporter has provided the weighted average CIF price during POI along with the quantities exported to India. The Authority has therefore referenced the same for the purpose of determination of the export price. The Authority has on this CIF price considered adjustments on ocean freight, ocean insurance and commission as per the data provided during the earlier midterm review.

The ex-factory export price comes to \*\*\*\*\$/MT.

Since there is no response by the exporter, the Authority confirms the export price as \*\*\*\*\$/MT

On the basis of the above, the dumping margin comes to 24.87% (\*\*\*\*\$/MT)

#### **B OTHER NON-COOPERATIVE EXPORTERS/PRODUCERS FROM GERMANY**

As there is no response to the disclosure, the Authority has evaluated Normal Value and export price as under.-

##### **NORMAL VALUE**

The Authority notes that none of the exporters/producers from Germany have cooperated. The Authority under such circumstances therefore has referenced the normal value as determined for M/s Bayer AG only

The normal value therefore has been referenced as \*\*\*\*\$/MT

##### **EXPORT PRICE**

As regard the ex-factory export price, the Authority has referenced the least export price of M/s Bayer AG for the non-cooperative exporters/producers. The adjustments on export price as granted to M/s Bayer AG have also been considered for these non-cooperative exporters/producers

The ex-factory export price comes to \*\*\*\*\$/MT

On the basis of the above, the dumping margin comes to 44.11% (\*\*\*\*\$/MT).

#### **4. DUMPING-COMPARISON OF NORMAL VALUE AND EXPORT PRICE**

The rules relating to comparison provides as follows

“While arriving at margin of dumping, the Designated Authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-works level, and in respect of sales made at as nearly possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability.”

The Authority has carried out comparison of weighted average normal value with the weighted average ex-factory export price for evaluation of the dumping margin. While evaluating the Normal Value, the Authority has applied the ordinary course of trade test as per Rule 2 of the Annexure I to the Anti Dumping Rules.

Based on the normal value and the ex-factory export price as determined above the Authority has evaluated the dumping margin for the subject goods originating in or exported from the subject countries to India as follows -

Exporter/producer	Normal Value \$/MT	Export Price \$/MT	Dumping Margin(%)
<b>KOREA RP</b>			
1.Korea Kumho Petrochemical Co.	***	***	10.27
2.Hyundai Petrochemical Co Ltd.	****	****	47.08
3.All other exporters/producers	****	****	49.06
<b>Germany</b>			
1.Bayer AG	****	****	24.87
2.All other exporters/producers	****	****	44.11

The above dumping margins are above the de-minimus limit.

#### 5. INJURY AND CAUSAL LINK

The Authority notes that as per Section 9A(5) of the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 “the anti dumping duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition:

Provides further that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension:

Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of five years has not come to a conclusion before such expiry, the anti dumping duty may continue to remain in force pending the outcome of such a review for a further period not exceeding one year”

Also under Rule 11 supra, Annexure-II, when a finding of injury is arrived at, such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry, “.....taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles. ” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree

For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry as production,

capacity utilisation, sales quantum, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II(iv) of the rules supra.

Since under the present investigation it is to be evaluated as to whether cessation of anti dumping duties would lead to continuance or recurrence of dumping and injury, the Authority has considered appropriate injury parameters as indicated in Annexure II(iv) of the Rules supra to evaluate this aspect.

The Authority observes the various economic parameters pertaining to the subject goods for the Domestic Industry i.e. M/s Apar Industries Ltd. and imports of subject goods from subject countries as under:-

Economic Parameters	1997-98	1998-1999	1999-2000	POI (2000-2001)
Capacity(MT)	6250	6250	6250	6250
Gross NBR production(MT)	3785	4609	4990	5154
Effective production (MT)	4300	5366	5742	5360
Capacity utilisation based on effective production (%)	69%	86%	92%	86%
NBR indigenous sales (MT)	3149	3750	4073	4637
Gross block (Rs in lakhs)	4483	4534	5266	5865
Closing stock (MT)	183	279	380	172
Average wage per employee(Rs)	63095	66667	69645	81695
Maximum established demand(MT)	10142	9934	12372	10481
Total maximum imports (MT)	6693	6184	8299	5844
Share of imports of Korea in total imports (%)	33.59	48.42	53.45	48.58
Share of imports of Germany in total imports (%)	18	9.7	7.23	7.99
% of subject country imports in total imports (%)	51.59	58.12	69.68	56.57
% of imports from South Korea of total demands	23.16	30.14	35.86	27.09
% of imports from Germany of total demands	12.41	6.04	4.85	4.46
% of imports from subject countries of total demands	35.57	36.18	40.70	31.54
% of share of Domestic Industry in total demand	31.05	37.75	32.92	44.24

Net Sales	****	****	****	****
Realisation (Rs/MT)				
Cost of production (Rs/MT)	****	****	****	****
Profitability (Rs /MT)	****	****	****	****

The authority also notes the submissions regarding referencing DGCI&S data for imports made by various interested parties. The Authority recalls its observations in the disclosure statement and has evaluated the maximum demand and maximum imports on the basis of the data available from the responses of the cooperating exporters, DGCI&S and the secondary source viz. PPR.

The Authority notes that it has been submitted by M/s KKPC that various injury parameters and cost of production of M/s Apar Industries Ltd should be examined in detail and injury and causal link be appropriately considered. Also various interested parties have raised the issues pertaining to examination of injury to Domestic Industry. The Authority notes that M/s Apar Industries Limited primarily produces NBR at its Walia plant at Gujarat. During the period of investigation, the company has produced NBR to an extent of about 95% of the total capacity utilised during the period of investigation. The company maintains separate books of accounts for Walia plant, duly audited. Thus the basis for determination of NIP is authentic and the costs and expenses related to NBR only have been considered for the purpose of determination of cost of production and thereby the non-injurious price. Also consistent with the practice, the Designated Authority has normated the various elements of costs so as not to grant the Domestic Industry any undue benefit or protection which might accrue to them on account of their inefficiencies. Hence the arguments of various interested parties regarding profitability and cross loading of expenses on different related products by the company being a multi-product company are duly taken care of by the Authority during onsite verification of the Domestic Industry.

The above economic parameters in the Table indicates that demand of subject goods has been around 10000MT to 12000 MT and has therefore not been a factor for cause of injury. The indicators on production and capacity utilisation for Domestic Industry show upward trend. Though the share of Domestic Industry in total demand have increased, the imports from the subject countries, especially Korea RP continue to be significant as imports from subject countries as % of demand continues to be significant despite anti dumping duty. This coupled with price undercutting is causing material injury to the Domestic Industry and would also lead to recurrence of injury.

The Authority notes that the net sales realisation of the Domestic Industry during the period of investigation is below the non-injurious price. The dumped imports from the subject countries evidence price undercutting as the landed value of such dumped imports are below the non-injurious price and in case of M/s KKPC even after imposition of the existing anti dumping duties, there is still price undercutting when landed values with anti dumping duty are compared with the non-injurious price. The argument of M/s



KKPC that the effect of customs duties and SADD should be appropriately considered are also duly considered by the Authority. The Authority notes that NBR is an industrial product and as per the consistent practice it is the ex-factory non-injurious price which is compared with the landed value as defined in this determination below. In case the customs duties have fallen during the present period of investigation for the subject goods, the raw material utilised for manufacture of the subject goods by the Domestic Industry have also attracted lower duties and therefore the non-injurious price has also been affected by the fall in customs duties. Thus the practice of comparing non-injurious price during the period of investigation with the landed value in POI is consistent and appropriate. The argument of M/s KKPC regarding granting the adjustments on the level of trade as the exports of M/s KKPC are made to the wholesalers and not to the end users is also not appropriate since if the wholesalers in the distribution chain benefit by the dumped imports, ultimately the supplies are only made to the retail level actual users. It therefore has an adverse impact on the sales of the Domestic Industry and thus ex-factory comparison as indicated above is appropriate. As indicated above, the comparison for the evaluation is appropriate at the ex-factory level which the Authority has been doing consistently. The Authority has therefore followed the same approach. The landed value of dumped goods from M/s KKPC even with addition of existing anti dumping duty is lower than NIP. The Authority in regard to submissions on high Butadiene cost notes that the Hon'ble CEGAT in its judgement dated 4.2.1997 in case of NBR from Japan has upheld the methodology on NIP determination at optimum level and have taken cognizance of the situational conditions of the Domestic Industry. The various economic factors viz price undercutting by dumped imports, net sales realisation lower than NIP and erosion of profitability imply that if anti dumping duties on subject goods from subject countries are withdrawn, the dumping and injury will continue and recur and will cause intensified material injury to Domestic Industry.

## **6. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES**

The Authority notes that the submissions have been made regarding demand and supply mismatch of the subject goods and the effect on export competitiveness as well. The Authority in this regard holds that the purpose of anti dumping duty duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

The Authority also recognises that though the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products, however, fair competition in the Indian market will not be reduced by these anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by the dumping practices and would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice of the subject goods to the consumers. Imposition of anti-dumping measures would also not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers/users.

The Authority notes that it has been mentioned by M/s KKPC that the disclosure should have been sent under the signature of Designated Authority citing various case laws on the matter. Also the exporter has submitted that the public hearing conducted by the Designated Authority was not appropriately conducted as per Rules and has cited the WTO articles and case laws pertaining to the same. The Authority in this regard notes Rule regarding that the oral submissions to be made during the investigation and the issuance of the disclosure under Rule 16. The Authority notes that the oral submissions presented during the hearing are only be considered if they are subsequently produced in writing. Therefore an essential requirement is that the oral submissions should be backed by the written submissions so that this could be appropriately considered during the course of investigation. The Authority has followed this rule position and its consistent practice in holding such a hearing and inviting various interested parties to make their submissions. Further the Authority notes that all submissions made by M/s KKPC were duly verified on site by the verification team and all relevant submissions have been appropriately considered and addressed. As regards the disclosure, the Authority holds that the disclosure pertains to the information on the essential facts which form the basis for the decision but is not a decision. The Authority has followed the consistent practice of disclosing such a information under the signature of the investigation officer on behalf of Designated Authority and therefore holds that the practice adopted under Rule 16 of the Anti Dumping Rules has been adhered to in this case as well.

#### **7. LANDED VALUE**

The landed value has been determined for the subject goods after adding on weighted average CIF export price, the applicable level of custom duties (except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A) and one percent towards landing charges

#### **D. CONCLUSIONS:**

##### **It is seen, after considering the foregoing that:**

- (a) The subject goods originating in or exported from the subject countries have been exported to India below its normal value;.
- (b) The various economic indicators and injury parameters in particular price undercutting by dumped imports imply that the cessation of anti dumping duty on the subject goods from the subject countries will lead to continuance or recurrence of dumping and injury and therefore the Authority recommends continuation of anti dumping duty on the subject goods as indicated below. In this regard the Authority also notes that on NBR imports from Japan in the Sunset Review implemented by Customs vide Notification dated 21.12.2001 a variable duty has been levied, the Authority considers it appropriate to levy anti dumping duty in variable form in this investigation as well. The authority recalls that levy in dollar terms has been upheld by the Hon'ble CEGAT
- (c) In view of the above, it is recommended that the amount of Anti Dumping Duty in variable form equal to the difference between the amount as indicated in Column 3 of the Table below and the landed value in \$/MT be imposed, by the Central Government on all grades of Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) originating in or exported from Korea RP and Germany falling under Chapter 40 of the Customs Tariff

1	2	3
SI No.	Name of the exporter/producer	Amount (\$/MT)
1	Korea RP	
	1 Korea Kumho Petrochemical Co. Ltd. (KKPC)	1692.12
	2. Hyundai Petrochemical Co. Ltd	1908.28
	3 All other exporter/producers	1902.28
2	Germany	
	1 Bayer AG	2314.8
	2. All other exporters/ producers	2314.8

- (d) An appeal against this order shall lie to the Customs, Excise, Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act supra.

L.V. SAPTHARISHI, Designated Authority & Addl. Secy.

